चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 01 अगस्त- 07 अगस्त 2016 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

अखिलेश यादव से पूछना चाहिए

मुसलमानों का मज़ाक़ क्यों...

प्रभात रंजन दीन

समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का मजाक बना कर रख दिया है. साढ़े चार साल के शासनकाल में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया. मुसलमानों को फर्जी बयानों, झूठे विज्ञापनों और खोखले प्रलोभनों से बहलाया जाता रहा. सत्ता संभालने के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुसलमानों के कल्याण के लिए जिन योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा की, वे सब इन साढ़े चार वर्षों में बेमानी साबित हुईं. जिस घोषणा पत्र के बूते समाजवादी पार्टी चुनाव जीत कर आई, उसमें अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो वायदे किए गए थे, उसके कार्यान्वयन पर सरकार ने कोई ध्यान ही नहीं दिया. सरकार का यह रवैया देखते हुए नौकरशाही ने भी मुसलमानों के साथ ऐसा बर्ताव किया कि जानकर आपको हंसी भी आएगी, दुख भी होगा और गुस्सा भी आएगा. अल्पसंख्यकों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार और नौकरशाही ने फूहड़ और अराजक व्यवहार दिखाया है. स्वाभाविक है कि यह सब लिखने के लिए 'चौथी दुनिया' के पास ठोस प्रामाणिक आधार होगा. यह आधार खबर के विस्तार में परत दर परत खुलता जाएगा और समाजवादी सरकार के अल्पसंख्यक-प्रेम की कलई भी छिलका दर छिलका खुलती जाएगी.

मुसलमानों के साथ किए गए फूहड़ मजाक की पहली परत यह है... अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बाकायदा कैबिनेट के जरिए जिन योजनाओं को 'त्वरित गति से' लागू करने का फैसला 14 अगस्त 2013 को लेती है, उन योजनाओं के कार्यान्वयन पर पहली बैठक तीन साल बाद 11 मई 2016 को होती है. उत्तर प्रदेश सरकार के 30 विभिन्न विभागों की तकरीबन सौ योजनाओं में अल्पसंख्यकों के कल्याण का क्या काम हुआ और इसे कैसे कार्यान्वित करना है, इस विषद विषय को तत्कालीन मुख्य सचिव आलोक रंजन ने 30 मिनट में निपटा डाला. सरकार के फैसले के तीन साल बाद बुलाई गई बैठक सवा छह बजे शाम को शुरू हुई और पौने सात बजे समाप्त भी हो गई. इस बैठक में सम्बद्ध विभागों के अधिकांश अधिकारी शरीक नहीं हुए, लिहाजा उसे आधे घंटे में समाप्त हो ही जाना था. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव,

अल्पसंख्यक-कल्याण की योजनाओं के अमल पर उजागर हुए मज़ाक़िया तथ्य

अखिलेश सरकार के फैसले के तीन साल बाद मुख्य सचिव ने बुलाई पहली बैठक

तीन साल बाद हुई बैठक महज़ आधे घंटे में समाप्त, अधिकांश अफसर नदारद रहे

अल्पसंख्यक-कल्याण की योजनाओं पर अमल तक़रीबन शून्य, आधिकारिक पुष्टि

मंत्रिमंडल के निर्णय और मुख्य सचिव की बैठक को प्रदेश की नौकरशाही कितनी गंभीरता से लेती है, इससे जाहिर हो जाता है. अल्पसंख्यक-कल्याण की घोषित योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक महीने की 12 तारीख को सरकार के समक्ष पेश होनी थी. लेकिन किसी भी विभाग ने आज तक कोई प्रगति रिपोर्ट नहीं दी और न सरकार को ही इस तरफ झांकने की फुरसत मिली. सरकार ने जब फैसला लिया था, उस समय प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी थे. तीन साल बाद जब पहली बैठक हुई तब मुख्य सचिव के पद पर आलोक रंजन विराजमान थे.

सच्चर कमेटी और रंगनाथ कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की जरूरतों पर रुदालियां गाती रहने वाली समाजवादी पार्टी को सत्ता संभालने के सवा साल बाद अल्पसंख्यकों के कल्याण की सुध आई थी. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास के लिए 30 सरकारी विभागों की 85 योजनाओं के जरिए लाभान्वित करने का फैसला किया था. सरकार ने मुख्यमंत्री की सियासी तकरीरों से सुसज्जित सात पेज की प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की थी, जिसमें मुसलमानों की गरीबी और बदहाली पर चिंता जताने, सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर प्रतिबद्धता जताने और अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में लाने का जतन करने जैसे वाक्य सोच-सोच कर पिरोए गए थे. इन योजनाओं को लागू करने और उस पर निगरानी के लिए प्रदेश में मुख्य सचिव और जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियां गठित करने का फैसला हुआ था. इन समितियों में अल्पसंख्यक समुदाय के दो-दो सदस्यों को नामित करने का प्रावधान भी किया गया था. प्रस्तावित योजना में पारदर्शिता बरतने के लिए हिंदी और उर्दू में वेबसाइट शुरू करने और धूमधाम से इसका प्रचार करने का निर्णय लिया गया था. धूमधाम से प्रचार तो खूब हुआ और उस पर करोड़ों रुपये फूंक डाले गए. लेकिन अन्य कोई काम नहीं हुआ. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पहली बैठक ही तीन साल बाद हुई तो दूसरे काम के बारे में सोचा जा सकता है. अल्पसंख्यक कल्याण के लिए प्रस्तावित योजनाओं की वेबसाइट शुरू करने की बात तो छोड़ दें, उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग क्लिक करें तो समाजवादी सरकार का अल्पसंख्यक-प्रेम सामने दिख जाएगा. क्लिक करने पर आपके दिमाग से क्लिक-क्लिक की आवाज आने लगेगी, लेकिन वेबसाइट नहीं खुलेगी. दो दिन लगातार प्रयास करने के बाद वेबसाइट खुली तो अल्पसंख्यक कल्याण वाले खाते में जो सबसे अद्यतन (करेंट) शासनादेश है, वह 22 नवम्बर 2013 का है. स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिए उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं. ध्यान रहे कि सरकार के 30 विभागों की विभिन्न (शेष पृष्ठ 2 पर)

कश्मीर की सरकार दिल्ली से नहीं चलनी चाहिए

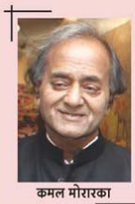

कमल मोरारका

कश्मीर को लेकर देश में हंगामा मचा है. हमें यह याद रखना चाहिए कि कश्मीर के तत्कालीन निर्विवादित नेता शेख़ अब्दुल्ला की वजह से कश्मीर का झुकाव भारत के प्रति हुआ. महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान जाना सहर्ष स्वीकार कर सकते थे. लेकिन शेख़ अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं, हम सभ्य राज्य हैं और हमें धर्मनिरपेक्ष भारत के साथ रहना चाहिए. इसके बाद नेहरू पाकिस्तान की शिकायत लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंच गए. संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि तीन महीने के भीतर जनमत संग्रह होना चाहिए. हालांकि, यह हमारे ख़िलाफ़ नहीं गया, क्योंकि यूएन के प्रस्ताव में पाकिस्तान को सीमा से अपने सैनिकों को हटाना था, उसने ऐसा नहीं किया. इसलिए जनमत संग्रह वाली बात हमारे ख़िलाफ़ नहीं गई. बेशक, तब से आज तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है, भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हो चुके हैं, शिमला समझौता हो चुका है. लेकिन अब कश्मीर में गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं. 1983 तक समस्या इतनी गंभीर नहीं थी, क्योंकि तब शेख़ अब्दुल्ला को वहां नेतृत्व देने के लिए पुनर्स्थापित किया जा चुका था. 1982 में उनकी मौत हुई. कश्मीर में चुनाव हुए. उनके बेटे फ़ारूक़ अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव लड़ा. कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सहमति नहीं बनी और पहली बार कश्मीर में एक सत्तारूढ़ पार्टी, दिल्ली के विरोध के बाद भी फिर से सत्ता में आ गई. मैं समझता हूं कि कश्मीर में शांति स्थापित करने का यह सुनहरा मौक़ा था, लेकिन दुर्भाग्य से फ़ारूक़ सरकार दल-बदल की वजह से अस्थिर कर दी गई और उनके बहनोई जीएम शाह को मुख्यमंत्री बना दिया गया. जीएम शाह न तो धर्मनिरपेक्ष थे और न ही वे शांति चाहते थे. कश्मीर में पहला सांप्रदायिक दंगा शाह के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ था.

> **जब कश्मीरियों ने 1983 में फ़ारूक़ अब्दुल्ला को अपना नेता चुना, तो केंद्र ने पिछले दरवाज़े से उस सरकार को अस्थिर कर दिया. आपने संदेश दिया कि जब तक दिल्ली की पसंद की सरकार नहीं होगी, तब तक आपको शासन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.**

मुद्दा यह है कि कश्मीर के लोगों को कैसे यह विश्वास दिलाया जाए कि हम आपकी स्वायत्तता का सम्मान करेंगे, आपकी पसंद का सम्मान करेंगे. एक बार जब कश्मीरियों ने 1983 में फ़ारूक़ अब्दुल्ला को अपना नेता चुना, तो केंद्र ने पिछले दरवाज़े से उस सरकार को अस्थिर कर दिया. आपने संदेश दिया कि जब तक दिल्ली की पसंद की सरकार नहीं होगी, तब तक आपको शासन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ऐसा संदेश देश के किसी भी भाग के लिए ग़लत होगा, कश्मीर के लिए तो और अधिक ग़लत होगा. अब हालात ये हैं कि कश्मीर में जब एक छात्र नेता, जिसके पास बहुत ज्यादा समर्थन नहीं था, मारा गया तो उसके जनाज़े में तक़रीबन 5 लाख लोग शरीक हुए. मैं नहीं जानता कि महबूबा मुफ्ती क्या सोच रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाजपा-पीडीपी सरकार अब वास्तव में इस मुद्दे को संभाल सकती है. आपको कश्मीरियों को ख़ुद की सरकार चुनने का मौक़ा देना होगा. अब समय आ गया है कि आपको कश्मीर में 1953 से पहले की स्थिति बहाल करनी होगी, अगर आप कश्मीर की जनता को अपने साथ रखना चाहते हैं. धारा 370 के तहत हमने उन्हें जो भी गारंटी दी है, उसका हमें पूरा-पूरा पालन करना होगा, उसे तब तक मानना होगा, जब तक वे ख़ुद इसे ख़त्म करने की बात नहीं कहते.

अब यह काम कैसे किया जाए? कश्मीर में भाजपा-पीडीपी की बहुमत की सरकार है. यदि वाक़ई वे इस मसले को हल कर लेते हैं तो यह बहुत अच्छा है. अब समय आ गया है जब आप कश्मीर विधानसभा का चुनाव कांग्रेस और

भाजपा की भागीदारी के बिना होने दें. इन दोनों पार्टियों को कश्मीर से बाहर रखना चाहिए. स्थानीय पार्टी चाहे, वह नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी या अन्य पार्टी या कोई कश्मीरी व्यक्ति, चुनाव लड़े और निर्वाचित हो. यहां तक कि अगर एक अलगाववादी पार्टी भी चुनाव जीतती है तो इसमें कोई समस्या नहीं है. डीएमके एक अलगाववादी पार्टी थी, जो अलग झंडा, अलग मद्रास, तमिलनाडु चाहती थी. एक बार जब वे चुन लिए गए तो भारतीय संविधान के अनुसार कार्य करने लगे. अब दशकों से वहां द्रमुक या अन्नाद्रमुक की सरकार बन रही है. कश्मीर में भी दो स्थानीय पार्टी की व्यवस्था चल सकती है. वे स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे. मुझे लगता है कि समय आ गया है कि एक सर्वदलीय बैठक कर कश्मीर मुद्दे का हल तलाशा जाए. एक दो मंत्री पद के लिए आपको अपने क्षुद्र स्वार्थ दूर रखने होंगे. आदर्श रूप से भाजपा को मुफ्ती सरकार का बाहर से समर्थन करना चाहिए था. सरकार में भागीदारी कर उसने अच्छा नहीं किया है. उनका कहना है कि जम्मू के लोगों की भावनाओं को भी देखना है. लेकिन ये सब सत्ता के लिए बहानेबाज़ी है. सरकार या मंत्री पद का कोई मतलब नहीं है, देश महत्वपूर्ण है. क्या हम कश्मीर की ज़मीन चाहते हैं? ज़मीन सुरक्षित है क्योंकि वहां उसकी रक्षा के लिए सेना है. पाकिस्तान चाहे जितना भी शोर मचा ले, वो हमसे कश्मीर नहीं छीन सकता.

कश्मीरी लोगों का दिल जीतने के लिए हमें उनके मन में विश्वास पैदा करना होगा. संयोग से, कश्मीर का इस्लाम दुनिया के बाकी हिस्सों के इस्लाम से अलग सूफ़ी इस्लाम है. आतंकी ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए चरार-ए-शरीफ़ को विस्फोट से उड़ा दिया. मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को दलीय राजनीति से ऊपर उठकर एक कुशल राजनेता (स्टेट्समैन) की तरह सोचना चाहिए. ऐसी स्थिति पैदा करें कि कश्मीरी स्वेच्छा से भारत के साथ एकीकृत होने की चाहत दिखाएं.

मैं सरकार को चेतावनी देना चाहूंगा. विकास पैकेज, रोज़गार सृजन और उद्योग लगाने की बात हो रही है, ये सब जनता की बुद्धिमता का अपमान है. आज का युवा बेशक यह सब चाहता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान की क़ीमत पर नहीं. उन्हें यहां महसूस होना चाहिए कि कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू से शासित हो रहा है न कि दिल्ली से. जब तक हम ऐसी परिस्थितियों का निर्माण नहीं करते हैं, तब तक मुझे डर है कि कश्मीर में समस्या और बढ़ेगी, जैसा 1983 के बाद वहां आतंकवाद ने अपना सर उठाया था. सामान्य स्थिति बहाल होने से पहले तक आतंकवाद वहां एक बड़ी समस्या थी. अब, कश्मीर में नई पीढ़ी आ गई है. हमें एक बार फिर वही पुरानी कहानी नहीं दोहरानी चाहिए. ■

मुसलमानों का मज़ाक़ क्यों

पृष्ठ 1 का शेष

योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय को लाभान्वित करने के कार्यक्रम की अलग से वेबसाइट बनाने की जो बात कही गई थी, वह भी कार्यान्वित नहीं हुई.

बहरहाल, सरकार के फैसले के तीन साल बाद मुख्य सचिव की बैठक बुलाई जाती है, उस बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति नगण्य रहती है, उस बैठक में मुख्य सचिव आलोक रंजन अफसरों से क्या कहते हैं उसे आप भी सुनें. मुख्य सचिव कहते हैं, 'यह योजना राज्य सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है और विकास की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है. इसलिए इस योजना में किसी भी प्रकार की शिथिलता को क्षमा नहीं किया जाएगा.' मुख्य सचिव की हिदायतों की इन पंक्तियों को पढ़ कर आपको भी आक्रोश मिश्रित हंसी आई होगी और अल्पसंख्यकों के साथ सरकार कैसा मजाक कर रही है, यह स्पष्ट हुआ होगा. अल्पसंख्यक-कल्याण की योजना के कार्यान्वयन को लेकर जब सरकार से सूचना के अधिकार के तहत जन-पूछताछ तेज हुई तब सरकार को योजना की याद आई और तब आनन-फानन में बैठक बुलाई गई. ऐसी विलंबित बैठक में शिथिलता को लेकर दी गई हिदायतें वीभत्स मजाक ही तो हैं. अखिलेश सरकार ने वर्ष 2013 में निर्णय लिया, मुख्य सचिव ने इस पर 2016 में पहली बैठक बुलाई, कार्यान्वयन तकरीबन शून्य पाया गया, योजना में सरकारी विभागों की गैर-दिलचस्पी की आधिकारिक पुष्टि हुई, फिर भी अफसरों को 'इस महत्वपूर्ण योजना को गंभीरता से लेने और लक्ष्य को शत प्रतिशत पूरा किए जाने के निर्देश के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त कर दी गई.' यह मुख्य सचिव की बैठक से सम्बन्धित सरकारी दस्तावेज की आधिकारिक औपचारिक (हास्यास्पद) पंक्तियां हैं, जिन्हें यहां हूबहू दोहराया गया है. ताकि इन लाइनों का मर्म और नेताओं का धर्म साफ-साफ समझ में आए. अब चुनाव सामने है, तो अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाओं का सारा अधूरा पड़ा काम कब होगा? इन्हीं सवालों के साथ मुस्लिम 'वोट-बैंक' रूबरू है.

अल्पसंख्यक-कल्याण की योजना पर वर्ष 2014-15 में क्या हुआ? सरकार इस सवाल पर चुप है और सम्बन्धित आधिकारिक दस्तावेज भी इस अवधि की कोई चर्चा नहीं करते. 2015-16 के दरम्यान 28 सरकारी विभागों की 65 योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया गया, इसकी कोई सूचना सरकार को नहीं है. कृषि विभाग की सात योजनाओं में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए क्या काम हुए, इसकी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है. वही हाल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन, पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला कल्याण विभाग, दुग्ध विकास, उद्यान, लघु उद्योग, खादी ग्रामोद्योग समेत दर्जनों अन्य विभागों का है.

मुख्यमंत्री का दफ्तर भी नहीं दे पाया जवाब

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने क्या किया, इस सवाल का मुख्यमंत्री सचिवालय के पास भी कोई जवाब नहीं था. आरटीआई ऐक्टिविस्ट सलीम बेग ने सूचना के अधिकार के तहत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इस बारे में सूचना मांगी थी. लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय उन सवालों का जवाब नहीं दे पाया. तुरंत टोपी ट्रांसफर की गई. मुख्यमंत्री सचिवालय ने उन सवालों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कंधे पर डाल दिया. लिखा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ही इन सवालों का जवाब देने में सक्षम है. उधर, सवाल देख कर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सांप सूंघ गया. जवाब उनके पास भी नहीं था. लंबे अर्से तक फाइल वहीं दबी रही. जवाब हासिल करने के लिए जब दूसरी अपील दाखिल हुई और कानूनी घेरा बढ़ा तब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जवाब जुटाना शुरू किया. फिर तो 'पैंडोरा-बॉक्स' खुल गया और सरकार की अजीबोगरीब हरकतें उजागर होती चली गईं. इससे अल्पसंख्यकों का इतना कल्याण जरूर हुआ कि उजागर हुए आधिकारिक दस्तावेजों ने अल्पसंख्यकों की आंखें जरूर खोल दीं. चुनाव का समय है, लिहाजा, प्रदेश के 19 फीसदी अल्पसंख्यक दरवाजे पर बहुत जल्दी नतमस्तक होने वाले सपा नेताओं से ये सवाल जरूर पूछेंगे और हिसाब-किताब बराबर करेंगे. उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 21 जिलों में मुस्लिम मत 19 प्रतिशत है. सर्वाधिक संख्या रामपुर में 50.57 प्रतिशत से ऊपर है. इसके बाद बिजनौर, ज्योतिबा फुले नगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व बलरामपुर में यह प्रतिशत 37 से 47 तक है. मेरठ, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बागपत, गाजियाबाद और लखनऊ में भी मुस्लिम मतदाता खासी तादाद में हैं. अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को लागू करने में फेल होने की खबरों के उजागर होने से समाजवादी पार्टी में गहरी चिंता है. सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव की सार्वजनिक फटकार की बेचैनी कहीं और भी है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलायम सिंह यह कह चुके हैं कि राज्य सरकार को अल्पसंख्यकों से जुड़ी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान ढूंढना चाहिए. अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनाओं के लागू नहीं होने पर भी मुलायम कई बार नाराजगी जाहिर कर चुके हैं. ■

सपा सरकार में उठा उर्दू का जनाज़ा

अखिलेश सरकार ने उर्दू अरबी और फारसी भाषाओं की जड़ें उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं होने दीं. अल्पसंख्यक विभाग की इस्लामिक शोध से जुड़ी संस्था की जमीन और इमारत आजम खान की निजी संस्था को कौड़ियों के मोल लीज पर दे दी गई लेकिन लखनऊ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का कबाड़ा कर दिया गया. उत्तर प्रदेश में दूसरी राजभाषा के रूप में स्थापित उर्दू को विकसित करने के उद्देश्य से लखनऊ में उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, लेकिन यहां उन्हीं भाषाओं की प्राथमिकता समाप्त कर दी गई. अजीबोगरीब पहलू यह है कि उर्दू अरबी और फारसी के अकादमिक विकास के लिए जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, उसके सभी शीर्ष पदों पर बैठे लोग उर्दू अरबी या फारसी भाषाओं की शैक्षिक योग्यता नहीं रखते. जामिया मिलिया के प्रोफेसर खान मसूद अहमद ने 2014 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी-फारसी विश्वविद्यालय का वीसी बनते ही उर्दू भाषा की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी. वीसी और रजिस्ट्रार ने तब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उर्दू अरबी या फारसी भाषा वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी और उन विषयों के अंक रिजल्ट के पूर्णांक (एग्रीगेट) में नहीं जोड़े जाएंगे. इस तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का औचित्य ही समाप्त कर दिया गया.

पांच साल का दंश अल्पसंख्यकों का अंश

यूनानी चिकित्सा पद्धति के प्रचार-प्रसार पर सरकार ने एक वर्ष में कितना खर्च किया? इस सवाल पर सरकार कहती है 50 हजार रुपये. सरकार का यह जवाब ही सरकार की मंशा उजागर करती है. पूरे सालभर में यूनानी चिकित्सा पद्धति के प्रचार-प्रसार पर महज 50 हजार रुपये का खर्च आश्चर्यजनक है. यूनानी चिकित्सा पद्धति की पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी और उर्दू भाषा है. मुसलमानों का यूनानी चिकित्सा पद्धति से खास लगाव भी रहा है. प्रदेश में मात्र दो राजकीय यूनानी

(शेष पृष्ठ 3 पर)

अधूरी ही रह गई अल्पसंख्यक-कल्याण की योजना

उत्तर प्रदेश के 30 सरकारी विभागों की विभिन्न योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय को लाभान्वित करने की योजना बनाई गई थी:-

विभाग का नाम	योजनाएं/कार्यक्रम
कृषि	'आइसोपॉम' (इंटेग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयलसीड्स, पल्सेज़, ऑयल पाल्म एंड मेज़) योजना
	प्रमाणित बीजों पर अनुदान
	संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देना
	संकर बीजों के प्रोत्साहन की योजना
	विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
	मृदा में सूक्ष्म तत्व को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम का वितरण
	भूमि सेना योजना
गन्ना विकास	ग्रामीण मार्गों का निर्माण
	उन्नत गन्ना बीजों का वितरण
लघु सिंचाई	निःशुल्क बोरिंग
	गहरे नलकूप हेतु अनुदान
	बोरिंग/पंपिंग सेट हेतु अनुदान
उद्यान	सूक्ष्म सिंचाई
	राष्ट्रीय उद्यानीकरण मिशन
	पान की खेती
	ढाबा/फास्ट फुड/रेस्तरां हेतु प्रशिक्षण
	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना
	फल पट्टी योजना
	हरबल गार्डन योजना
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत संचालित कार्यक्रम
पशुपालन	पैरावेट स्कीम
	गाय एवं भैंस के कृत्रिम गर्भाधान और पशु प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना
	पशुपालकों की प्रशिक्षण योजना
मत्स्य विकास	मोबाइल फिश पार्लर योजना
कृषि विपणन	13वें वित्त आयोग के अंतर्गत मंडी शेड (एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब) का विकास
	हब में निर्मित दुकानों एवं चबूतरों का आवंटन
	मंडी परिषद निधि से निर्मित मंडी और उप मंडियों में दुकानों और चबूतरों का आवंटन
	मंडी परिषद निधि से संचालित जनेश्वर मिश्र ग्रामों का चयन
ग्राम्य विकास	स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना
	अंबेडकर विशेष रोजगार योजना
	ग्रामीण पेयजल योजनाएं
	हैंडपंप
	इंदिरा आवास योजना
	लोहिया ग्रामीण आवास योजना
पंचायती राज	पंचायत भवनों का निर्माण
	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान)
	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
	ए.एन.एम. सेंटर
	अरबन हेल्थ पोस्ट
लोक निर्माण	ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण
सिंचाई	डॉ. राम मनोहर लोहिया नलकूप योजना
ऊर्जा	निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण
लघु उद्योग	कारीगरों को विपणन हेतु सहायता
	कारीगरों के कौशल विकास के लिए डिजाइन वर्कशॉप
	महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना
खादी ग्रामोद्योग	मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना
	कौशल सुधार योजना
रेशम विकास	जागरूकता एवं प्रशिक्षण योजना
	कैटेलिटिक विकास योजनान्तर्गत बेनिफिशियरी इम्पावरमेंट प्रोग्राम तथा लाभार्थीपरक अनुदान सहाययित सूक्ष्म योजनाएं
	कैटेलिटिक विकास योजना (सी.डी.ई.)
पर्यटन	कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम
बेसिक शिक्षा	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में छात्राओं का नामांकन
माध्यमिक शिक्षा	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण
	माध्यमिक विद्यालयों में आई.सी.टी. कार्यक्रम
	असेवित न्याय पंचायत में कन्या विद्यालयों की स्थापना के लिए निजी संस्थानों को अनुदान
	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (नए विद्यालयों की स्थापना/उच्चीकरण, मॉडल स्कूलों की स्थापना/निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों का निर्माण)
उच्च शिक्षा	नए उच्च एवं माध्यमिक राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना/निर्माण
	वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण
	असेवित क्षेत्रों में निजी महाविद्यालयों की स्थापना
	36 मॉडल राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना
युवा कल्याण	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के तहत पी.ए.आई.सी.सी.ए. केंद्र की स्थापना
नगर विकास	शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति की योजनाएं
	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना
	नया सवेरा नगर विकास योजना
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन	स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना के तहत संचालित कार्यक्रम- कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम (ऋण/अनुदान), शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम (आवर्ती निधि), शहरी मजदूर कार्यक्रम
	आसरा योजना
	रिक्शा योजना
	शहरी स्लम में अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बुनियादी सेवाएं
पिछड़ा वर्ग कल्याण	बीमारी एवं पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान
	व्यावसायिक प्रशिक्षण
व्यावसायिक शिक्षा	असेवित विकास खंडों में आई.टी.आई. का निर्माण/स्थापना
	कौशल विकास मिशन
समाज कल्याण	रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना
विकलांग कल्याण	नेत्रहीन मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को भरण-पोषण हेतु अनुदान (विकलांग पेंशन)
	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण योजना
महिला कल्याण	निराश्रित महिलाओं के लिए भरण-पोषण अनुदान
दुग्ध विकास	कृषकों का प्रशिक्षण
	दुग्ध संघों/समितियों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्जीवीकरण का विस्तार एवं विस्तार योजना
	दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु तकनीकी निवेश योजना
	संघन मिनी डेरी परियोजना
	नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लिमेंट (एन.एम.पी.एस)
समग्र ग्राम विकास	डॉ. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 08 अंक 22
01 अगस्त- 07 अगस्त 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

मुसलमानों का मज़ाक़ क्यों

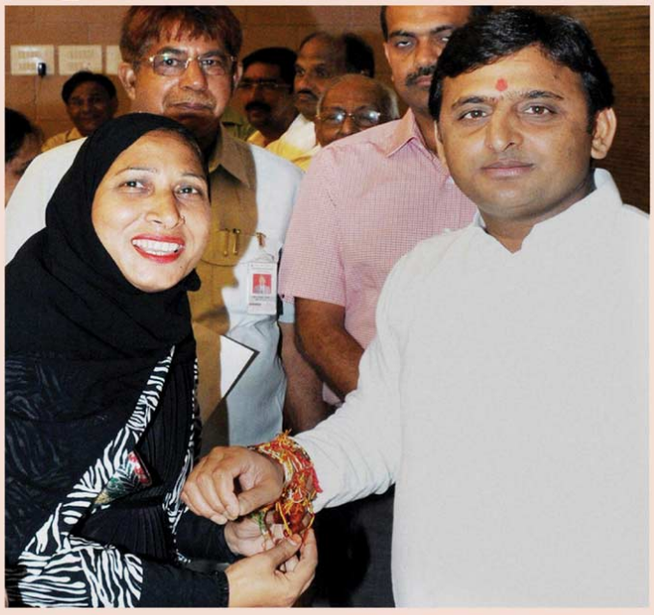

पृष्ठ 2 का शेष

मेडिकल कॉलेज लखनऊ और इलाहाबाद में स्थित है. प्रदेश के सात मंडल ऐसे हैं जहां एक भी सरकारी या गैर सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज नहीं है. यूनानी मेडिकल कॉलेजों में नर्स और फार्मासिस्ट के पद ही सृजित नहीं हैं. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाजसेवी सलीम बेग की जनहित याचिका लंबित है. जनहित याचिकाओं के दबाव में सरकार ने वर्ष 2015 में नर्स और फार्मासिस्ट का कोर्स शुरू तो किया मगर उससे उर्दू भाषा को बाहर कर दिया. जबकि यूनानी के डॉक्टर-हक़ीम उर्दू या अंग्रेजी में दवा की पर्ची लिखते हैं.

सलीम बेग कहते हैं कि यूनानी मेडिकल कॉलेज की बात तो छोड़िए, बरेली से मेरठ जिले के बीच एक भी सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित नहीं है जबकि इस दूरी में रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और बिजनौर जैसे जिले लगते हैं. इस क्षेत्र की विधानसभा की सर्वाधिक सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, लेकिन विडंबना है कि इस क्षेत्र में एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं, एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं, सब तरफ निजी विश्वविद्यालयों की भरमार लगी है और शिक्षा के एवज में आम लोगों को लूटा जा रहा है. समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में उत्तर प्रदेश में उर्दू की तरक्की के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों में प्राइमरी, मिडिल व हाई स्कूल स्तर के उर्दू मीडियम के सरकारी स्कूलों की स्थापना करने का वादा किया था. लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया गया. समाजवादी पार्टी ने चुनावी घोषणा-पत्र में अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित 14 वादे किए थे. लेकिन ये वादे अनदेखे ही रह गए. मुसलमानों को मुख्यधारा में लाने के सवाल पर सरकार का जवाब 'शून्य' लिखा आता है. सपा सरकार का अल्पसंख्यक-प्रेम इस तथ्य से भी जाहिर होता है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जारी धन का 25 फीसद भी खर्च नहीं हो पाता. वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के लिए 1024 करोड़ रुपये मंज़ूर किए. लेकिन सरकार इसका 25 प्रतिशत भी खर्च नहीं कर पाई.

यूपी पुलिस में पांच प्रतिशत मुसलमान

यह आधिकारिक तथ्य एक साल पहले का है, लेकिन वर्ष 2016 में इस आंकड़े में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है. लिहाजा, हम आधिकारिक तौर पर यह कह सकते हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व महज पांच फीसदी है. यह जानकारी भी सूचना के अधिकार के जरिए संजय शर्मा ने बाहर निकाली थी. आरटीआई के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी की सूचना मांगी गई थी. इसमें बताया गया कि 19 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले प्रदेश की पुलिस में मात्र पांच प्रतिशत मुसलमान काम करते हैं. आधिकारिक सूचना के मुताबिक यूपी पुलिस में कार्यरत तृतीय श्रेणी के कुल 192799 कर्मचारियों में से 10203 (5.29) प्रतिशत कर्मचारी मुसलमान हैं. इसी तरह यूपी पुलिस में कार्यरत चौथी श्रेणी के कुल 13489 कर्मचारियों में से 408 (3.02 प्रतिशत) कर्मचारी मुसलमान हैं. तीसरी और चौथी श्रेणी के पुलिस कर्मचारियों की संख्या मिला दें तो इनमें मुस्लिम कर्मचारियों की तादाद 10611 (5.14 फीसदी) आती है.

उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं और न हिंदी हिंदुओं की भाषा है

सूचना का अधिकार कानून का प्रचार करने वाला केंद्र सरकार का विज्ञापन उर्दू को मुसलमानों की भाषा बता रहा है. इस विज्ञापन से उत्तर प्रदेश का प्रसंग जुड़ा है, इसलिए यूपी के लोगों की इस विज्ञापन के प्रति भृकुटि तनी हुई है. यूपी के बुद्धिजीवियों का कहना है कि हिंदी से व्याकरण और शब्द लेने वाली उर्दू भारत में सम्पर्क भाषा रही है, लेकिन इसे समुदाय विशेष की भाषा बना दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है. केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से विजुअल मीडिया के लिए जारी इस विज्ञापन में गोवा, उत्तर प्रदेश, बंगाल और केरल की चार कहानियां कही गई हैं. इस विज्ञापन में पृष्ठ-स्वर (वॉयस-ओवर) हिंदी में है और सब-टाइटल्स अंग्रेजी में. इस विज्ञापन में राज्यों की मुख्य भाषा को आधार बनाकर संदेश देने की कोशिश की गई है. लेकिन जब गोवा और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक पात्रों पर फोकस आता है तो भाषाई पूर्वाग्रह अभिव्यक्त होता है. यह विज्ञापन स्थापित करता दिखता है कि सभी मुसलमान उर्दू बोलते हैं और सभी ईसाई अंग्रेजी बोलते हैं. विज्ञापन में उत्तर प्रदेश के मोहम्मद भाई का जिक्र करते हुए फारसी लिपि वाली उर्दू और गोवा के ब्रिगेंजा का संदर्भ सुनाते समय रोमन लिपि के साथ अंग्रेजी दिखाई जाती है. जबकि गोवा की आधिकारिक भाषा कोंकणी है और उत्तर प्रदेश की पहली आधिकारिक भाषा हिंदी और दूसरी भाषा उर्दू है. इस लिहाज से केंद्र सरकार का विज्ञापन भाषाई पूर्वाग्रह प्रदर्शित करने वाला विज्ञापन प्रतीत होता है.

लिपि के फर्क को छोड़ दें तो असलियत में हिंदी और उर्दू को खड़ी बोली का ही दो रूप माना जाता है. फिराक गोरखपुरी के नाम से देश-दुनिया में मशहूर शायर रघुपति सहाय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक थे, लेकिन उनका कहना था कि उर्दू में शब्दों के इस्तेमाल की विशेष शैली है. फिराक ने कहा है कि उर्दू जबान में अरबी-फारसी के 95 प्रतिशत शब्द वही हैं जिन्हें आम जनता बड़ी ही आसानी से बोलती और समझती है. आदमी, औरत, मर्द, बच्चा, कमजोर, जमीन, हवा, आसमान, गरम, सर्द, हालत, खराब, नेकी, बदी, दुश्मनी, दोस्ती, शर्म, दौलत, मकान, जिन्दगी, खुशी, आराम और किताब जैसे सैकड़ों अरबी-फारसी शब्द हैं जो हिंदी-उर्दू में बड़ी ही सहजता से बोले जाते हैं. अब तो नागरी लिपि का इस्तेमाल कर उर्दू में कविताएं, कहानियां और उपन्यास लिखे जा रहे हैं. इस चलन में राही मासूम रजा का नाम सबसे ऊपर है. ■

अल्पसंख्यक-प्रेमी सरकार इन संजीदा सवालों पर चुप क्यों है?

अखिलेश सरकार के चार साल पूरे होने पर सामाजिक संस्था रिहाई मंच ने सपा सरकार के समक्ष 41 सवाल रखे थे. सरकार की तरफ से उन सवालों का कोई जवाब सामने नहीं आया. लिहाजा, उन अनुत्तरित सवालों को फिर से हम सामने रख रहे हैं, कहीं चुनावी वर्ष में सरकार का कोई जवाब आ जाए.

1. निर्दोष मुस्लिम नौजवान जो आतंकवादी होने के नाम पर जेलों में बंद हैं, उन्हें चुनावी वादे के अनुसार रिहा क्यों नहीं किया गया?
2. अदालतों द्वारा बरी हुए बेगुनाहों को चुनावी वादे के अनुसार पुनर्वास और मुआवज़ा क्यों नहीं दिया गया?
3. साम्प्रदायिक हिंसा के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
4. मुसलमानों को 18 फ़ीसदी आरक्षण देने का वादा पूरा क्यों नहीं किया गया?
5. यूपी में साम्प्रदायिक हिंसा बिल लाने के लिए सरकार ने गंभीरता क्यों नहीं दिखाई?
6. सच्चर, रंगनाथ और कुंडू कमेटी की सिफ़ारिशों पर अमल क्यों नहीं किया गया?
7. मुज़फ्फरनगर सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ित परिवारों को इंसाफ़ दिलाने का वादा पूरा क्यों नहीं किया गया?
8. साम्प्रदायिक उन्माद और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ़ सरकार ने कानूनी कारवाई क्यों नहीं की?
9. राजनीतिक विरोधियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ़ भड़काऊ भाषण देकर अराजकता फैलाने वाले नेताओं पर कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती?
10. प्रदेश के राज्य अल्पसंख्यक आयोग में वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं होती, मामलों का कोई केस स्टडी नहीं होता. साम्प्रदायिक हिंसा से ग्रस्त मुज़फ़्फ़रनगर, दादरी तक में आयोग ने कोई दौरा नहीं. इसकी स्थापना के गाइडलाइन के अनुसार जनपदों में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पदों पर तैनात अधिकारी अल्पसंख्यक नहीं हैं. सरकार की इस उदासीनता की वजह क्या है?
11. प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के क्रम संख्या 14 व 15 में उल्लिखित है कि जो भी नौजवान दहशतगर्दी के तहत जेलों में बंद किए जाएंगे और अदालती प्रक्रिया से बरी होंगे, उन्हें पुनर्वास, मुआवज़ा और सरकारी नौकरी दी जाएगी. परन्तु इस पर अमल क्यों नहीं किया गया?
12. प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के मुताबिक आतंकवाद के नाम पर जेलों में बंद किए गए नौजवानों को फर्जी तरीके से फंसाने वाले अधिकारियों पर कारवाई उन्हीं धाराओं के तहत किए जाने की बात के बावजूद ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
13. मुसलमानों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए राजकीय सुरक्षा बलों में मुसलमानों की भर्ती का विशेष प्रावधान करने और कैम्प आयोजित करने का वादा पूरा क्यों नहीं किया गया?
14. सभी सरकारी कमीशनों, बोर्डों और कमेटियों में कम से कम एक अल्पसंख्यक प्रतिनिधि को सदस्य नियुक्त करने के सरकार के वादे का क्या हुआ?
15. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से अखिलेश सरकार ने 3 दिसंबर 2015 को सूचना अधिकार नियमावली 2015 से उर्दू भाषा में आवेदन/अपील देने पर पाबंदी क्यों लगाई?
16. बुनकरों की कर्ज़ माफी क्यों नहीं हुई?
17. किसानों की तरह गरीब बुनकरों को मुफ्त बिजली देने के वादे का क्या हुआ?
18. जिन औद्योगिक क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की बहुलता है, जैसे हथकरघा, हस्तकला, हैंडलूम, कालीन उद्योग, चूड़ी, ताला, जरी, जरदोजी, बीड़ी, कैंची उद्योग उन्हें राज्य द्वारा सहायता देकर प्रोत्साहित करने, कस्बों पर बिजली के बकाया बिलों पर लगने वाले ब्याज को माफ़ कर बुनकरों को राहत देने, छोटे और कुटीर उद्योगों में कुशल कारीगरों की कमी को पूरा करने के लिए प्रत्येक विकास खंड स्तर पर एक-एक आईटीआई की स्थापना करने का वादा पूरा क्यों नहीं हुआ?
19. यूपी के अल्पसंख्यक बहुल जिलों में संचालित मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान के तहत संचालित अधिकांश योजनाएं अपूर्ण क्यों हैं?
20. 20 अगस्त 2013 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय को उनका वाजिब हक़ दिलाने के लिए अल्पसंख्यकों को 30 विभिन्न विभागों में संचालित 85 योजनाओं में 20 प्रतिशत मात्राकृत लाभान्वित किए जाने का जो वादा किया था, उसे क्यों नहीं पूरा किया गया?
21. 25 अक्टूबर 2013 की घोषणा के अनुसार स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना के अन्तर्गत मुस्लिमों को 20 प्रतिशत लाभान्वित किया जाना था, जिसमें से स्वर्ण जयंती शहरी योजना अंतर्गत 6 उपयोजनाएं संचालित तो हुई लेकिन 31 मार्च 2014 को समाप्त कर दी गईं. इस मद के लिए जो पैसा था वह कहां खर्च हुआ?
22. उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा मानने के बावजूद अखिलेश सरकार के कार्यकाल में सरकारी कामकाज में महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों, सरकारी आदेशों समेत गज़ट का अनुवाद उर्दू भाषा में क्यों नहीं होता?
23. ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ की प्रथम परिनियमावली में उर्दू/अरबी/फारसी के अंक अन्य विषयों की तरह अंक-पत्र में न जोड़े जाने के निर्णय से उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के मक़सद को ही ख़त्म कर दिया गया. ऐसा क्यों किया गया?
24. ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ की प्रथम परिनियमावली में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति में उर्दू की अनिवार्यता को क्यों समाप्त कर दिया गया?
25. ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में एक भी नई फैकल्टी क्यों नहीं खोली गई?
26. ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ से मदरसों को जोड़ने के बजाए उसे मदरसों से दूर क्यों किया गया?
27. ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर, ओएसडी, फाइनेंसर कोई भी उर्दू भाषा की डिग्री प्राप्त क्यों नहीं है?
28. ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ की प्रथम परिनियमावली उर्दू भाषा में क्यों नहीं?
29. रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव आईएएस उर्दू रटडी सेंटर में मात्र 50 सीट जबकि प्रदेश में 75 जिले हैं. पढ़ाई का माध्यम उर्दू भाषा नहीं और कोई पद स्थाई नहीं, आखिर ऐसा क्यों?
30. उर्दू की प्रोन्नति के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों में प्राइमरी, मिडिल व हाई स्कूल स्तर पर सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों की स्थापना क्यों नहीं की गई?
31. अखिलेश सरकार के कार्यकाल में यूपी में एक भी यूनानी मेडिकल कालेज की स्थापना क्यों नहीं की गई?
32. यूपी के किसी भी यूनानी चिकित्सालय में नर्स और फार्मासिस्ट की नियमित नियुक्ति क्यों नहीं?
33. यूनानी चिकित्सा पद्धति जिसका कोर्स उर्दू भाषा में है, उसके नर्स और फार्मासिस्ट के कोर्स से उर्दू को क्यों बाहर किया गया?
34. यूनानी चिकित्सा पद्धति की 2008 से आज तक कोई भी नियमावली नहीं बनी व स्थाई निदेशक क्यों नहीं नियुक्त हुआ?
35. मुसलमानों के वह शैक्षिक संस्थान जो विश्वविद्यालय की शर्तों पर पूरा उतरते हैं, उन्हें कानून के तहत यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का वादा पूरा क्यों नहीं किया गया?
36. अखिलेश सरकार ने आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से अधिक पिछड़ा मानते हुए दलितों की तरह दलित मुस्लिमों को जनसंख्या के आधार पर अलग से आरक्षण क्यों नहीं दिया?
37. सपा सरकार द्वारा बनाए गए मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की सभी कानूनी बाधाएं समाप्त करने की बात तो की गई थी, लेकिन क्या अच्छा होता कि इस विश्वविद्यालय को सरकारी विश्वविद्यालय के रूप में बनाया गया होता, क्योंकि यह विश्वविद्यालय भी डोनेशन की बुनियाद पर ही प्रवेश देता है, जिससे गरीब जनता को सीधा लाभ नहीं पहुंच रहा है. उक्त क्षेत्र में प्राइवेट कई विश्वविद्यालय मौजूद हैं, जबकि बरेली से लेकर मेरठ तक 200 किमी के परिक्षेत्र में एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है. सरकार ने उक्त क्षेत्र में कोई सरकारी विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनवाया जिससे जनता को सीधा लाभ पहुंचता?
38. मुस्लिम बहुल जिलों में नए सरकारी शैक्षिक संस्थानों की स्थापना क्यों नहीं की गई?
39. क़ब्रिस्तानों की भूमि पर अवैध क़ब्ज़े को रोकने व भूमि की सुरक्षा के लिए चारदीवारी के निर्माण पर कार्य क्यों नहीं किया गया?
40. दरगाहों के संरक्षण व विकास हेतु दरगाह ऐक्ट का वादा क्यों पूरा नहीं किया गया और स्पेशल पैकेज के वादे का क्या हुआ?
41. वक़्फ़ डाटा कम्प्यूटरीकृत स्कीम के तहत आज तक वक़्फ़ के सारे डाटा कम्प्यूटरीकृत क्यों नहीं किए गए?

यूपी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट काफी प्रयास के बावजूद नहीं खुली

अल्पसंख्यक कल्याण का सच : नवंबर 2013 के बाद कोई शासनादेश जारी ही नहीं हुआ

यूपी सरकार 22 नवंबर, 2013 को यह आदेश जारी कर आराम से सो गई

मिशन यूपी में जुटे बिहारी योद्धा

फोटो- प्रभात पाण्डेय

महागठबंधन के तीनों दल-जनता दल (यू), राष्ट्रीय जनता दल व कांग्रेस-की तीन दिशाएं तय मानी जा रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 'संघ-मुक्त भारत' के राजनीतिक नारे और 'शराब-मुक्त भारत' के सामाजिक अभियान के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में हैं. वे भारतीय जनता पार्टी व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और समाजवादी पार्टी व इसके सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर एक साथ निशाना साध रहे हैं. उनके निशाने पर कांग्रेस नहीं है और यह स्वाभाविक है क्योंकि बिहार में वह उनका सहयोगी है, लेकिन यहां उसकी राह जुदा है. वह यूपी में सत्ता के दावेदार के तौर पर खुद को पेश कर सम्मानजनक 'राजनीतिक जमीन' की तलाश में है.

सरोज सिंह

उत्तर प्रदेश के चुनावी समर की आंच बिहार में भी शिद्दत से महसूस की जा रही है. प्रखर चेतना से संपन्न यह सूबा पड़ोस की राजनीतिक सरगर्मी से तपने लगा है. हालांकि चुनाव में अभी कई महीने हैं, पर सत्तारूढ़ महागठबंधन हो या विपक्षी एनडीए, दोनों के घटक दल अपने-अपने तरीके से वहां के चुनावी अखाड़े में दांव आजमाने को बेताब हैं. ये अपने-अपने राग पर अपनी-अपनी डफली बजाने की तैयारी करते दिख रहे हैं. महागठबंधन के तीनों दलों-जनता दल (यू), राष्ट्रीय जनता दल व कांग्रेस-की तीन दिशाएं तय मानी जा रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 'संघ-मुक्त भारत' के राजनीतिक नारे और 'शराब-मुक्त भारत' के सामाजिक अभियान के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में हैं. वे भारतीय जनता पार्टी व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और समाजवादी पार्टी व इसके सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर एक साथ निशाना साध रहे हैं. उनके निशाने पर कांग्रेस नहीं है और यह स्वाभाविक है क्योंकि बिहार में वह उनका सहयोगी है, लेकिन यहां उसकी राह जुदा है. वह यूपी में सत्ता के दावेदार के तौर पर खुद को पेश कर सम्मानजनक 'राजनीतिक जमीन' की तलाश में है. महागठबंधन के तीसरे दल राजद ने अब तक अपना पत्ता नहीं खोला है. हालांकि मुलायम सिंह यादव और सपा के प्रति वह अपनी सहानुभूति जाहिर कर चुका है. इधर, एनडीए में भी हालात सामान्य तो नहीं ही रहने की उम्मीद है. भारतीय जनता पार्टी सत्ता की दावेदार है और उस हिसाब से वोट की जुगाड़ में भी लगी है. बिहार एनडीए के गैर भाजपाई दल रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा), उपेन्द्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) को उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई हिस्सा मिलेगा या नहीं, यह तय नहीं है. ये तीनों दल चुनाव में उतरने की हरसूरत तैयारी में हैं.

जद (यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 'संघ-मुक्त भारत' का राजनीतिक नारा और शराबबंदी के सामाजिक अभियान के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अपनी भूमिका को बेहतर राजनीतिक आकार देने के ख्याल से कई महीने पहले ही मैदान में कूद पड़े. बिहार में नई सरकार के गठन के कुछ महीनों के भीतर उनके 'मिशन 2019' के बहाने मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत हो गई. उन्होंने साल के आरंभिक महीनों में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक मित्रों की तलाश की, पीस पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल जैसों से सकारात्मक संकेत भी मिले, पर बात नहीं बनी और इनके रास्ते अलग-अलग ही रहे. अपना दल के कृष्णा पटेल एनडीए से नाखुश हैं और इस खेमा से चुनावी तालमेल की उम्मीद जद (यू) सुप्रीमो को है. दोनों दलों के नेताओं ने इस आशय के संकेत भी दिए हैं. इधर, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की कार्य-शैली से नाराज होकर आरके चौधरी अलग हो गए हैं. आरके चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ होने की इच्छा जताई है. ये जद (यू) के लिए नई उम्मीद हो सकते हैं. ऐसी राजनीतिक कवायद जारी रहेगी, पर अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए सक्रियता जरूरी है, इस रणनीति के तहत ही जद (यू) आगे बढ़ रहा है. नीतीश कुमार ने मई में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से रैलियों-आयोजनों का सिलसिला आरंभ किया और हाल में इलाहाबाद के फूलपुर में रैली की है. अगले दो हफ्ते में ऐसी ही रैलियां लखनऊ और कानपुर में होनी हैं. लखनऊ के लिए 26 जुलाई की तारीख तय है जबकि कानपुर में अगस्त के पहले हफ्ते में रैली होनी है. नीतीश कुमार का यह राजनीतिक अभियान पूर्वांचल से आगे बढ़ रहा है. चुनावी सरगर्मी के परवान चढ़ने से पहले वे प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अपनी बात पहुंचा देना चाहते हैं. इस अभियान के जरिए वे देश के सबसे बड़े राज्य में अपनी पार्टी की संभावित राजनीतिक हैसियत और चुनावों के लिए उम्मीदवारों की खोज का काम तो कर ही रहे हैं, जद (यू) संगठन के विस्तार का उपाय भी ढूंढ रहे हैं.

जद (यू) की कार्य योजना है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मी के परवान चढ़ने-अर्थात् चुनाव आयोग की किसी भी घोषणा के पहले-अधिकतर हिस्सों में अपने अभियान का एक या उससे भी अधिक चरण पूरा कर लिया जाए. इसमें उनका सारा जोर गैर यादव पिछड़े और महादलित समाजिक समूहों के प्रभाव के इलाकों में खुद को गंभीरता से पेश करने की है. जद (यू) नेतृत्व इस रणनीति को आकार देने की तैयारी में जुटी है, इस काम में बिहार के राजनीतिक सहयोगियों से उसे कोई मदद नहीं मिलनी है. कांग्रेस ताम-झाम के साथ खुद चुनाव में उतर रही है और वहां नया सामाजिक समीकरण तैयार कर भाजपा के साथ-साथ सपा के लिए भी परेशानी पैदा करने की रणनीति अपना रही है. महागठबंधन के दूसरे सहयोगी राजद और इसके सुप्रीमो लालू प्रसाद सपा और इसके सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ अपनी सहानुभूति जाहिर कर चुके हैं. लालू प्रसाद ने पिछले दिनों साफ शब्दों में कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों (भाजपा) को पराजित करने के लिए मुलायम सिंह को साथ लिया जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश में भी बिहार जैसा महागठबंधन बनाने की जरूरत है. इसके लिए वे प्रयास करेंगे. फिर उन्होंने अपनी मिशन की सफलता की उम्मीद जताते हुए कहा कि उनका काम आरंभ हो गया है. पर, जद (यू) सुप्रीमो नीतीश कुमार ने इसका कोई नोटिस ही नहीं लिया. वे अपने अभियान में लगे हैं और भाजपा और सपा के खिलाफ एक साथ कारवां तैयार कर अपनी राह चल रहे हैं. जद (यू) अध्यक्ष की इस 'एकला चलो' की रणनीति के कई आयाम हैं. बिहार से दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर ही है और उत्तर प्रदेश की उपलब्धि उनके मिशन 2019 को नई उड़ान देगी. उनकी राष्ट्रीय स्वीकृति बनेगी और संभावित तीसरे मोर्चे के प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर उनका छवि-प्रक्षेपण भी होगा. दल का औपचारिक सुप्रीमो बनने के बाद हिन्दी पट्टी के किसी राज्य में यह पहला चुनाव है और इसमें उनके राजनीतिक कौशल की परीक्षा होनी है. इन सब के साथ एक बात और है. बिहार विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव की सपा और उनके परिवार की भूमिका को नीतीश कुमार कभी भूल नहीं सकते, वह इसे 'वापस' करना चाहते हैं और इसके लिए चुनाव से बेहतर स्थिति क्या हो सकती है! इसीलिए वे उत्तर प्रदेश में गैर यादव पिछड़े मतदाता समूहों को अपने साथ जोड़ने में लगे हैं. उनके इस राजनीतिक अभियान में उन क्षेत्रों को ही फोकस किया गया है, जहां गैर यादव पिछड़े सामाजिक समूहों का वर्चस्व है. उन राजनीतिक नेतृत्वों को वे तवज्जो दे रहे हैं जिनका असर इन सामाजिक समूहों पर है. इस काम में सांसद आरसीपी सिंह उनके मददगार हो रहे हैं. आरसीपी सिंह पूर्व आइएएस हैं और उत्तर प्रदेश कैडर के ही हैं. वहां गैर यादव राजनेताओं के साथ काम का उनका लंबा अनुभव है.

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद क्या करेंगे, यह उनके परिवार के बाहर के शायद ही किसी को मालूम हो. बिहार के सत्तारूढ़ महागठबंधन में एक मात्र लालू प्रसाद ही हैं जो उत्तर प्रदेश को लेकर साफ-साफ कुछ नहीं बोल रहे हैं. हालांकि वे अपने पहले मुख्यमंत्रित्व काल से-उन दिनों जनता दल ही था-उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं. लेकिन कैसी सफलता मिली है, यह भी बताने की जरूरत नहीं है. राजद सूत्रों पर भरोसा करें तो लालू प्रसाद अब सारा समय बिहार में देकर यहीं अपनी जमीन को अधिकाधिक पुख्ता बनाना चाहते हैं. फिर, मुलायम सिंह से अपने पारिवारिक संबंध को राजनीति के कारण प्रभावित नहीं होने देने की नीति पर चलने के पक्षधर दिख रहे हैं. अब उनके राजनीतिक फैसलों पर 'परिवार' का असर बढ़ता जा रहा है. उनकी सार्वजनिक गतिविधि भी इससे काफी प्रभावित हो रही है, यह सीमित होती जा रही है. पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनावों से राजद के अलग रहने को उनके बदलते राजनीतिक आचरण के उदाहरण के तौर पर पेश किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है. यह कहना कठिन है कि राजद सुप्रीमो किसके पास खड़ा दिखेंगे-मुलायम सिंह के आसपास या नीतीश कुमार के साथ. उनकी राजनीति के जानकारों को भरोसा है कि नीतीश-मुलायम को निकट करवाने की वे अंत तक कोशिश करेंगे. पर इसमें विफल होने की स्थिति में- परोक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर-वे मुलायम के साथ दिखना चाहेंगे. बिहार में उनके समर्थक सामाजिक आधार को भी यही रास आएगा. एनडीए में भी स्थिति कम रोचक नहीं है. भाजपा ने अपने बिहार के राजनीतिक साथियों को कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है. लोजपा उत्तर प्रदेश के चुनावी अखाड़े में उतरने की घोषणा कर चुकी है. पार्टी सुप्रीमो ने यह साफ नहीं किया है कि कैसे उतरेगी. पर, सूत्रों का कहना है कि वे एनडीए में ही हिस्सेदारी चाहते हैं. उन्हें उम्मीद है कि दलित होने के कारण उनकी पार्टी को तवज्जो मिल सकती है. पिछले चुनाव में भी रामविलास पासवान की पार्टी वहां मैदान में थी. हालांकि परिणाम के बारे में वे और उनके सहयोगी-जो परिवारजन ही हैं-कुछ कहने से कतराते हैं. हम के सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने कहा है कि उनकी पार्टी वहां चुनाव में हिस्सा लेगी. वे एनडीए से संदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं. बिहार के राजनीतिक हलकों की चर्चाओं पर भरोसा करें, तो उत्तर प्रदेश के लिए मांझी हाथ-पांव मार रहे हैं, लेकिन कहीं से उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही है. एनडीए के गैर भाजपाई बिहारी घटकों में उपेंद्र कुशवाहा और उनकी रालोसपा भाग्यवान हो सकती थी, यदि भाजपा की पुरानी योजना को साकार किया जाता. बहुजन समाज पार्टी से अलग हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को रालोसपा से जोड़ने की चर्चा चली थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. मौर्य बहुजन लोकतांत्रिक मोर्चा नाम से संगठन बना रहे हैं. अब बदले हालात में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में रालोसपा को कुछ मिलेगा, इसका खुलासा होना बाकी है. लेकिन इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम एनडीए की बिहार की आंतरिक बुनावट को प्रभावित करेगी.

लालू प्रसाद यादव

जीतनराम मांझी

रामविलास पासवान

उपेंद्र कुशवाहा

पिछले चुनाव में भी रामविलास पासवान की पार्टी वहां मैदान में थी. हालांकि परिणाम के बारे में वे और उनके सहयोगी-जो परिवारजन ही हैं-कुछ कहने से कतराते हैं. हम के सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने कहा है कि उनकी पार्टी वहां चुनाव में हिस्सा लेगी. वे एनडीए से संदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं. बिहार के राजनीतिक हलकों की चर्चाओं पर भरोसा करें, तो उत्तर प्रदेश के लिए मांझी हाथ-पांव मार रहे हैं, लेकिन कहीं से उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही है.

मंडल राजनीति के बिहार संस्करण के दिग्गजों-लालू प्रसाद और नीतीश कुमार-का उत्तर प्रदेश के चुनावी अखाड़ों में क्या हैसियत रही है, यह बताने की जरूरत नहीं है. लालू प्रसाद 1990 में मुख्यमंत्री बने और उसके कुछ ही वर्ष बाद वहां चुनाव होने पर उन दिनों के जनता दल ने उसमें अपने उम्मीदवार उतारे थे. लालू तब से वहां जा रहे हैं. बाद के चुनावों में भी वे वहां उम्मीदवार देते रहे, जाते रहे. परिणाम कैसे रहे यह बताने की जरूरत नहीं है. नीतीश कुमार भी वहां के चुनावों में अपने उम्मीदवार देते रहे, प्रचार में जाते रहे. लेकिन कभी भी उत्साहजनक नतीजा नहीं मिला. हालांकि इस बार हालात बदले हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजय-रथ को बिहार में रोकने के तमगा के साथ नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर कोई साल भर पहले से अभियान चला रहे हैं. इसके अलावा बिहार में शराबबंदी लागू करने का यश भी उनके साथ है. लेकिन वहां वे अकेले हैं. लालू प्रसाद का उनके साथ होना मुश्किल दिखता है और कांग्रेस खुद बड़ी तैयारी के साथ मैदान में है. फिर भी, इस भाजपा विरोधी राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति से एक संपर्क सेतु-प्रशांत किशोर-उनके पास हैं. इसका वे उपयोग करेंगे और करेंगे तो किस हद तक, यह कहना कठिन है. पर इतना तय है कि जद (यू) सुप्रीमो के मिशन 2019 की अग्निपरीक्षा उत्तर प्रदेश में ही होनी है. इस अग्निपरीक्षा में वे कुछ भी अपेक्षित हासिल कर लेते हैं, तो वह गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी राजनीति के केंद्र में खुद को पेश कर सकते हैं. इस लिहाज से यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण है.■

दलित-आदिवासियों के ख़िलाफ़ हिंसा

इतने क़ानून फिर भी क्यों बढ़ते जा रहे हैं अपराध

शशि शेखर

पिछले दिनों दो खबरें आईं, एक हरियाणा से और दूसरी गुजरात के सौराष्ट्र से. हरियाणा में एक दलित लड़की से गैंगरेप की खबर थी, तो वहीं गुजरात में कुछ दलित युवकों को एक राजनीतिक संगठन से जुड़े कथित गौ रक्षकों द्वारा पीटे जाने की खबर आई. दलित युवकों पर आरोप था कि वे एक मृत पशु की खाल उतार रहे थे. गौ रक्षकों द्वारा पीटे जाने के बाद कुछ दलित युवकों ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की. इस घटनाक्रम के बाद गुजरात के बड़े हिस्से में दलित समुदाय के लोगों ने आंदोलन किया. आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन दलित समुदाय के लोग दलित युवकों की पिटाई को लेकर काफी आक्रोशित थे.

ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ समय में दलितों के खिलाफ अपराध की केवल यही दो घटनाएं सामने आई हैं. दलितों और आदिवासियों के खिलाफ देश भर में तकरीबन हर दिन किसी न किसी किस्म की आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं. इनमें से कुछ मामलों में थानों में रिपोर्ट दर्ज होती है, जबकि अधिकतर मामले अनरिपोर्टेड (जिस घटना की सूचना पुलिस तक नहीं पहुंचती) रह जाते हैं. अगर सिर्फ सरकारी आंकड़ों की बात करें तो साल 2009 से लेकर 2014 तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है. और, ये तब हो रहा है, जब इस देश में अनुसूचित जाति/जनजाति के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों में कड़े कानून और सजा के प्रावधान हैं. सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि कड़े कानून होने के बाद भी समाज के इस कमजोर तबके के खिलाफ अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है?

अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के खिलाफ होने वाले अपराध का चरित्र राष्ट्रव्यापी है. यानी, असम से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर

आंध्र प्रदेश तक दलितों पर अत्याचार होता है. देश का कोई भी राज्य इससे अछूता नहीं है. पिछले पांच वर्षों (2009 से लेकर 2014 तक) के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ होने वाले अपराधों में 118 फीसद की वृद्धि हुई है. ये आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं. दलितों के खिलाफ होने वाली हिंसा का शिक्षा और समृद्धि से भी कोई संबंध नहीं है. ऐसा नहीं है कि कोई राज्य अगर अधिक शिक्षित या समृद्ध है, तो वहां दलितों के खिलाफ हिंसा नहीं होगी या कम होगी. उदाहरण के लिए देश में उच्च साक्षरता दर और सातवीं सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले केरल में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ होने वाले अपराध का दर उच्चतम है. 2014 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध उत्तर प्रदेश में (8075), फिर राजस्थान (8028) और बिहार (7893) में दर्ज हुए, जबकि अनुसूचित जनजाति के खिलाफ सर्वाधिक अपराध राजस्थान में (3952) दर्ज किए गए थे और इसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश (2279) और ओडिशा (1259) का.

भारत की वंचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ होने वाली हिंसा से निपटने के लिए कानून की कोई कमी नहीं है. इसके लिए विशेष कानून हैं, जिसमें नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अलावा एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) एक्ट 1989 जैसे कानून भी हैं. इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) है. लेकिन सवाल है कि क्या इन कानूनों का इस्तेमाल कर पाने में ये तबका समर्थ है या क्या उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई भी होती है? अगर समुचित कार्रवाई होती तो फिर क्या वजह है कि साल दर साल ऐसे अपराधों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. हालांकि, बेहतर रिपोर्टिंग और एफआईआर दर्ज होने की वजह से भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों की बढ़ती संख्या का पता चल रहा है जो पहले नहीं होता था. साल 2009 में जहां एससी के खिलाफ 33,412 अपराध हुए थे, वहीं 2014 में यह बढ़कर 47,064 हो गया. लेकिन अब भी ऐसी खबरें आती हैं कि पुलिस उनके केस दर्ज करने में अनिच्छा दिखाती है.

एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ 2233 बलात्कार और 704 हत्या व अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ 925 बलात्कार और 157 हत्या के मामले दर्ज किए गए. लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ऐसे अपराधों के मामले में कितने मामलों में दोषियों को सजा मिल पाती है? आंकड़ों के मुताबिक अन्य अपराधों के मुकाबले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के खिलाफ होने वाले अपराधों में कम से कम अभियुक्तों को दोषी करार दिया जाता है और उन्हें सजा मिल पाती है. आईपीसी के सभी मामलों में जहां सजा मिलने की दर 45 फीसदी है, वहीं इसकी तुलना में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों में सजा की दर महज 28 फीसदी ही है. जाहिर है, जब अपराधियों के मन में सजा का भय ही न होगा तो अपराध तो होंगे ही. ■

अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध की संख्या (वर्ष 2014)

राज्य	अपराध की संख्या
उत्तरप्रदेश	8075
राजस्थान	8028
बिहार	7893
आंध्रप्रदेश	4414
मध्यप्रदेश	4151

अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध की संख्या (वर्ष 2014)

राज्य	अपराध की संख्या
राजस्थान	3952
मध्यप्रदेश	2279
ओडिशा	1259
छत्तीसगढ़	721
आंध्रप्रदेश	627

कानून बनते गए, साल दर साल अपराध बढ़ते गए

अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध की संख्या

साल	अपराध की संख्या
2009	33412
2010	32643
2011	33719
2012	33655
2013	29408
2014	47064

अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध की संख्या

साल	अपराध की संख्या
2009	5250
2010	5764
2011	5756
2012	5922
2013	6793
2014	11451

feedback@chauthiduniya.com

किसानों से धोखाधड़ी कर रहीं बीज कंपनियां

सोरिन शर्मा

एक तरफ सरकार किसानों के हितों के लिए योजनाओं की घोषणा करती है, वहीं सरकारी अमला योजना प्रक्रिया में सेंध लगाकर लूट मचाने की तैयारी में जुट जाता है. विभिन्न राज्य सरकारों ने किसानों को बेहतर क्वालिटी का बीज देने के लिए बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं का गठन किया है. लेकिन बिहार में इन संस्थाओं द्वारा किसानों के हितों की उपेक्षा कर बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में घोर अनियमितताएं बरती जा रही हैं. ताजा मामला पटना स्थित बिहार राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का है. पता चला है कि इस संस्था के अधिकारी मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित एक निजी फर्म पैसर्स महाकाल सीड्स से साठ-गांठ कर प्रमाणीकरण प्रक्रिया को फर्जी ढंग से अंजाम देने में जुटे हैं.

इस मामले में बिहार राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से आरटीआई के अंतर्गत सब्जी फसल के खरीफ वर्ष 2015-16 से संबंधित प्रमाणीकरन, पंजीयन कराने वाली कंपनियों एवं संबंधित किसानों के बारे में जानकारी मांगी गई, तो विभाग ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी. विभाग का कहना है कि अभी निबंधन की प्रक्रिया जारी है, इसलिए सूचना नहीं दी जा सकती है. जाहिर है, सूचना नहीं दिए जाने के कारण उक्त विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल तो उठते ही हैं, साथ ही उसकी प्रक्रिया भी संदेहपूर्ण हो जाती है. इसके बाद जब महाकाल सीड्स, उज्जैन द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच की गई तो कई ऐसे तथ्यों का पता चला जिससे बीज प्रमाणीकरण प्रक्रिया में अनियमितता बरते जाने की जानकारी मिली.

मसलन, महाकाल सीड्स उज्जैन ने बिहार राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से लौकी, गिल्की, तरोई, करेला, बरबटी एवं भिंडी आदि का पंजीयन कराया था. बीज की बुआई से लेकर पैकेजिंग होने तक का समय बीज प्रमाणीकरण संस्था ने 11 माह निर्धारित किया है. बिहार राज्य प्रमाणीकरण संस्था के सौजन्य से महाकाल सीड्स उज्जैन ने उक्त फसल को मात्र 4 माह में ही उत्पादन संबंधी समस्त प्रक्रिया को पूर्ण कर प्रमाण पत्र हासिल कर लिया. इसके बीज के लॉट नंबर पर मई माह अंकित है, जो पूर्ण रूप से संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है. इसके अलावा परीक्षण एवं पैकेजिंग की तिथि भी मई माह ही अंकित की गयी है. यानी उक्त फर्म ने बीज की कटाई, मढ़ाई, सुखाई, सफाई एवं पैकिंग जैसी समस्त प्रक्रियाएं मई माह में ही पूर्ण कर लीं. इतनी बड़ी मात्रा में समस्त प्रक्रिया जैसे नमूनों का परीक्षण, पैकेजिंग आदि का एक माह में होना संदिग्ध प्रतीत होता है.

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन द्वारा जारी सीड्स प्रोडक्शन बुक के अनुसार लौकी, गिल्की, तरोई, करेला एवं भिंडी की फसल सीड्स प्रोडक्शन के लिए रबी सीजन उपयुक्त नहीं है. इसके अनुसार बीज उत्पादन के लिए बुआई का समय उत्तर भारत में खरीफ सीजन में जून-जुलाई एवं जायद फसलों के लिए फरवरी-मार्च है. इससे स्पष्ट है कि ये फसलें रबी सीजन में बीज उत्पादन के लिए पंजीयन हेतु उचित नहीं हैं. इसका मतलब यह हुआ कि उक्त फसलों की बुआई फरवरी माह में की गई है, जबकि कंपनी ने इसे मई महीना बताया है.

यह भी जानकारी मिली है कि बिहार राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा 1 एवं 2 मई को प्रमाण पत्र दिया गया. साथ ही इसी महीने में बिहार राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों/प्रतिनिधियों की देख रेख में महाकाल सीड्स ने बीजों में टैग लगाकर पैकिंग की. उक्त फर्म ने संयुक्त संचालक उद्यान, भोपाल को दिए पत्र में यह बताया कि उनका समस्त प्रमाणित बीज 17/06/16 को बिहार से आ रहा है. लेकिन उक्त कंपनी आज तक इस संबंध में कोई प्रमाण नहीं दे सकी है कि उनका बीज बिहार से आया है या वहां बीज पर टैग लगाकर पैकेजिंग की गई है. यह इस बात का प्रमाण है कि न तो उक्त फर्म का किसी तरह का बीज बिहार राज्य बीज प्रमाणीकरण के अधिकारियों की देख-रेख में बिहार में पैक हुआ और न ही कोई बीज बिहार से मध्य प्रदेश लाया गया. इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए यह अंदेशा है कि बिहार राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से मिले टैग के सहारे महाकाल सीड्स ने घटिया स्तर के बीज अपने गोदाम में भर दिए हों.

भारत जैसे एक कृषि प्रधान देश में किसानों के हितों में चलाई जा रही योजनाओं में अगर धांधली होती है, तो इससे किसानों एवं देश की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है. ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए बीज कंपनियां सरकारी संस्थाओं से साठ-गांठ कर किसानों के हितों की अनदेखी कर रही हैं. जाहिर है, ऐसी कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि किसानों के हितों की अनदेखी न हो सके. ■

feedback@chauthiduniya.com

केवल घोषणाओं की है रघुवर सरकार

राज्य में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा है कि वे राजधानी में मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार की गाड़ी छीनकर भाग गए, वहीं मुख्यमंत्री के गृह नगर जमशेदपुर में अपराधियों ने उनके एक रिश्तेदार की हत्या घर में घुसकर कर दी. नक्सलियों पर रोकथाम एवं जड़ से नेस्तनाबूद करने के जितने दावे राज्य के मुखिया रघुवर दास कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं. नक्सलियों ने राज्य के सभी 24 जिलों में अपना वर्चस्व कायम कर लिया है और स्थिति ये है कि विकास कार्यों में नक्सलियों को लेवी दिये बिना काम शुरू करना असंभव है. हालात ये हैं कि नक्सल प्रभावित इलाकों में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी भी अपनी जान की रक्षा के लिए एक निश्चित राशि उग्रवादी संगठनों को देते हैं.

प्रशांत शरण

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास अपनी तारीफ में पार्टी के आला नेताओं से अपनी पीठ भले ही थपथपा लें, पर जमीनी हकीकत यह है कि सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है. चाहे वह राज्य में अपराध का बढ़ता ग्राफ हो या नक्सलवाद या फिर विकास के अन्य दावे. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यह नारा दिया कि 'पहले पढ़ाई तब विदाई' पर इस नारे को उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी ने धत्ता बताते हुए अपने बेटे मुन्ना मरांडी की शादी मात्र 12 वर्षीया नाबालिग लड़की से कर दी. दूसरी तरफ राज्य में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा है कि वे राजधानी में मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार की गाड़ी छीनकर भाग गए. वहीं मुख्यमंत्री के गृह नगर जमशेदपुर में अपराधियों ने उनके एक रिश्तेदार की हत्या घर में घुसकर कर दी. नक्सलियों पर रोकथाम एवं जड़ से नेस्तनाबूद करने के जितने दावे राज्य के मुखिया रघुवर दास कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं. नक्सलियों ने राज्य के सभी 24 जिलों में अपना वर्चस्व कायम कर लिया है और स्थिति ये है कि विकास कार्यों में नक्सलियों को लेवी दिये बिना काम शुरू करना असंभव है. हालात ये हैं कि नक्सल प्रभावित इलाकों में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी भी अपनी जान की रक्षा के लिए एक निश्चित राशि उग्रवादी संगठनों को देते हैं. विकास कार्यों की बात करें, तो डेढ़ साल में यहां एक भी उद्योग नहीं लगा और न ही किसी औद्योगिक घराने के साथ कोई एमओयू साइन हुआ है. मुख्यमंत्री ने जीरो पावर कट की घोषणा कई बार की, लेकिन स्थिति यह है कि राजधानी में ही तीन से चार घंटे रोज बिजली की कटौती हो रही है.

मुख्यमंत्री ने एक लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, पर अभी तक तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय नौकरी के लिए नियमावली नहीं बनी है. इसके बाद ही यह तय होगा कि वह पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होगा या सभी लोग आवेदन कर सकेंगे. पांच लाख युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, पर पांच हजार लोगों को भी प्रशिक्षित नहीं किया जा सका है.

भ्रष्टाचार मुक्त राज्य का दावा मुख्यमंत्री हमेशा करते रहे हैं, पर विकास कार्यों में भ्रष्टाचार चरम पर है. विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों को चालीस प्रतिशत तक कमीशन देना पड़ता है. स्वयं मुख्यमंत्री रघुवर दास, उनके राजनीतिक सलाहकार अजय कुमार एवं पुलिस के अपर महानिदेशक स्तर के एक अधिकारी राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के एक विधायक निर्मला देवी को पांच करोड़ रुपये का प्रलोभन देने के आरोप में घिरे हैं. इस संबंध में एक जनहित याचिका भी उच्च न्यायालय में दाखिल की गई है.

मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर काबू पाने के उद्देश्य से एंटी करप्शन ब्यूरो बना तो दिया, लेकिन अभी तक केवल तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ही इसकी पकड़ में आए हैं. जबकि यहां कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा व निर्माण जैसे विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है. मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुखिया हो या मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई कर सचिवालय भेज दिया जाएगा. पर सवाल यह है कि क्या सचिवालय में केवल निकम्मे एवं भ्रष्ट अधिकारियों को रखा गया है, जबकि सारे नीति-निर्धारण एवं फंड यहीं से रिलीज होते हैं.

सिंचाई कार्यों के लिए बनाये जा रहे चेक डैम व बड़े तालाबों में भ्रष्टाचार आम बात है, किसानों को अनुदान पर दिये जाने वाले मशीनों में भी भ्रष्टाचार चरम पर है. इस संबंध में विभाग के प्रधान सचिव नितीन मदन कुलकर्णी तो मंत्री पर ही आरोप लगा रहे हैं. पूरे राज्य में एक लाख डोभा की खुदाई में भी जमकर दुरुपयोग हुआ. डोभा की खुदाई मनरेगा के तहत मजदूरों से कराना जाना था, पर डोभा जेसीबी मशीन से खोदा गया. कई जिलों के उपायुक्तों ने संबंधित लोगों को फटकार लगाई, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई.

ठीक यही स्थिति यहां स्वच्छ भारत मिशन की भी है. राज्य में कागजों पर तो 21 लाख शौचालय का निर्माण दिखा दिया गया, पर यूनिसेफ के एक सर्वे से पता चला कि चौदह लाख शौचालयों का कहीं अता-पता नहीं है. स्वच्छ भारत मिशन का यहां सबसे बुरा हाल है. स्मार्ट सिटी में दूसरी बार सिर्फ राजधानी रांची ही स्मार्ट सिटी घोषित हुआ है. यहां बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है.

सड़क एवं भवन निर्माण के नाम पर यहां लूट मची है. बनी हुई सड़कों को फिर से बना दिया जाता है. मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी कि सभी पंचायतों को सड़क से जोड़ा जाएगा, पंचायतों में स्वास्थ्य भवन एवं पंचायत भवन बनाए जाएंगे, पर यह केवल घोषणा तक ही सिमट कर रह गया.

शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार की बात कही जा रही है, पर हालत ये है कि गांव में हाई स्कूल की शिक्षा पाने के लिए 25 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि महाविद्यालय में पढ़ना तो गांव के लोगों के लिए सपना ही है. स्वास्थ्य का हाल भी यहां सबसे बुरा है. यहां कुपोषित मां और बच्चों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है. कुपोषण के कारण बच्चे असमय दम तोड़ रहे हैं. इसके लिए कई योजनाएं चलाई गईं, लेकिन कुपोषण पर काबू नहीं पाया जा सका.

वहीं, मुख्यमंत्री रघुवर दास घोषणा करते हैं कि राज्य में विकास की धारा बहने लगी है और अब यहां विकास कार्य दिखने लगे हैं. मुख्यमंत्री को कागजी आंकड़ों पर विश्वास न कर भौतिक सत्यापन करना चाहिए, तभी यह पता चलेगा कि सचमुच झारखंड कितना विकास कर रहा है.■

डेढ़ वर्षों में दिख रहा है राज्य में विकास : मुख्यमंत्री

भाजपा के आला नेताओं का आशीर्वाद पाकर मुख्यमंत्री रघुवर दास कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं. अपनी पार्टी के पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए वे कहते हैं कि पिछली सरकार ने झारखंड में कुछ नहीं किया, जबकि उनके डेढ़ साल के कार्यकाल में विकास की झलक दिखने लगी है. दास कहते हैं कि वे वादा नहीं करते, बल्कि कर के दिखाते हैं. झारखंड गठन के बाद से स्थानीय नीति को लेकर केवल राजनीति होती रही, लेकिन सत्ता में आते ही उन्होंने स्थानीय नीति की घोषणा कर दी, जिसका लाभ यहां के लोगों को मिल रहा है. तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नौकरी केवल स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दी गयी है.

यह पूछे जाने पर कि आपने पिछले वर्ष एक लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, इस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई, तो उन्होंने कहा कि सभी विभागों को रिक्त पदों की सूची देने को कहा गया है. जैसे-जैसे रिक्तियां आती जा रही हैं, उन्हें भरने का काम किया जा रहा है. राज्य में बेसिक संरचना का विकास हो रहा है, सभी पंचायतों को सड़क से जोड़ने का काम शुरू हो गया है, साथ ही रिंग रोड एवं शहरी सड़कों का निर्माण कार्य भी तेजी से हो रहा है. जल संरक्षण के लिए डेढ़ लाख डोभा बनाए गए हैं. इस साल पांच लाख डोभा बनाने का लक्ष्य रखा गया है. डोभा में जल संचय होने से इसका लाभ किसानों को मिलेगा, साथ ही बड़े तालाबों के निर्माण का भी आदेश दिया गया है.

उन्होंने कहा कि राज्य में बड़े औद्योगिक घरानों ने झारखंड में निवेश की इच्छा जताई है. उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए महानगरों में रोड शो का आयोजन किया जा रहा है. मुम्बई एवं बेंगलुरू में हुए कार्यक्रम में कई उद्योगपति निवेश करने को राजी हुए हैं. झारखंड में सभी आधारभूत संरचना, खनिज एवं अन्य संसाधन मौजूद हैं. झारखंड धीरे-धीरे इंडस्ट्रीयल हब बनने की ओर अग्रसर है. नक्सलवाद पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. नागरिकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है. विधि-व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा हमने जनता से किया है. भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, इसके लिए एक एंटी करप्शन ब्यूरो का गठन किया गया है.■

राज्य में रघुवरी नहीं रावण राज: सुखदेव

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत झारखंड में रघुवर राज नहीं, बल्कि रावण राज मानते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है. थाने में आदिवासी इंस्पेक्टर की हत्या एवं एक निर्दोष आदिवासी बालक की पुलिस द्वारा पीट-पीटकर हत्या से यह साबित होता है कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है. पुलिस के वरीय अधिकारी भी यह स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य में आपराधिक व नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे विकास कार्य बाधित हो रहे हैं.

उन्होंने कहा कि पिछले माह अपराधियों ने राज्य में 28 लोगों की हत्या कर दी है. राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो गई है. इस सरकार को घोषणा वाली सरकार की संज्ञा देते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी की तरह लोगों को केवल सब्जबाग दिखा रही है. राज्य में स्थानान्तरण और पदस्थापन का खेल चल रहा है. पैसा लेकर अधिकारियों की पोस्टिंग की जा रही है, अधिकारियों को लूट की छूट दे दी गई है और इसका लाभ मंत्री, मुख्यमंत्री उठा रहे हैं.

उन्होंने सरकार को आदिवासी विरोधी बताते हुए कहा कि अधिसूचित क्षेत्र में भी आदिवासी एवं स्थानीय लोगों को तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में सौ प्रतिशत आरक्षण नहीं मिल पा रहा है. आदिवासी बहुल गांवों में विकास कार्य रोक दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति भी बाहरी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई है.■

जनता को गुमराह कर रही है सरकार: बाबुलाल

झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबुलाल मरांडी तो इस सरकार को केवल कागजी घोषणाओं वाली सरकार बताते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है. अपराध, नक्सलवाद जहां तेजी से बढ़ा है, वहीं विकास का काम कुछ हुआ ही नहीं है. यहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है. पुलिस कस्टडी में निर्दोष मासूम की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, पर अभी तक पुलिस अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उल्टे उस मासूम को ही नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाला बताकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की जा रही है. सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी के बेटे पर यौन शोषण का तो आरोप है ही, उसने बारह वर्ष की लड़की के साथ विवाह किया, पर सरकार ने इनलोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. वहीं इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी का ही तबादला कर दिया गया. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घोषणा की थी कि तीन वर्ष के पहले किसी अधिकारी का स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा, पर छह-छह माह में ही अधिकारियों का स्थानान्तरण पैसे के लिए हो रहा है.

मुख्यमंत्री बदलता झारखंड का नारा दे रहे हैं, पर झारखंड में क्या बदला है? उद्योग लगाने के नाम पर मंत्री, अधिकारी देश-विदेश का दौरा कर रहे हैं, जबकि राज्य में एक भी उद्योग धंधे नहीं लगे हैं. वहीं, स्थानीय नीति के नाम पर स्थानीय लोगों का हक मारा जा रहा है.■

नक्सल प्रभावित इलाकों में किसान कर रहे पर्ल फार्मिंग

मोती उत्पादन से बदली तक़दीर

चंदन राय

जोश और जुनून हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी राह निकल आती है. महाराष्ट्र में नक्सल प्रभावित इलाका गढ़चिरौली व चंद्रपुर जिले कभी किसानों की आत्महत्या की वजह से चर्चा में रहते थे. यहां के किसानों के बारे में कहा जाता था कि वे कर्ज में ही जन्म लेते हैं, कर्ज में जीते हैं और कर्ज में ही दम तोड़ देते हैं. अंकोला निवासी पर्ल साइंटिस्ट अशोक मनवानी ने सूखाग्रस्त चंद्रपुर के किसानों की तकदीर बदलने की ठान ली. उन्होंने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को मोतियों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया. उनके प्रशिक्षण का परिणाम है कि नक्सल प्रभावित यह क्षेत्र आज मोतियों के उत्पादन के लिए चर्चा में है.

वर्ष 2012 में अशोक मनवानी ने पचास किसानों को मोतियों के उत्पादन की ट्रेनिंग दी. वे बताते हैं कि जंगल में किसानों को ट्रेनिंग देना भी आसान नहीं था. ओएस्टर (सीप) खोलने के लिए ओपनर व ऑपरेशन टूल्स स्थानीय बाजार में उपलब्ध नहीं थे. कुछ समृद्ध किसान चेन्नई से इन उपकरणों को मंगाकर मोती का उत्पादन कर रहे थे. इन महंगे टूल्स को खरीदना चंद्रपुर के किसानों के लिए संभव नहीं था. किसानों को ट्रेनिंग तो दे दी गई, लेकिन वे बिना उपकरण के मोतियों का उत्पादन करें तो कैसे? उन्होंने कहा, बिना सरकारी मदद और समुचित उपकरण के इन किसानों की मदद कर पाना काफी मुश्किल था. एक बार तो ऐसा हुआ कि किसानों को ट्रेनिंग देने के दौरान मेरे पास भी ऑपरेशन टूल्स उपलब्ध नहीं थे. चेन्नई स्थित कंपनी बंद हो चुकी थी. सोचा, क्यों न कुछ ऐसा उपकरण बनाया जाए जो सस्ता हो और आसानी से उपलब्ध भी हो. साइकिल के स्पोक से ओएस्टर ओपनर बना दिया. ओएस्टर का आवरण खोलते समय यह ख्याल रखना होता है कि वह ज्यादा न खुले, नहीं तो जीव दम तोड़ देता है. इस उपकरण से किसानों की परेशानी कम हुई, लेकिन अभी एक समस्या और थी. ओएस्टर को तालाब में डालने से पहले उसे ऑपरेट करना होता है. उसके अंदर एक बाह्य पदार्थ डालना होता है, जिससे मोतियों का उत्पादन होता है. यहां के किसानों को ऑपरेशन टूल्स उपलब्ध कराने के लिए एक लकड़ी की मशीन बनाई, जिससे इस इलाके में मोतियों का उत्पादन संभव हो सका. इन दोनों आविष्कारों के लिए वैज्ञानिक अशोक मनवानी को सरकार से अवार्ड भी मिल चुका है.

आज चंद्रपुर में सुयोग कावड़े जैसे कई किसान मोतियों का उत्पादन कर लाखों रुपये महीने कमा रहे हैं. इस इलाके की खासियत है कि यहां तालाब व छोटी नदियों में सीप बहुतायत में उपलब्ध हैं. कुछ किसान नदी से सीपियों को निकाल मुंबई व आस-पास के इलाकों में बेचकर भी पैसा कमा रहे हैं. कुछ किसान सीपियों से हैंडीक्राफ्ट्स तैयार कर स्थानीय बाजार में बेच रहे हैं. सीप से बने दीयों की एक खासियत है कि इनकी सतह चमकीली होने के कारण यह ज्यादा रोशनी बिखेरती हैं, साथ ही मिट्टी के दीयों की अपेक्षा कम तेल सोखती हैं. अब तो यहां के किसान सीप

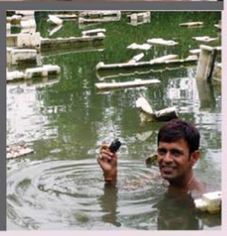

व मछली पकड़ने की जाली व अन्य उपकरण भी तैयार कर अच्छा पैसा कमा रहे हैं. गोंदिया जिले के गांधी ने भी किसानों को एकजुट कर मोती उत्पादन के लिए प्रेरित किया. गांधी वर्कशॉप आयोजित कर पर्ल कल्चर से किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं. एक पिछड़े इलाके में पर्ल कल्चर के सपने को उतारना आसान नहीं था. लेकिन इलाके के किसानों ने हिम्मत दिखाई और वे अब पारंपरिक खेती छोड़कर कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक तरीकों से मोती उत्पादन सीखकर एक बेहतर जीवन जी रहे हैं. अब गढ़चिरौली जैसे क्षेत्र में मोती उत्पादन के क्षेत्र में कुछ बड़े प्रोजेक्ट भी आने लगे हैं. सरकार भी मोती उत्पादक किसानों की मदद के लिए वित्तीय मदद दे रही है.

मिशन पर्ल कल्चर को बनाया लक्ष्य

2001 से ही अशोक मनवानी फ्रेश वाटर पर्ल कल्चर सलाहकार के रूप में देशभर में लोगों को मोती उत्पादन के लिए प्रेरित कर रहे हैं. अशोक बताते हैं कि कॉलेज लाइब्रेरी में मोती उत्पादन के बारे में पढ़ा था. तभी से अंकोला में मोहना नदी से सीप चुनकर घर ले आता और सीप को ऑपरेट कर समीप के तालाब में डाल देता. कई वर्षों तक ऐसा करता रहा, लेकिन सीप से मोती नहीं निकली. छोटी सीप से मोती का उत्पादन नहीं होने पर 10-12 साल तक रिसर्च करता रहा. आखिरकार छोटे तालाब व नदियों के मीठे जल में मोती उत्पादन में सफलता मिली. 2002 में उनकी शादी कुलजंन दूबे से हुई, जो हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट और फैशन डिजाइनर थीं. शादी के तीन दिन बाद ही अशोक मनवानी किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए घर से निकल पड़े. तभी से पति-पत्नी दोनों ने मिशन पर्ल कल्चर को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया. उनका मकसद है कि देश मोती उत्पादन में आत्मनिर्भर बने ताकि यहां से अन्य देशों को मोतियों का निर्यात किया जा सके.

ऐसे होती है मोतियों की खेती

प्राकृतिक रूप से सीप में कोई बाहरी पदार्थ, बालू का कण या कीट के प्रवेश करने से मोती का उत्पादन होता है. धीरे-धीरे सीप इस बाहय पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं और उस कण के चारों तरफ एक चमकदार परत जमा करते जाते हैं. प्राकृतिक रूप से मोती बनाने में इसी तरीके का इस्तेमाल होता है. मोती बनने में पांच से छह महीने का समय लगता है. अशोक किसानों को डिजाइनर मोती भी तैयार करने की ट्रेनिंग देते हैं, जिसकी घरेलू व विदेशी बाजार में काफी मांग है. डिजाइनर मोती तैयार करने के लिए खास किस्म के खांचे बनाकर सीप में डाले जाते हैं, जिससे बुद्ध, गणपति, साईं व होली क्रॉस डिजाइन के मोती तैयार किए जाते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

समेकित खेती से कर रहे मोती उत्पादन

बिहार में बेगूसराय जिले के तेतारी गांव में जयशंकर प्रसाद बूढ़ी गंडक नदी से सीप इकट्ठा कर मोतियों की खेती कर रहे हैं. उन्होंने पर्ल वैज्ञानिक अशोक मनवानी के निर्देशन में मोती उत्पादन की ट्रेनिंग ली. जयशंकर प्रसाद को समेकित खेती के लिए 2011 में नेशनल अवॉर्ड भी मिल चुका है. जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मीठे जल वाले मोतियों के उत्पादन के लिए किसानों को सरकार प्रोत्साहन दे, तभी मांग के अनुरूप उत्पादन संभव है. मोती का बाजार विकसित होगा, तभी किसान बेहतर उत्पादन के लिए प्रेरित होंगे. जयशंकर अपने डेढ़ एकड़ के तालाब में कतला, रेहु जैसी मछलियों की ब्रीडिंग कराते हैं. कतला और रेहु मछलियां ठहरे पानी में ब्रीडिंग नहीं करती हैं, यह वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है. इसी तालाब में बूढ़ी गंडक नदी से सीप इकट्ठे कर वे मोतियों की खेती करते हैं. तालाब के मेड़ पर उन्होंने सागवान, अमरूद, अखरोट और केले के सैकड़ों पेड़ लगाए हैं, जिससे तालाब में गिरे पत्तों से मछलियों का भोजन (पेंटान) तैयार होता है. तालाब के किनारे की जमीन पर वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन के अलावा बत्तख, बर्बरीक नस्ल की बकरी व मुर्गी पालन भी किया जाता है. वे पॉली हाउस में औषधीय पौधों व सब्जियों की खेती कर अपने क्षेत्र में किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं. वे कहते हैं कि मोती उत्पादन के लिए उच्च शिक्षा और ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती, लगन हो तो कम पैसे में ही मोती उत्पादन किया जा सकता है.

शौचालय निर्माण के अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी ज़रूरत

क्या ऐसे साफ होंगी नदियां

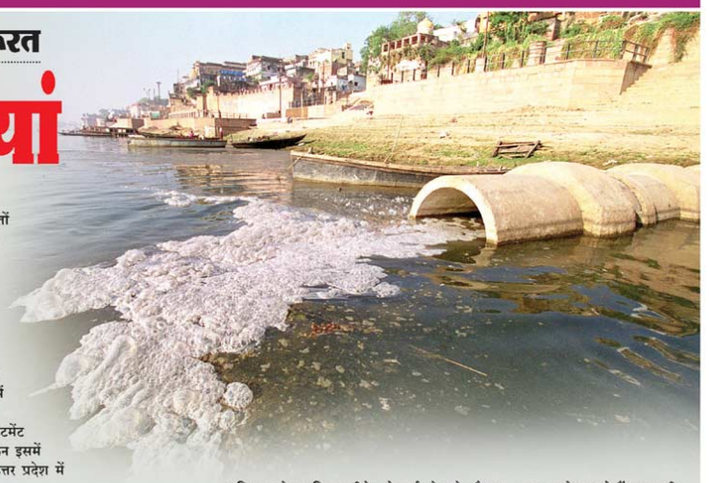

धर्मेंद्र कुमार सिंह

देश में शहरी क्षेत्रों के 38 करोड़ लोगों द्वारा उत्पन्न 30 प्रतिशत गंदा पानी ही शुद्ध होकर निकलता है. बाकी 70 प्रतिशत पानी बिना ट्रीटमेंट के नदियों, नालों, तालाबों व झीलों में डाल दिया जाता है. सीवेज का गंदा पानी इसी तरह नदियों, नालों, तालाबों और अन्य जगहों पर छोड़ा जाता रहा, तो न नदियां साफ हो पाएंगी और न नमामि गंगे की योजना ही परवान चढ़ सकेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि वर्ष 2019 तक देश का हर नागरिक शौचालय का इस्तेमाल करे. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के पास अभी चार साल का समय है, लेकिन सवाल है कि सरकार इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगी? अगर मान लिया जाए कि सरकार यह लक्ष्य प्राप्त भी कर लेती है, तो नदियों, नालों एवं जल के स्रोतों को प्रदूषित होने से कैसे रोका जाएगा?

सरकारी की तरफ से जारी आंकड़ों से पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों से लगभग 62,000 मिलियन लीटर (एमएलडी) गंदा पानी प्रतिदिन निकलता है. भारत में परिशोधन क्षमता केवल 23,277 एमएलडी या निकलने वाले सीवेज का 30 प्रतिशत है. आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में सूचीबद्ध 816 नगर निगम के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट(एसटीपी) में से 522 ही काम कर रहे हैं. 62,000 एमएलडी में से सूचीबद्ध क्षमता 23,277 एमएलडी है, लेकिन वास्तव में निकलने वाले गंदे पानी में से 18,883 एमएलडी से अधिक पानी परिशोधित नहीं किया जाता है. इसका मतलब यह हुआ कि भारत के शहरी इलाकों से बहने वाला 70 प्रतिशत गंदा पानी परिशोधित नहीं किया जाता है. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट के मुताबिक 79 सीवेज संयंत्र काम नहीं कर रहे हैं, वहीं 145 निर्माणाधीन हैं और 70 प्रस्तावित हैं.

भारत के एक लाख से अधिक और 50 हजार से एक लाख तक के आबादी वाले शहरों से 38,255 एमएलडी सीवेज प्रतिदिन निकलता है, जिसमें से केवल 11,787 एमएलडी निकलने वाले सीवेज को परिशोधित किया जाता है. बाकी दूषित पानी को सीधे नदियों, नालों, झीलों या अन्य जल स्रोतों में छोड़ दिया जाता है. रिपोर्ट के अनुसार इस वजह से भारत के भूजल संसाधनों का तीन-चौथाई भाग प्रदूषित होता है और जल स्रोतों का लगभग 80 प्रतिशत भाग प्रदूषित है. साथ ही 39 प्रतिशत संयंत्र धाराओं या जल स्रोतों में छोड़े जाने के लिए पर्यावरण नियमों के अनुरूप नहीं है. जल प्रदूषण का 75 से 80 प्रतिशत हिस्सा घरेलू सीवेज से निकलता है जो बिना किसी ट्रीटमेंट के स्थानीय जल स्रोत में मिल जाता है.

पूरे देश में काम करने वाले 522 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे अधिक 86 पंजाब में हैं, लेकिन इसमें 38 या उससे भी कम काम करने योग्य हैं. उत्तर प्रदेश में

सबसे अधिक 62 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहे हैं. दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 60 और तीसरे स्थान पर कर्नाटक में 44 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहे हैं.

भारत के शहरी क्षेत्रों में करीब दो करोड़ घरों में सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है. एफएसएम की रिपोर्ट के मुताबिक एक करोड़ पचास लाख घरों में शौचालय नहीं हैं. अगर हम एक परिवार में पांच लोगों को मानते हैं तो इसका मतलब हुआ कि साढ़े आठ करोड़ लोग शहरी इलाकों में वगैर साफ-सफाई के रह रहे हैं. लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में जानकारी मिली कि 7 दिसंबर 2015 तक ग्रामीण परिवारों में केवल 48.4 प्रतिशत घरों में शौचालयों की सुविधा है. शहरी क्षेत्रों में 7.1 प्रतिशत परिवारों के पास ऐसे(पिट लैटरिन्स) शौचालय हैं जिसमें कोई स्लैब नहीं है जो सीधे नालियों में मिलते हैं. शहरी क्षेत्रों में केवल 32.7 प्रतिशत लोग भूमिगत सीवेज नेटवर्क से जुड़े शौचालय का उपयोग करते हैं. साथ ही सेप्टिक टैंक के साथ शहर में रहने वाले लगभग 8 करोड़ परिवारों में से 3 करोड़ परिवारों के पास कचरा निस्तारण के लिए कोई साधन नहीं है.

शहरी परिवारों के 12.6 प्रतिशत और झुग्गी-झोपड़ी की बात करें, तो इनमें 18.9 प्रतिशत लोग खुले में शौच जाते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक 1.7 प्रतिशत लोग शौचालय होने के बावजूद खुले में शौच जाते हैं.

राज्यों में स्वच्छता की स्थिति

मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में करीब 22.5 प्रतिशत लोग खुले में शौच जाते हैं, तमिलनाडु में 16.2 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 14.8 प्रतिशत, गुजरात 8.7 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 7.7 प्रतिशत और दिल्ली में 3 प्रतिशत लोग खुल में शौच जाते हैं. पिछले वर्ष मई में लोकसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक लगभग 55 प्रतिशत ग्रामीण परिवार खुले में शौच जाते हैं. इस संबंध में ओडिशा पहले स्थान पर है. ओडिशा में 86.6 प्रतिशत परिवार और केरल में 3.9 प्रतिशत लोग खुले में शौच जाते हैं.

मोदी सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना है. ग्रामीण शहरी इलाकों में सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय बनाना और पानी की आपूर्ति करना. सड़कें, फुटपाथ और बस्तियों को साफ रखना और अशुद्ध जल को स्वच्छ करना. लेकिन अभी 70 प्रतिशत सीवेज को बिना परिशोधित किए नदियों, नालों, झीलों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों में छोड़ा जा रहा है. सरकार शौचालय बनाने पर जोर दे रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या शौचालयों से निकलने वाली गंदगी के ट्रीटमेंट के लिए प्लांट भी लगाया जाएगा या इसे बिना परिशोधन के ही जलस्रोतों में छोड़ दिया जाएगा? सच्चाई यह है कि सरकार अपने लक्ष्य से बहुत पीछे नजर आ रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

दलितों के साथ यह बर्ताव दुर्भाग्यपूर्ण है

भाजपा का यह कहना बिल्कुल सही था कि हम आपको एक वैकल्पिक शासन देंगे और संप्रग सरकार के 10 साल के शासन के बाद लोगों ने भाजपा को सत्ता सौंप दिया. लेकिन भाजपा को सावधान रहना चाहिए. भाजपा को यह नहीं कहना चाहिए कि लोगों ने संविधान या स्वतंत्रता संग्राम की नीतियों को नकार दिया है. ऐसी बातें सच्चाई से कोसों दूर हैं. हां, लोग बेहतर शासन चाहते हैं. मुद्रास्फीति की बढ़ती दर से सबसे ज़्यादा ग़रीब आदमी परेशान है. भ्रष्टाचार से देश में एक बुरा वातावरण बनता है. शायद इन्हीं दो वजहों से भाजपा को 282 सीटें प्राप्त हुई थीं. लेकिन एक बार जब आप शासन में आ जाते हैं तब आप चुनावी मोड में नहीं रह सकते हैं.

गुजरात में ऊना की दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने जनता और संसद के मन को झकझोर कर रख दिया है. आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी देश में दलितों के साथ सवर्णों द्वारा सही बर्ताव नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है. हालांकि यह एक सामाजिक मुद्दा है, लेकिन जहां तक सरकार की बात है, क़ानून और व्यवस्था बनाए रखे जाना चाहिए. क़ानून के उल्लंघन की दशा में पुलिस और ज़िला प्रशासन द्वारा कड़ाई से निपटा जाना चाहिए. भाजपा का सत्ता में होना और आम तौर पर सवर्णों की पार्टी माना जाना-इस समस्या को और बढ़ा देता है. यदि इस पर समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती है और इस समस्या का निर्णायक हल नहीं निकाला जाता है, तो इस धारणा को बल मिलेगा कि प्रशासन इस मामले में गंभीर नहीं है और यह सब भाजपा के पक्ष में नहीं जाएगा. मुझे यक़ीन है कि ऐसी चीज़ें स्थानीय परिस्थितियों और स्थानीय लोगों के उकसावे की वजह से होती हैं और इसमें राज्य के अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं है और केंद्रीय अधिकारियों की तो बिल्कुल नहीं होती है. लेकिन प्रशासन ने क्या कार्रवाई की और कितनी तेज़ी से की, इससे यह संकेत मिलता है कि यह सब क्यों और कैसे हुआ? बेशक सरकार ने संसद को भरोसा दिया है कि वे कार्रवाई करेंगे, उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में तीव्र कार्रवाई होगी. वैसे जितनी जल्दी कार्रवाई होगी, उतना ही देश के लिए बेहतर होगा.

उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान मायावती के ख़िलाफ़ दिया है. दयाशंकर सिंह ने उनके ख़िलाफ़ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है. बेशक, लीडर ऑफ द हाउस (नेता, सदन) अरुण जेटली ने स्पष्ट रूप से संसद से कहा है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस घटना से पीड़ा हुई है, उनकी पार्टी को पीड़ा हुई है और वे यहां सुनिश्चित करेंगे कि आगे ऐसा न हो. भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से दयाशंकर सिंह का निष्कासन भी सही दिशा में उठाया गया एक कदम है. जैसा कि मैं पिछले दो-तीन बार से अपने कॉलम में लिख रहा हूं, अगर भाजपा लंबे समय तक एक सत्तारूढ़ पार्टी बने रहना चाहती है, तो उसे आरएसएस, विहिप, बजरंग दल आदि को संयमित और नियंत्रित कर रखना होगा. भले ये संगठन चाहें तो अपने हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ावा देते रहें, लेकिन शासन के वातावरण को दूषित करने की कोशिश और अभद्र भाषा के प्रयोग से भाजपा को मदद नहीं मिलने वाली है. यही वो बिंदु है, जहां भाजपा के मुक़ाबले कांग्रेस बेहतर स्थिति में नज़र आती थी. क्षेत्रीय पार्टियों के विपरीत, जैसे जनता दल मुख्य रूप से पिछड़ा, बसपा दलित वर्ग की पार्टी है, वहीं कांग्रेस समाज के हर वर्ग की पार्टी रही है. ऐसा स्वाभाविक है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में लड़ी गई थी और संविधान में जो बातें हैं, वो अधिकतर 1947 से पहले कांग्रेस के प्रस्ताव में लाई जा चुकी थीं.

उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान मायावती के ख़िलाफ़ दिया है. दयाशंकर सिंह ने उनके ख़िलाफ़ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है. बेशक, लीडर ऑफ द हाउस (नेता, सदन) अरुण जेटली ने स्पष्ट रूप से संसद से कहा है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस घटना से पीड़ा हुई है, उनकी पार्टी को पीड़ा हुई है और वे यहां सुनिश्चित करेंगे कि आगे ऐसा न हो. भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से दयाशंकर सिंह का निष्कासन भी सही दिशा में उठाया गया एक कदम है. जैसा कि मैं पिछले दो-तीन बार से अपने कॉलम में लिख रहा हूं, अगर भाजपा लंबे समय तक एक सत्तारूढ़ पार्टी बने रहना चाहती है, तो उसे आरएसएस, विहिप, बजरंग दल आदि को संयमित और नियंत्रित कर रखना होगा. भले ये संगठन चाहें तो अपने हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ावा देते रहें, लेकिन शासन के वातावरण को दूषित करने की कोशिश और अभद्र भाषा के प्रयोग से भाजपा को मदद नहीं मिलने वाली है. यही वो बिंदु है, जहां भाजपा के मुक़ाबले कांग्रेस बेहतर स्थिति में नज़र आती थी. क्षेत्रीय पार्टियों के विपरीत, जैसे जनता दल मुख्य रूप से पिछड़ा, बसपा दलित वर्ग की पार्टी है, वहीं कांग्रेस समाज के हर वर्ग की पार्टी रही है. ऐसा स्वाभाविक है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में लड़ी गई थी और संविधान में जो बातें हैं, वो अधिकतर 1947 से पहले कांग्रेस के प्रस्ताव में लाई जा चुकी थीं.

भाजपा का यह कहना बिल्कुल सही था कि हम आपको एक वैकल्पिक शासन देंगे और संप्रग सरकार के 10 साल के शासन के बाद लोगों ने भाजपा को सत्ता सौंप दिया. लेकिन भाजपा को सावधान रहना चाहिए. भाजपा को यह नहीं कहना चाहिए कि लोगों ने संविधान या स्वतंत्रता संग्राम की नीतियों को नकार दिया है. ऐसी बातें सच्चाई से कोसों दूर हैं. हां, लोग बेहतर शासन चाहते हैं. मुद्रास्फीति की बढ़ती दर से सबसे ज़्यादा ग़रीब आदमी परेशान है. भ्रष्टाचार से देश में एक बुरा वातावरण बनता है. शायद इन्हीं दो वजहों से भाजपा को 282 सीटें प्राप्त हुई थीं. लेकिन एक बार जब आप शासन में आ जाते हैं तब आप चुनावी मोड में नहीं रह सकते हैं. अब आप सरकार चला रहे हैं और जब आप गंभीरता से शासन करते हैं तब आपके पास सीमित विकल्प होते हैं. भारत जैसे एक जटिल देश में शायद थोड़ी झिझक के साथ आप यह मानेंगे कि कांग्रेस ने इस स्थिति में भी सबसे बेहतर विकल्प का प्रयोग किया. बेशक कोई भी काम और बेहतर तरीके से किया जा सकता है और भाजपा को कांग्रेस से बेहतर करना है. यही एक रास्ता है, जिसके जरिए भाजपा लोगों को समझा सकती है कि वे सिर्फ बेहतर शासन देने आए हैं, न कि केवल हल्ला-हंगामा मचाने. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

शराबबंदी पूरे देश में लागू हो

कवर स्टोरी-मैं आ रहा हूं (18 जुलाई-24 जुलाई 2016) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू कर देश की जनता खासकर महिलाओं के दिल में विशेष स्थान बना लिया है. शराबबंदी लागू होने से बिहार की जनता खुश है और वह इसके लिए नीतीश कुमार का आभार प्रकट करती है. नीतीश कुमार ने न केवल शराब की वजह से तबाह हो रही लोगों की जिंदगियों को बचाया है, बल्कि लोगों के घरों में खुशियां भर दी हैं. नीतीश कुमार ने बिल्कुल सही कहा है कि लोग जो पैसा शराब पर खर्च कर रहे थे, अब वो पैसा खाने, कपड़े, बच्चों को पढ़ाने और दूसरी जरूरतों पर खर्च करेंगे. नीतीश कुमार ने पूरे देश में शराबबंदी लागू करने का जो बीड़ा उठाया है उसमें उनके साथ पूरे देश की जनता है. उत्तर प्रदेश सरकार को भी चाहिए कि नीतीश कुमार से सीख लेते हुए प्रदेश में शराबबंदी लागू करे. शराब से नौजवानों, छात्रों और लोगों का पारिवारिक जीवन तबाह हो रहा है. इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में शराबबंदी लागू करें.

-अशोक सिंह, *देवरिया, उत्तर प्रदेश.*

भाजपा विकास के एजेंडे से भटक गई है

आलेख-विधानसभा चुनाव में उग्र हिंदूवादी धारा पर लौटेगी भाजपा!, महज संयोग नहीं है योगी से योग (18 जुलाई-24 जुलाई 2016) शीर्षक से लिखे अपने लेख में प्रभात रंजन दीन ने कहा है कि कुछ दिन पहले तक उग्र हिंदूवादी रवैये से दूर रहने की बातें कहने वाले भाजपा नेता फिर से कट्टर लाइन पर आते दिख रहे हैं. यह बिल्कुल सही है कि भाजपा अपने उग्र हिंदूवादी धारा पर लौटेगी. कैराना जैसे मुद्दे को भाजपा नेताओं द्वारा जोर-शोर से उठाया जाना और अमित शाह का ये कहना कि योगी का नाम लेने मात्र से कार्यकर्ताओं में रोमांच होने लगता है, इसका यह साफ संकेत है कि भाजपा उग्र हिन्दूवादी धारा पर लौटेगी. भाजपा चाहती है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण हो जिसका फायदा पार्टी को मिले. लेकिन भाजपा अपने विकास के एजेंडे से भटकती है तो उसको नुकसान ही होगा, क्योंकि अब जनता को बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए. भाजपा को यह बात समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन उग्र हिंदूवादी धारा पर लौटने से लगता है कि भाजपा अपने विकास के एजेंडे से भटक गई है.

-अजय तिवारी, *कानपुर, उत्तर प्रदेश.*

खुशी के इंतजार में जनता

आलेख-आगे बढ़ने के लिए नीतियां बदलने की जरूरत (18 जुलाई-24 जुलाई 2016) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. कमल मोरारका ने बिल्कुल सही कहा है कि सरकार का असल प्रदर्शन आर्थिक स्थिति को देखकर समझा जा सकता है. महंगाई अब भी उच्च स्तर पर है. दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं. आम आदमी परेशान है. सरकार इस सबसे कैसे निपटेगी, कोई नहीं जानता. मोदी सरकार को अपनी नीति बदलने की जरूरत है, क्योंकि सरकार बने दो साल से अधिक हो गए हैं और कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है. अगर हम महंगाई की बात करें, तो महंगाई कम होने की जगह बढ़ गई है. दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं और एक बार किसी चीज की कीमत बढ़ जा रही है, तो कम होने का नाम नहीं ले रही है. बेरोजगारी में कोई कमी नहीं आई और नौजवान नौकरी के लिए इधर-उधर धक्के खा रहे हैं. इसलिए मोदी सरकार को अपनी पुरानी नीति बदलनी चाहिए, जिससे आम आदमी के जीवन में खुशी आ सके.

-विक्रांत यादव, *भागलपुर, बिहार.*

नशे के खिलाफ अभियान

जब तोप मुकाबिल हो-नशे के खिलाफ जनता का शंखनाद है पंजाब चुनाव (18 जुलाई-24 जुलाई 2016) पढ़ा. संतोष भारतीय ने अपने संपादकीय में बिल्कुल सही कहा कि पंजाब का यह चुनाव दरअसल प्रशासनिक व्यवस्था और नशाखोरी के खिलाफ जिसमें शराब, चरस या जितने भी प्रकार के ड्रग्स होते हैं, उनके खिलाफ जनता का एक शंखनाद है. पंजाब विधानसभा चुनाव में नशाखोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अभियान छेड़ा हुआ है. पंजाब में ड्रग्स के कारोबार में प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा लगा हुआ है. सरकार को इसके बारे में जानकारी है, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई करने के बजाए पंजाब की अकाली और भाजपा सरकार ने आंखें बंद कर रखी हैं. पंजाब में नौजवान तरह-तरह के नशे की गिरफ्त में हैं. पंजाब में एक बड़े मंत्री के ऊपर भी आरोप था कि वह ड्रग्स के कारोबार में लिप्त है. पंजाब के लोगों में इसे लेकर गुस्सा है और पंजाब चुनाव सच में नशे के खिलाफ जनता का शंखनाद होगा.

-हरनीत सिंह भसीन, *रोहिणी, दिल्ली.*

पंजाब में किसकी होगी सरकार!

मनीष कुमार ने अपने आलेख आप की आंधी में उड़ता पंजाब (18 जुलाई-24 जुलाई 2016) में सही कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभरी है. पंजाब में शिरोमणी अकाली दल-भाजपा सरकार के खिलाफ माहौल है जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को होता दिख रहा है. लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सबसे अधिक फायदा पंजाब में हुआ था, जहां से उसने चार सीटें हासिल की थीं. नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा और भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा को जबरदस्त झटका दिया है और उनके आम आदमी पार्टी में जाने की संभावना है. आम आदमी पार्टी उन्हें पंजाब में अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी में आने के लिए यही शर्त रखी थी. पंजाब में आम आदमी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है.

-पुष्कर भारद्वाज, *द्वारका, नई दिल्ली.*

नीतीश का सराहनीय कदम

मैं चौथी दुनिया राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र का नियमित पाठक हूं और मुझे इसका हर सप्ताह बेसब्री से इंतजार रहता है. चौथी दुनिया में प्रकाशित खबरें तथ्यपरक और प्रभावित करने वाली होती हैं. कवर स्टोरी मैं आ रहा हूं (18 जुलाई- 24 जुलाई 2016) में नीतीश कुमार ने सही कहा है कि अगर सरकार को शराब के व्यापार से पांच हजार करोड़ रुपये की आमदनी होती थी तो इसका मतलब था कि लोग कम से कम दस हजार करोड़ रुपये की शराब पी रहे थे. शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार में हर साल दस हजार करोड़ रुपया बचेगा. नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू कर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जिसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है. देश के जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं लागू है, वहां की राज्य सरकारों को भी नीतीश कुमार की तरह कड़ा कदम उठाते हुए शराबबंदी लागू करनी चाहिए.

-रूपेश गुप्ता, *बक्सर, बिहार.*

केजरीवाल का जनता से संवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की तर्ज पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी देश की राजधानी दिल्ली में एक नया कार्यक्रम टॉक टू एके शुरू किया है. केजरीवाल ने जनता से संवाद करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया है. यह एक अच्छी पहल है. अब यह देखना है कि केजरीवाल इसके माध्यम से जनता से संवाद करते हैं या इसका इस्तेमाल केंद्र सरकार पर निशाना साधने के लिए करते हैं. जैसा कि केजरीवाल ने इस कार्यक्रम की शुरुआत अपनी सरकार की सफलता और मोदी सरकार पर निशाना साधने से की. इस बार उन्होंने यहां तक कह दिया कि दिल्ली और केंद्र सरकार का रिश्ता भारत और पाकिस्तान की तरह है. केजरीवाल को इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता से संवाद करना चाहिए. उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और उसे दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए. जिससे जनता के बीच सरकार के प्रति अच्छा संदेश जाए.

-रवि कुमार, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

अंधराष्ट्रवाद से बढ़ रहा है लोकतंत्र के लिए ख़तरा

चाहे कोई भी विषय हो, देश का एक छोटा लेकिन ख़तरनाक तबक़ा फेसबुक का सहारा लेकर नफ़रत फैलाने का काम तेज़ी से कर रहा है. हर चीज़ छद्म राष्ट्रवाद से जोड़ी जा रही है और देश के लोगों में हिंदू–मुसलमान के बीच बंटवारा करने, नफ़रत फैलाने का सशक्त प्रयास किया जा रहा है. जैसे यह छोटा ग्रुप अंधराष्ट्रवाद के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही मुस्लिम समुदाय का एक छोटा तबक़ा ठीक वैसी ही हरकतें कर रहा है. न हिंदू और न मुस्लिम समाज इन घटनाओं के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है और न चिंतित हो रहा है, पर देश एक ख़तरनाक मुहाने की तरफ तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है.

देश का मतलब अंधराष्ट्रवाद हो गया है, चाहे वो कश्मीर के बहाने हो, चाहे वंदे मातरम या फिर लव जिहाद के बहाने. अंधराष्ट्रवाद का मतलब ही देश है, हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है. ये लोग किसानों की आत्महत्या, बेरोज़गारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य के सवालों को देश का सवाल नहीं मानते. इन सवालों पर राजनीतिक दल भी बात नहीं कर रहे हैं. इससे लगता है कि वो पीढ़ी जिसे हम देश की रहनुमाई करने वाली पीढ़ी मानते थे, पूर्णतया समाप्त हो गई है. हम बात चाहे जवाहरलाल नेहरू की करें, इंदिरा गांधी की, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, ज्योति बसु, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर लालकृष्ण आडवाणी की. अब इनकी परंपराएं भी इनके दलों में नहीं बची हैं.

जो तबक़ा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अंधराष्ट्रवाद की वकालत कर रहा है, उसके लिए किसान की आत्महत्या या किसान की समस्या कोई अस्तित्व नहीं रखती. सरकार के बीच के लोग किसानों की आत्महत्या का मजाक़ उड़ा रहे हैं. देश के कृषि मंत्री किसानों की आत्महत्या को अतिसाधारण शब्दों में लेते हैं और वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूत–प्रेतों की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसे कहते ज़रा भी नहीं शर्माते हैं. संसद के दोनों सदन किसानों की आत्महत्या पर एक दिन भी ख़ामोश नहीं होते. संसद के दोनों सदन एक दिन भी खेती के समाप्त होने की प्रक्रिया पर बात नहीं करते. किसान, बेरोज़गारी, महंगाई और भ्रष्टाचार की समस्या जैसे सवाल अब संसद और सांसदों को परेशान नहीं करते.

> देश का मतलब अंधराष्ट्रवाद हो गया है, चाहे वो कश्मीर के बहाने हो, चाहे वंदे मातरम या फिर लव जिहाद के बहाने. अंधराष्ट्रवाद का मतलब ही देश है, हमें ये समझाने की कोशिश हो रही है. ये लोग किसानों की आत्महत्या, बेरोज़गारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य के सवालों को देश का सवाल नहीं मानते. इन सवालों पर राजनीतिक दल भी बात नहीं कर रहे हैं. इससे लगता है कि वो पीढ़ी जिसे हम देश की रहनुमाई करने वाली पीढ़ी मानते थे, पूर्णतया समाप्त हो गई है. हम बात चाहे जवाहरलाल नेहरू की करें, इंदिरा गांधी की, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, ज्योति बसु, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर लालकृष्ण आडवाणी की. अब इनकी परंपराएं भी इनके दलों में नहीं बची हैं.

संसद में सांसद देश के राजनीतिक दलों से आते हैं, लेकिन राजनीतिक दल पूरी तरह से असंवेदनहीन हो गए हैं. अब उनके बीच देश की समस्याओं को लेकर बातचीत नहीं होती. मुझे याद नहीं है कि देश के सवालों पर किन्हीं दो या तीन या चार या पांच राजनीतिक दलों के बीच पिछले वर्षों में कोई चर्चा हुई हो. उस स्थिति को देश का नाम लेने वाले राजनेता कैसे अनदेखा कर रहे हैं. उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि दुनिया के अन्य देशों में वहां की राजनीति के विरुद्ध जिस तरह नकारात्मक गुस्सा फूटता है, वैसा गुस्सा भारत में भी फूट सकता है. उस समय क़ानून धराशायी हो जाता है और गुस्सा सिर्फ उनके प्रति फूटता है जो जाने या अनजाने उस स्थिति के लिए ज़िम्मेदार होते हैं.

इसलिए देश में एक नई तरह की राजनीति पैदा हुई है, जिसके सामने कोई विचारधारा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है. लेकिन वो समस्याओं के लिए कुछ व्यक्तियों या कुछ दलों को ज़िम्मेदार बनाती है और उसी को अपनी विचारधारा के रूप में प्रकट करती है. इससे बड़ा विचारधारा का कोई मखौल नहीं हो सकता. जब हम विचारधारा की बात करते हैं, तो हम उन नियमों, उन सिद्धांतों की बात करते हैं, जिनके आधार पर कोई दल शासन करने का अधिकार जनता से लेता है. लेकिन अगर महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, समानता, किसान को उपज का सही लाभ, हर व्यक्ति को जीने का, पढ़ाई का और स्वास्थ्य का अधिकार मिले–जब ये सिद्धांत सामने नहीं होते, तो फिर वैसे नकारात्मक फ़ैसले सामने होते हैं, जिनका विरोध करने के नाम पर लोग सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं और मुझे लगता है कि ये स्थिति अंततः अराजकता और अधिनायकवाद में परिवर्तित होती है. इसलिए मुझे लगता है कि देश के राजनेताओं को सोचने और समझने की ज़रूरत है.

देश के बुनियादी सवाल चाहे वो विद्यार्थियों, किसानों व लोगों की जीवनशैली से जुड़े हों, वे महत्वपूर्ण हैं बनाम अंधराष्ट्रवाद के. ये अलग बात है कि बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने का सबसे आसान रास्ता अंधराष्ट्रवाद है, जिसके लिए अब कुछ टेलीविज़न चैनल खुल्लम–खुल्ला हिस्सेदार बन गए हैं और सोशल मीडिया पर अंधराष्ट्रवाद की इन दिनों बाढ़ आई हुई है. मुझे लगता है कि हमारे देश में लोकतंत्र के ख़िलाफ़ अगर कोई सबसे सशक्त साज़िश हो रही है, वो सोशल मीडिया के जरिए हो रही है. इस पर वे लोग ख़ामोश हैं जो लोकतंत्र को दुनिया की सबसे सशक्त राजनीतिक प्रणाली मानते हैं, जिनका विश्वास है कि लोकतंत्र से ही विकास हो सकता है, पर ये लोग हार रहे हैं और वे लोग जीत रहे हैं जो मानते हैं कि लोकतंत्र के ज़रिए विकास नहीं हो सकता. इसमें वे भी हैं जो खुलेआम हथियार चलाते हैं और वे भी हैं जो खुलेआम हथियार की तरह लोगों के ज़ेहन को प्रदूषित कर रहे हैं.

इसमें सबसे ज़्यादा दोषी मीडिया है, जो इस स्थिति का हिस्सेदार बन रहा है. जिस तरह राजनीतिक दलों में आपस में बातचीत नहीं होती, वैसे ही मीडिया में भी आपस में बातचीत नहीं होती है. राजनीतिक दलों से ज़्यादा ख़तरनाक मीडिया का बंटवारा, मीडिया की चुप्पी और मीडिया की समझ है. क्या हम लोकतंत्र को समाप्त करने में हिस्सेदार बनना ज़्यादा अच्छा समझते हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

सत्ता में बने रहने की कला में माहिर है कंज़र्वेटिव पार्टी

राजनीतिक दल आम तौर पर विचारधारा पर आधारित होते हैं, चाहे वो ब्रिटिश लेबर पार्टी की तरह वामपंथी हों या फिर दक्षिणपंथी. सभी राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता हासिल करना होता है ताकि वे अपना विज़न लागू कर सकें. कंजर्वेटिव पार्टी दुनिया के सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से एक है. इसकी जड़ें 1688 की रक्तहीन क्रांति से जुड़ी हैं. हालांकि बदलाव विरोधी होने के कारण कंजर्वेटिव पार्टी पराजित पक्ष के साथ थी, लेकिन उसने खुद को हमेशा सत्ता संघर्ष में एक पक्ष के रूप में कायम रखा.

कंजर्वेटिव पार्टी ने पिछली कई सदियों तक पुरानी व्यवस्था को बरकरार रखने की वकालत की और किसी भी त्वरित परिवर्तन के विचार का विरोध किया. लेकिन उसे यह एहसास हो गया था कि नए परिवर्तन को ज्यादा समय तक नहीं रोका जा सकता है. एक राजनीतिक दल को सत्ता में बने रहने के लिए खुद को हालात के अनुकूल बदलना पड़ता है. भले ही वे बदलाव क्रांतिकारी न हों, लेकिन पार्टी को समय के मुताबिक खुद को ढालना पड़ता है.

बहरहाल, कंजर्वेटिव पार्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सत्ता में बने रहने की कला में माहिर है. यूरोपीय संघ को लेकर पार्टी में पिछले 30 साल से मतभेद हैं. पार्टी में यह आंतरिक मतभेद प्रधानमंत्री जॉन मेजर के पतन और उनके बाद होने वाले लगातार तीन चुनावों में हार का कारण बना. इस अवधि में पार्टी नेतृत्व में चार बार बदलाव किये गए. वर्ष 2010 में 13 साल बाद एक गठबंधन सरकार के साथ पार्टी सत्ता में आई. 2015 के चुनाव में उसे पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन पार्टी में आंतरिक विवाद जारी रहा. लिहाज़ा डेविड कैमरन ने यह सोच कर जनमत कराया कि ऐसा करने से यूरोपीय संघ को लेकर ब्रिटेन में खड़ा विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया. जनमत संग्रह के नतीजों ने कैमरन के कैरियर को समाप्त कर दिया. कल तक जिस पद पर उनका मज़बूत नियंत्रण था, उसे उन्हें छोड़ना पड़ा. अपने कार्यकाल के अंतिम दिन वे संसद गए और प्रधानमंत्री को संबोधित सवालों के जवाब में उन्होंने साबित कर दिया कि वे संसदीय राजनीति में कितने निपुण हैं.

ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को बहुत तेजी से बदला जा सकता है. 24 जून को जनमत संग्रह के नतीजे घोषित हुए, उसके फ़ौरन बाद कैमरन ने घोषणा कर दी कि जैसे ही अगला प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा वे त्यागपत्र दे देंगे. प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई. इस प्रक्रिया में कुल पांच उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया. कंजर्वेटिव संसदीय दल ने दो चरणों में मतदान किया. पहले चरण के मतदान के बाद पांचवें और चौथे नम्बर के उम्मीदवार चुनाव मैदान से बाहर हो गए. अगले सप्ताह दूसरे चरण के मतदान में बाक़ी तीन उम्मीदवारों में से केवल दो ही मुकाबले में रह गए थे. पार्टी के साधारण सदस्यों के पोस्टल बैलट के जरिए शेष दो महिला उम्मीदवारों में से किसी एक को अपना नेता चुनना था. पूरी प्रक्रिया में कुल आठ सप्ताह का समय लग जाता. इसी बीच एक उम्मीदवार ने अपने एक वरिष्ठ प्रतिद्वंद्वी को आहत करने वाला व्यक्तिगत बयान देने की गंभीर गलती की, जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें उम्मीदवारी छोड़ने की सलाह दी गई. लिहाज़ा उस उम्मीदवार के मुक़ाबले से बाहर जाने के बाद चुनाव कराने की आवश्यकता ही नहीं रही. थेरेसा मे को विजेता घोषित कर दिया गया.

> वर्ष 2010 में 13 साल बाद एक गठबंधन सरकार के साथ पार्टी सत्ता में आई. 2015 के चुनाव में उसे पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन पार्टी में आंतरिक विवाद जारी रहा. लिहाज़ा डेविड कैमरन ने यह सोच कर जनमत कराया कि ऐसा करने से यूरोपीय संघ को लेकर ब्रिटेन में खड़ा विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया.

11 जुलाई को, जनमत संग्रह के 18 दिनों के बाद, एक प्रधानमंत्री ने दूसरे प्रधानमंत्री की जगह ले ली. डेविड कैमरन अपने कार्यालय की सील वापस करने के लिए महारानी के महल गए. इसके फौरन बाद नई प्रधानमंत्री गईं, जिन्होंने महारानी का हाथ चूमा. मीडिया और आम जनता 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एकत्र थे. निवर्तमान नेता, उनकी पत्नी और बच्चों ने छह साल से वहां रह रहे निवास स्थान को छोड़ दिया और नई नेता अपने पति के साथ वहां रहने के लिए आ गईं.

इस बीच लेबर पार्टी दो हिस्सों में बंटी दिख रही है. एक तरफ वे लोग हैं जो परिवर्तन चाहते हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो चुनाव जीतना चाहते हैं. लेबर पार्टी एकदम शिथिल नज़र आ रही है और हो सकता है आने वाले दिनों में यह दो हिस्सों में बंट जाए.

यहां भारत के लिए भी एक सबक है. भारत की सबसे पुरानी पार्टी (कांग्रेस) वंशवाद के कारण गतिहीन हो गई है और सत्ता में वापस नहीं आ सकती. एक विचारधारा वाली पार्टी को सावधान रहने की जरूरत होती है और ये पार्टियां विचारधारा को सत्ता की राह में बाधा नहीं बनने देती हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

बाढ़ की आहट से कहीं ख़ुशी, कहीं ग़म

प्रत्येक वर्ष कोसी में आने वाली बाढ़ की मार झेलते आ रहे लोगों में अभी से बाढ़ को लेकर दहशत है और लोगों ने सुरक्षित स्थानों की तलाश शुरू कर दी है. प्रशासनिक स्तर पर भी दावा किया जा रहा है कि संभावित बाढ़ के मद्देनजर न केवल सुरक्षित स्थान तलाश लिए गए हैं, बल्कि जरूरी सामानों का भंडारण भी कर लिया गया है. मौसम विभाग के द्वारा इस बार भारी बारिश की आशंका जताई जाने के बाद उत्तर बिहार के लोगों के मन में बाढ़ की तबाही का डर समाया हुआ है. गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक एवं कोसी सहित कई नदियों का जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है. इसके बावजूद दियारा के लोगों के साथ-साथ निचले इलाकों के लोगों को अपना-अपना आशियाना त्यागकर सुरक्षित जगह तलाशनी पड़ रही है, क्योंकि यह इलाका धीरे-धीरे बाढ़ की चपेट में आता जा रहा है.

राजेश सिन्हा

तमाम प्रशासनिक दावों के बाद भी बिहार में बाढ़ से पूर्व की तैयारियां अधूरी हैं. तटबंधों की मरम्मत के नाम पर केवल खानापूर्ति हुई है और तटबंधों की सुरक्षा के लिए नदियों में बोल्डर गिराने के नाम पर केवल अपनी जेबें भरी गईं. बाढ़ के मद्देनजर शासन-प्रशासन को जो तैयारी करनी चाहिए थी वो तैयारी नजर नहीं आ रही है. भीषण बाढ़ की वजह से कमजोर तटबंध टूटते हैं, तो कितनी जिंदगियां तबाह होगीं इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है. बिहार अभी भयानक बाढ़ की चपेट में तो नहीं है, लेकिन नेपाल के साथ-साथ बिहार में हो रही रिकॉर्ड बारिश की वजह से गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, घाघरा तथा महानंदा के साथ-साथ अन्य नदियां उफान मार रही हैं. अब धीरे-धीरे उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी शहरों में बाढ़ का खतरा नहीं है. सुपौल, मधुबनी एवं मोतिहारी के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है जिसकी वजह से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है.

प्रत्येक वर्ष कोसी में आने वाली बाढ़ की मार झेलते आ रहे लोगों में अभी से बाढ़ को लेकर दहशत है और लोगों ने सुरक्षित स्थानों की तलाश शुरू कर दी है. प्रशासनिक स्तर पर भी संभावित बाढ़ के मद्देनजर न केवल सुरक्षित स्थान तलाश लिए गए हैं, बल्कि जरूरी सामानों का भंडारण भी कर लिया गया है. मौसम विभाग के द्वारा इस बार भारी बारिश की आशंका जताई जाने के बाद उत्तर बिहार के लोगों के मन में बाढ़ की तबाही का डर समाया हुआ है. गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक एवं कोसी सहित नदियों का जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है. इसके बावजूद दियारा के लोगों के साथ-साथ निचले इलाकों के लोगों को अपना-अपना आशियाना त्यागकर सुरक्षित स्थान तलाशनी पड़ रही है, क्योंकि यह इलाका धीरे-धीरे बाढ़ की चपेट में आता जा रहा है. हालांकि यह कोई नई बात नहीं है. नदियों के जलस्तर में वृद्धि की वजह से दियारा व निचले इलाके के लोगों का इस बार समय से पहले आशियाना छिन गया है, बल्कि सैकड़ों लोगों के सामने रोजी-रोटी की समस्या भी उतपन्न होने गई है. लेकिन वहीं दियारा में बाढ़ का पानी आने की वजह से मछुआरों की जिंदगी में मानों बहार आ गई है. दूसरी जगहों पर पलायन कर चुके मछुआरे भी अब वापस लौट रहे हैं. वापस आए मछुआरों का कहना है कि कई वर्षों से गंगा समेत अन्य नदियों में बाढ़ न आने की वजह से इन लोगों के परंपरागत पेशे पर ग्रहण लग गया था. सहरसा जिले के मनोज सहनी तथा खगड़िया जिले की पुष्पा सहनी का कहना है कि कई वर्षों से गंगा मैया शायद नाराज थीं, जिसकी वजह से मछुआरों की जिंदगी रेंगती हुई नजर आ रही थी. मछुआरों को परम्परागत पेशे से मुंह मोड़कर किसी दूसरे धंधे को अपनाना पड़ा था. बेगूसराय जिले के कारे सहनी का कहना है कि नाराज गंगा मईया को मनाने में अबकी बार मछुआरे फिर सफल हो गए. बार-बार नदियों में बाढ़ आने की वजह से मछुआरे खुशहाल थे, लेकिन कई वर्षों से नदियों का पेट खाली रह जाने की वजह से इन लोगों के मछली व्यवसाय पर बुरा असर पड़ने लगा था. सुपौल जिले के अरविंद सहनी कहते हैं कि कई वर्षों से गंगा, कोसी सहित अन्य नदियों में बाढ़ नहीं आने की वजह से इन लोगों के सामने रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई थी. लेकिन इस बार दिन फिरने की आस में मछुआरे समाज के लोग अपने इष्ट की आराधना में लगे हैं. मछुआरों की स्थिति-परिस्थिति का समर्थन करते हुए बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ के पूर्व निदेशक नरेश सहनी का कहना है कि बीते वर्ष 2007 के बाद बिहार के कई जिलों में सूखे की स्थिति पैदा हो गई थी. नजीजतन सूखे की मार से तंग आ चुके मछुआरों के पलायन का सिलसिला शुरू हो गया. मछुआरों के द्वारा परंपरागत पेशे को छोड़कर किसी दूसरे कार्य में लग जाने की वजह से बिहार का मछली व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो गया. आंध्रप्रदेश की मछलियां बिहार के मछली बाजार पर राज करने लगीं. मछुआरों के नेता प्रभुदयाल सहनी कहते हैं कि सूखे की मार झेल रहे मछुआरे समाज के अधिसंख्य लोग कर्नाटक जाकर पत्थर उद्योग से जुड़ गए थे. प्रभुदयाल 2007 में आई बाढ़ का जिक्र करते हुए कहते हैं कि खगड़िया जिले का महज 113 पंचायत ही प्रभावित हुआ था, लेकिन नौ हजार मीट्रिक टन से अधिक मछलियों का उत्पादन हुआ था. इसके बाद से कभी भी मछली उत्पादन के मामले में यह जिला छह हजार हजार मीट्रिक टन से अधिक मछली उत्पादन का गवाह नहीं बन सका, क्योंकि इसके बाद बाढ़ की बाट जोहते ही मछुआरे रह गए और बाढ़ का दर्शन तक संभव नहीं हो सका. इस वर्ष शुरूआती समय में ही बाढ़ आ जाने से अत्यधिक मछलियों का उत्पादन होना तय है. सहरसा जिले के जयलाल सहनी की मानें तो नदियों में बाढ़ आने के बाद अब आंध्रप्रदेश की मछलियों के व्यवसाय पर जहां प्रतिकूल असर पड़ने लगा है वहीं मछली के शौकीनों को देशी मछली भी नसीब होने लगी है.

अजयलाल आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि सहरसा जिले के आस-पास से प्रवाहित होने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ने से देशी मछलियों का उत्पादन बढ़ा है. नतीजतन बाढ़ आने के पूर्व तक आंध्रप्रदेश से चालीस-चालीस किलो की दो सौ मछली पेटियां सहरसा पहुंचती थीं, तो वहीं अभी चालीस से पचास पेटियां ही पहुंच पा रही हैं. पहले लोगों को देशी मछलियां देखने तक को नहीं मिल पाती थीं. अब देशी मछलियां कम कीमत पर ही लोगों को उपलब्ध हो जा रही हैं. इस तरह की स्थिति से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि आंध्रप्रदेश की मछलियों का बाजार बाढ़ नहीं आने की वजह से बिहार में भी किस तरह फैल जाता है. खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा तथा बेगूसराय के मत्स्य पदाधिकारियों का भी मानना है कि इस वर्ष समय से पूर्व मौसम का दस्तक देना और नदियों का बढ़ता जलस्तर मछुआरों की जिंदगी के लिए आकाश कुसुम साबित होगा और मछलियों के उत्पादन में न केवल वृद्धि होगी बल्कि मछलियों के मामले में आंध्रप्रदेश पर निर्भरता भी कम होगी. बहरहाल, बिहार में बाढ़ का नजारा देखकर भले ही मछुआरों की जिंदगी में बहार आने का संकेत मिल रहा हो लेकिन अन्य लोगों के लिए यह तबाही का मंजर है.■

feedback@chauthiduniya.com

बाढ़ में सांपों का ख़ौफ़, सपेरों की चांदी

गीता कुमार

बिहार में बाढ़ की आहट पूरी तरह सुनाई दे रही है, विभिन्न जिलों में नाग के साथ-साथ अन्य प्रजाति की सांपों का विचरण शुरू हो गया है. कहने को तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सर्पदंश के शिकार लोगों के लिए दवा का भंडारण कर लिया गया है, लेकिव बाढ़ के पानी में घिरे होने की वजह से लोग झाड़-फूंक पर ही भरोसा कर किसी तरह जिंदगी काटने को विवश हैं. बाढ़ के दौरान किसी की सर्पदंश की वजह से मौत होने की खबर तो अभी नहीं मिल रही है, लेकिन विभिन्न जिलों के गांव में नाग, करैत, गेंहुअन सहित अन्य प्रजाति के सांपों का डर लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा है. ग्रामीणों का कहना है कि गंगा तथा कोसी सहित अन्य नदियों के जलस्तर में बृद्धि होने की वजह से जहां लोगों का आशियाना छिन गया है, तो वहीं सांप के साथ-साथ अन्य जीव भी जान बचाने के लिए इधर-उधर शरण ले रहे हैं. ऐसे में अगर सांप का डर लोगों के मन में है, तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए. वैसे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सर्पदंश के शिकार लोगों को तुरत राहत मुहैया कराने के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए. ग्रामीणों की अगर मानें तो इन लागों के द्वारा सर्पदंश के शिकार लोगों का इलाज वर्षों से झाड़-फूंक के सहारे ही किया जाता रहा है. इधर अंधविश्वासी समाज को ताकीद करते हुए युवाशक्ति के प्रदेश अध्यक्ष नागेन्द्र सिंह त्यागी का कहना है कि सर्पदंश के शिकार लोगों को झाड़-फूंक के बजाय चिकित्सक के पास जाना चाहिए. त्यागी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि इसके लिए जिला प्रशासन के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए. दूसरी तरफ खगड़िया के सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार सिंह का कहना है कि बाढ़ के पूर्व ही सर्पदंश की दवा का पर्याप्त मात्रा में भंडारण कर लिया गया है. सर्पदंश के शिकार लोगों को झाड़-फूंक के चक्कर में न पड़कर अविलंब चिकित्सकों के पास ले जाना चाहिए.■

www.iiher.org,
Mob. : 9386745004, 9204791696
Email : anilsulabh6@gmail.com

INDIAN INSTITUTE OF HEALTH EDUCATION & RESEARCH
Health Institute Rd, Beur (Near Central Jail), Patna -2.
(Recongnised by Govt. of Bihar, RCI, Govt. of India, IAP & ISPO)
AFFILIATED TO MAGADH UNIVERSITY, BODHGAYA

POST GRADUATE COURSES :

Name of Courses		Eligibility	Duration
MPT	Master of Physiotherapy	BPT	2yrs.
MOT	Master of Occupational Therapy	BOT	2yrs.
DEGREE COURSES			
BPT	Bachelor of Physiotherapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BOT	Bachelor of Occupational Therapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BPO	Bachelor of Prosthetic & Orthotic	I.Sc	4yrs.+6 Months of Internship
BASLP	Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology	I.Sc	3yrs.+1 year of Internship
BMLT	Bachelor of Medical Laboratory Technology	I.Sc	3yr.+6 Months of Internship
BMRIT	Bachelor of Radio Imaging Technology	I.Sc	3yrs.+6 Months of Internship
B.Ophth.	Bachelor of Ophthalmology	I.Sc	4yr.+6 Months of Internship
B.Ed.	(Special Education)	Graduate	1yr.
YEAR ABRIDGED DEGREE FOR DPT / DOT			
DIPLOMA COURSES :			
DPT	Diploma In Physiotherapy	I.Sc (Bio)	3yrs.+6 Month of Internship
D-X-Ray	Diploma In X-Ray Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DMLT	Diploma In Medical Laboratory Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DECG	Diploma In E.C.G.	I.Sc (Bio)	2yr.
DOTA	Diploma In O.T. Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DHM	Diploma In Hospital Management	Graduate	1yr.
CMD	Certificate In Medical Derssing	Matirc with Science & English	1yr.

ADMISSION OPEN

Form & Prospectus -
Can be obtained from the office against a payment of Rs. 500/- only by cash. Send a DD of Rs. 550/- only in the favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna, for postal delivery.

डॉ. अनिल सुलभ
निदेशक प्रमुख

ईम्पोर्टेड केमिकल से तैयार, लैब टेस्टेड
पेन्ट डिस्टेम्पर
कोई भी हो
वॉल पुट्टी केवल ईटालियन वॉल पुट्टी
Laboratory Tested
Please Compare Lab Report
Made from Imported Chemicals
ईटालियन
व्हाइट
वॉल पुट्टी
Slight Costly but Superior
लैब रिपोर्ट अवश्य चेक करें।
लैब रिपोर्ट हमारे सभी डीलर्स के यहां उपलब्ध है
प्रखण्ड स्तर या अपने क्षेत्र हेतु सप्लायर / डीलरशिप के लिए सम्पर्क करें।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com
सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाऐ
सीमेन्ट
कोई भी हो परन्तु
वाटरप्रूफिंग केमिकल सिर्फ
मिस्टर केमिस्ट
सीमेन्ट कोई भी हो लेकिन वाटरप्रूफिंग केमिकल मिस्टर केमिस्ट ही हो, क्योंकि मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग केमिकल ईम्पोर्टेड केमिकल से बनाया गया है, प्रत्येक पैक पर नम्बर युक्त होलोग्राम से नकल से पूरी तरह सुरक्षित १, ५, १०, २० एवं २०० लीटर होलोग्रामिक पैक में अब आपके यहां भी उपलब्ध। मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाए।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

चुनावी आस में भटक रहे राजनीतिक बेरोज़गार

बिहार में चुनावी पंच परिक्रमा खत्म होने के बाद थके-हारे राजनीतिक दल के नेताओं को अब अगले चुनावी मौसम का इंतजार है. विधान परिषद के स्नातक व स्थानीय निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा व बिहार विधानसभा चुनाव के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तक की भागदौड़ ने अब आखिरी रास्ते के रूप में अगले चुनावी सीजन तक मन मारकर रहने को मजबूर कर दिया है. धनबल, जातिबल व दलगत वोटों के अलावा अन्य विकल्पों के बूते जिसने बाजी मार ली, वे तो खुद को स्वघोषित जनसेवक का ताज लेकर चैन से हैं. लेकिन जिसने अपना सबकुछ खो कर भी चुनावी समर में मुंह की खाई है, उन्होंने अब अगली बारी की तैयारी में जमीन सूंघना शुरू कर दिया है. राजनीतिक बेरोजगारी से परेशान नेता अब किसी भी तरह से क्षेत्र में अपनी पहचान कायम करने में लगे हैं, तो कई नेताओं की जिले से पलायन की भी चर्चा जोरों पर है.

वाल्मीकि कुमार

बेरोज़गारी एक ऐसा शब्द है जिसके स्मरण मात्र से ही न जाने कितनी बातें हर किसी के मन में उठने लगती हैं. इस शब्द का प्रयोग वैसे शिक्षित व अशिक्षित लोगों के लिए किया जाता रहा है जो अपने और परिवार के जीवन-यापन के लिए एक अदद नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं, लेकिन अब यह शब्द केवल आम लोगों के लिए ही उपयुक्त नहीं रह गया है. लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव जीतकर सरकार में मौज करने वाले राजनीतिक दल के नेता भी इस श्रेणी में फिलहाल नजर आ रहे हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हैं. मगर वर्तमान में इनकी पहचान एक पूर्व प्रतिनिध तक ही सिमटकर रह गई है. अंतिम चरण में संपन्न पंचायत चुनाव के बाद अब इनकी नजर उन प्रदेशों पर टिक गई है, जहां अब चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है. किसको कहां और क्या हाथ लगता है, अभी यह कहना मुश्किल है. वैसे जाति व पार्टी के प्रचारक की पहचान चुनावी मौसम में हर वक्त होती रही है.

उत्तर बिहार के सीतामढ़ी जिले में वर्तमान में तकरीबन दो दर्जन नेता बेरोजगारी का दंष झेलने को मजबूर हैं. इनमें पूर्व सांसद, पूर्व विधायक से लेकर पूर्व विधान पार्षद तक शामिल हैं. अब तक के संपन्न चुनावों में इनकी भूमिका पर अगर नजर डाली जाई, तो बहुत कम ही हैं जो जिले की राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका को लेकर लोगों के बीच चर्चा में रहे हैं. मगर चुनाव समाप्त होने बाद इनकी सक्रियता भी मौन धारण करने लगी है. जिले की राजनीति में अपनी सक्रियता की कवायद करने वाले इन नेताओं के कार्यशैली पर एक नजर डालते हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव से पूर्व सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर अधिकांश यादव बिरादरी का कब्जा रहा. इनमें चार ऐसे पूर्व सांसद वर्तमान में मौजूद हैं जो जिले की राजनीति में अपनी पैठ कायम करने के लिए प्रयासरत हैं. इनमें पूर्व सांसद रामश्रेष्ठ खिरहर, नवल किशोर राय, सीताराम यादव व डॉ. अर्जुन राय शामिल हैं. पूर्व सांसद रामश्रेष्ठ खिरहर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से राजद में शामिल हुए थे. जबकि जिले के पुपरी अनुमंडल से राजनीति में आने वाले पूर्व सांसद नवल किशोर राय व सीताराम यादव के बीच राजनीतिक बर्चस्व की दावेदारी थमने का नाम नहीं ले रही है. गठबंधन की राजनीति की वजह से भले ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोलने से परहेज कर रहे हों, मगर दोनों नेताओं के बीच आंकड़ा हमेसा छत्तीस का ही रहा है. डॉ. अर्जुन राय की बात करें, तो उन्होंने मुजफ्फरपुर जिले के औराई विधानसभा सीट से राजनीति में प्रवेश किया और सूबे की सरकार में मंत्री बनकर अपनी पहचान कायम की और बाद में सीतामढ़ी संसदीय सीट से जीत हासिल की.

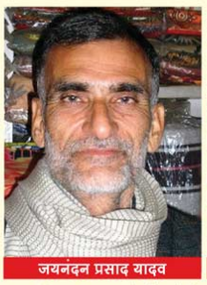

अर्जुन राय

डॉ. रामचंद्र पूर्वे

गुड्डी देवी

नगीना देवी

जयनंदन प्रसाद यादव

नवलकिशोर राय

सुनील कुमार पिंटू

सीताराम यादव

जबकि स्थानीय निकाय से विधान परिषद चुनाव में बाजी मार चुके दो पूर्व विधान पार्षदों में एक नेता ने जहां जिले की राजनीति में अब तक अपने को जीवंत बनाए रखा है, तो वहीं दूसरे को जिले के लोग वर्षों पहले भूल चुके हैं. इनमें एक पूर्व सांसद सीताराम यादव के पुत्र दिलीप कुमार यादव हैं जो चुनाव हारने के साथ ही जिले की राजनीति से खुद को अलग कर लिया. वहीं दूसरी ओर पूर्व विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद दलगत समर्थन नहीं मिलने के बाद भी विधानसभा चुनाव में बेलसंड सीट से चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक पहचान को बचाने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव में उनको सफलता नहीं मिली.

इनके अलावा सीतामढ़ी जिले के अलग-अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधत्व कर चुके तकरीबन डेढ़ दर्जन पूर्व विधायक भी गंभीर राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं. इनमें कई ऐसे भी हैं जो सूबे की सरकार में बतौर मंत्री कमान संभाल चुके हैं. इनमें रुन्नीसैदपुर के पूर्व विधायक नवल किशोर शाही व गुड्डी देवी, सुरसंड के नागेंद्र प्रसाद यादव, जयनंदन प्रसाद यादव, शाहिद अली खां व रवींद्र शाही, सोनबरसा से डॉ.रामचंद्र पूर्वे, रामजीवन प्रसाद व राम नरेश प्रसाद यादव, बथनाहा के सूर्यदेव राय व नगीना देवी, बेलसंड के संजय गुप्ता, मेजरगंज के गौरीशकर नागदंश, सीतामढ़ी के सुनील कुमार पिंटू व रीगा के मोतीलाल प्रसाद समेत अन्य शामिल हैं. इनमें कुछ तो ऐसे पूर्व प्रतिनिधि हैं जो क्षेत्र में जनता के बीच किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो चुनावी सीजन आने के साथ ही क्षेत्र में जनता के बीच प्रगट होते हैं.

> चुनावों में सेटिंग के खेल में माहिर कुछ नेताओं ने बेहतर प्रदर्शन कर अपनी राजनीतिक क्षमता का प्रदर्शन भी किया है. वहीं कुछ ने पर्दे के पीछे से ही अपने कुशल राजनीतिक अनुभव को आजमाया. इन नेताओं के समक्ष अब गंभीर बेरोजगारी का दौर शुरू हो गया है. आलम ये है कि जिले से नेताओं का पलायन भी शुरू हो चुका है और कोई पटना, तो कोई दिल्ली प्रवास पर निकलने लगा है. अब किसी पार्टी नेता के आगमन पर न जिंदाबाद का नारा लग रहा है और न ही सड़कों की घेराबंदी की जा रही है. केंद्र व राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर बहस का दौर जारी है. कोई कश्मीर की घटना पर केंद्र को घेर रहा है, तो कोई टॉपर घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है. कुल मिलाकर अब देखना है कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधि क्षेत्र के विकास को क्या दिशा दे पाते हैं?

वर्तमान में इन पूर्व प्रतिनिधियों के कार्यप्रणाली पर गौर करें, तो कई तथ्य सामने आ रहे हैं. सबसे अहम यह कि चुनाव हार जाने के बाद भी कुछ पूर्व प्रतिनिधि क्षेत्र की जनता की समस्याओं के निदान को लेकर जहां परेशान हैं, तो वहीं कुछ जनता के बीच विकास का खाका खींचने में लगे हैं. इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हर दिन हर पल अपना उल्लू सीधा करने के लिए मौके का इंतजार रहता है. जिले के रुन्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र में अब भी चुनाव पर विराम नहीं लगा है. पूर्व विधायक गुड्डी देवी व उनके पति राजेश चौधरी अब भी क्षेत्र में लगातार दस्तक दे रहे हैं. पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर तक की समस्या लेकर आने वाले लोगों के बीच अक्सर दोनों को देखा जाता है. वही सुरसंड क्षेत्र में जयनंदन प्रसाद यादव, तो रीगा में नगीना देवी व सूर्यदेव राय जनता के बीच अपनी उपस्थिति बनाए रखने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं. परिहार विधानसभा सीट से अपनी पत्नी गायत्री देवी को चुनाव जीताकर पूर्व विधायक रामनरेश प्रसाद यादव अपना बाजार बनाए रखने में लगे हैं. इनके अलावा अधिकांश या तो जिले से बाहर हैं या कहां हैं इसका जवाब किसी के पास नहीं है.

चुनावों में सक्रिय रहने वालों की माने तो कई पूर्व प्रतिनिधियों ने बेरोजगारी का हवाला देकर चुनावों में बिचौलिए की भूमिका निभाई. चुनावों में सेटिंग के खेल में माहिर कुछ नेताओं ने बेहतर प्रदर्शन कर अपनी राजनीतिक क्षमता का प्रदर्शन भी किया है. वहीं कुछ ने पर्दे के पीछे से ही अपने कुशल राजनीतिक अनुभव को आजमाया. इन नेताओं के समक्ष अब गंभीर बेरोजगारी का दौर शुरू हो गया है. आलम है कि जिले से नेताओं का पलायन भी शुरू हो चुका है और कोई पटना, तो कोई दिल्ली प्रवास पर निकलने लगा है. अब किसी पार्टी नेता के आगमन पर न जिंदाबाद का नारा लग रहा है और न ही सड़कों की घेराबंदी की जा रही है. केंद्र व राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर बहस का दौर जरूर जारी है. कोई कश्मीर की घटना पर केंद्र को घेर रहा है, तो कोई टॉपर घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है. कुल मिलाकर अब देखना है कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधि क्षेत्र के विकास को क्या दिशा दे पाते हैं?■

feedback@chauthiduniya.com

गर्भावस्था के दौरान यात्रा
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

Dr.Sima Shay
S.K. Puri, Boring Road Patna
डॉ सीमा सहाय एस.के. पुरी पटना से गर्भवती महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाएं यात्रा तो कर लेती हैं लेकिन उन्हें चाहिए कि गर्भवस्था के दौरान ज्यादा जरूरी हो तभी यात्रा करें...
Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate 100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.
A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil
Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcium & Lactic Acid Bacillus
Oflogyl-OZ Susp.
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg
Acoba Syp.
Methylcobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

JOHNSON PAINTS
— Interior & Exterior Wall Paints —
JP
बड़े अच्छे लगते हैं...
PERFECT Exterior Emulsion
JOHNSON Exterior Emulsion
JOHNSON PAINTS INDUSTRIES

कबीर चौरा के मुख्य महंत विवेकदास आचार्य ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

संत कबीर की ऐतिहासिक जन्मस्थली बचाइये

चौथी दुनिया ब्यूरो

कबीरपंथ के प्रमुख एवं कबीरचौरा मठ के महंत आचार्य पीठाधीश्वर संत विवेकदास आचार्य ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखकर संत कबीर की ऐतिहासिक जन्मस्थली के इर्द-गिर्द फैली गंदगी और बदहाली को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है. बसपा नेता के दबाव में आकर वाराणसी प्रशासन द्वारा उक्त स्थल पर तोड़-फोड़ किए जाने को तत्काल रोकने की मांग की गई है. उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में लिखा है कि कबीर जन्मस्थली के पास दस-बीस घरों की एक बस्ती है, जिसे बसपा का वोटबैंक बता कर संरक्षण दिया जा रहा है. स्थानीय बसपा नेता के दबाव में आकर वाराणसी प्रशासन संत कबीर की ऐतिहासिक जन्मस्थली में तोड़-फोड़ कर बस्ती के लिए इस स्थान पर शौचालय बनाने का कुचक्र रच रहा है. जबकि जन्मस्थली में पहले से ही 20 सुलभ शौचालय बने हुए हैं जिसकी कोई मरम्मत नहीं कराई जाती है.

संत विवेकदास आचार्य ने मुख्यमंत्री को बताया है कि कबीर जन्मस्थली के मुख्य द्वार पर कृषि विभाग और विधानसभा (रकबा-255) के नाम से कुछ जमीन है. कुछ वर्ष पूर्व दलितों को आगे कर प्रशासन की मदद से कुछ लोगों ने इस भूमि पर कब्जा कर लिया था. जब यह बात वाराणसी के तत्कालीन आयुक्त को पता चली तो अवैध कब्जा हटाकर आयुक्त ने अपने फंड से इसकी चारदीवारी बनवाई और इसमें एक कबीर स्तंभ का निर्माण भी कराया. अब इसी चारदीवारी और स्तंभ को प्रशासन तोड़ना चाहता है. उक्त चारदीवारी को तोड़ने से रोकने लिए महंत विवेक दास ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से अनुरोध किया है.

वाराणसी के लहरतारा में स्थित कबीर की जन्मस्थली की देखरेख और उसका संचालन कबीरचौरा मठ मूलगादी करता आ रहा है. कुछ वर्ष पहले सरकार की मदद से वाराणसी विकास प्राधिकरण ने कबीर की जन्म स्थली पर एक विशाल कबीर सभा भवन का निर्माण कराया था. साथ ही वाराणसी विकास प्राधिकरण ने पुरातत्व विभाग से इस स्थल और वहां पर सरोवर विकसित करने के लिए गोद भी ले रखा है. यहां आने वाले पर्यटकों के लिए परिसर को लाइट और पेड़ पौधों से सुसज्जित किया गया है. सरोवर को स्वच्छ रखने के लिए सुलभ शौचालय भी बनाए गए थे, लेकिन इन शौचालयों का रख-रखाव करने वाला कोई नहीं है. लहरतारा सरोवर ही वह जगह है, जहां कबीर नवजात शिशु के रूप में नीरू-नीमा नामक दम्पत्ति को मिले थे. पहले लहरतारा सरोवर 17 एकड़ में फैला था और आज भी कागज पर सरोवर इतने ही एकड़ में दर्ज है. लेकिन पुरातत्व विभाग के पास केवल पांच एकड़ सरोवर शेष बचा हुआ है. संत विवेकदास आचार्य के अनुसार भूमाफिया ने सरोवर को पाटकर उसके ऊपर अवैध भवन निर्माण कर लिए हैं. कुछ वर्ष पूर्व वाराणसी प्रशासन ने सरोवर की अवैध बंदोबस्ती को निरस्त कर दिया था. साथ ही लहरतारा सरोवर से अवैध निर्माण हटाने का निर्देश जारी किया गया था. लेकिन इसके बाद अवैध कब्जेदारों ने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया और अभी भी लोग वहां जमे हुए हैं.

संत विवेकदास आचार्य ने पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सम्पूर्णानंद द्वारा कबीर के प्राकट्य स्थल के निर्माण के प्रस्ताव का भी जिक्र किया है. वे लिखते हैं कि वर्ष 1954 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. सम्पूर्णानंद ने कबीरचौरामठ के तत्कालीन महंत जी से कबीर प्राकट्य स्थल के निर्माण के लिए सरकारी मदद की बात कही थी, लेकिन महंत जी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया. उन्होंने कहा था कि हम शासन की मदद से कबीर स्थल का निर्माण नहीं कराना चाहते. महंत जी की उस समय जो भी दृष्टि रही हो, लेकिन कबीर जन्मस्थली आज भी वीरान और उपेक्षित है. यह बिलकुल सही है कि इसके बाद कितने मुख्यमंत्री आए, लेकिन किसी ने भी कबीर जन्मस्थली के पुनर्निर्माण पर ध्यान नहीं दिया. वर्ष 2006 में इस स्थल पर एक भव्य और अनोखे स्मारक की योजना तैयार की गई थी, जिसकी आधारशिला तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने रखी थी. लेकिन उसका निर्माण कार्य आज तक शुरू नहीं हो पाया. वाराणसी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झील के सौंदर्यीकरण और इसके विकास के लिए सात करोड़ रुपये दिए हैं. उन्होंने आगे भी इसके विकास के लिए धनराशि देने की बात कही है. संत विवेकदास आचार्य ने पत्र में लिखा है कि मुख्यमंत्री जी जिस काम को उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए था, उस काम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ ले लिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि संत कबीर का पूरे देश में सर्वाधिक प्रभाव है.

वाराणसी के लहरतारा स्थित कबीर की जन्मस्थली की देखरेख और उसका संचालन कबीर चौरामठ मूलगादी करता आ रहा है. कुछ वर्ष पहले सरकार की मदद से वाराणसी विकास प्राधिकरण ने कबीर की जन्म स्थली पर एक विशाल कबीर सभा भवन का निर्माण कराया था. साथ ही वाराणसी विकास प्राधिकरण ने पुरातत्व विभाग से इस स्थल और वहां पर सरोवर विकसित करने के लिए गोद भी ले रखा है. यहां आने वाले पर्यटकों के लिए परिसर को लाइट और पेड़-पौधों से सुसज्जित किया गया है.

गौरतलब है कि प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हों या तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सभी ने कबीर की जन्मस्थली की उपेक्षा की. इतना ही नहीं अब सपा सरकार में इस ऐतिहासिक स्थल के साथ छेड़छाड़ भी शुरू हो गई है. संत विवेकदास आचार्य ने अपने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि प्रशासन के चारदीवारी तोड़ने के निर्णय के खिलाफ स्थानीय लोगों, कबीर भक्तों और साधु-संतों में काफी गुस्सा है. उन्होंने चेतावी देते हुए लिखा है कि प्रशासन ने अगर इसे तोड़ने की कोशिश की, तो उसको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा. आचार्य ने लिखा है कि अगर मुख्यमंत्री ने समय रहते प्रशासन को इसे तोड़ने से नहीं रोका तो वाराणसी में किसी अप्रिय घटना से इंकार नहीं किया जा सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

टोरंट पावर की सीनाज़ोरी और सपा सरकार की मुंहचोरी पर ग्रामीणों में ज़बरदस्त ग़ुस्सा

आगरा के गांवों में गहरा रहा आज़ादी का आंदोलन

सूफी यायावर

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगे आम नागरिकों को गिरवी रख देने के सरकारी कुचक्र के खिलाफ आगरा के गांव पिछले छह साल से संघर्ष कर रहे हैं. यह संघर्ष जल्दी ही व्यापक शक्ल अख्तियार कर लेगा. सियासतदां जिसे राख समझ रहे हैं, वह भीतर-भीतर सुलगता हुआ दावानल बनता जा रहा है. टोरंट पावर कंपनी की आराजकता और लूट के खिलाफ आगरा के दो दर्जन से अधिक गांवों में वर्षों से चल रहा आंदोलन अब गहराने लगा है. बसपा सरकार की करतूतों पर सपा सरकार द्वारा पर्दा डालने की कार्रवाई आने वाले विधानसभा चुनाव में 'यथोचित-परिणाम' देने वाली है. आगरा के दो दर्जन से अधिक गांवों में टोरंट पावर कंपनी की आराजकता और अत्याचार को अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचार की तरह देखा जा रहा है और ग्रामीणों का आंदोलन उसी नजरिए से प्रगाढ़ होता जा रहा है.

ग्रामीण संघर्ष विकास समिति के ब्रह्मानंद राजपूत ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में टोरंट के अधिग्रहण का विरोध वर्ष 2010 से ही चल रहा है. सभी राजनीतिक दल टोरंट के मुद्दे पर केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकते रहे हैं. ग्रामीण जनता अब अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद मैदान में आ जुटी है. लोगों ने टोरंट के उत्पीड़न से सभी गांवों को मुक्त कराने का अभियान तेज कर दिया है. स्थानीय लोगों का भी कहना है कि 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने टोरंट से मुक्ति दिलाने के नाम पर आगरा की जनता से वोट लिया था. लेकिन पांच वर्ष बीतने जा रहे हैं, हालात जस के तस बने हुए हैं. समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता तो साफ-साफ कहते हैं कि टोरंट बसपा सरकार की देन जरूर है, लेकिन टोरंट को हटाने में सपा सरकार कोई पहल नहीं कर सकती. उल्लेखनीय है कि आगरा के दहतोरा, मगटई, कलवारी मुहम्मदपुर, अमरपुरा, विलासगंज, लकावली, तोरा, कलाल खेरिया, बुढ़ेरा, बमरौली कटारा, नैनाना ब्राह्मण, नैनाना जाट, अजीजपुर, नगला, चमरौली, रजरईकुआंखेड़ा, महुआ खेड़ा, चोर नगरिया, मियांपुर, धनोली, घोंघे, नगला चुचाना समेत 24 गांवों के निवासियों की सहमति लिए बगैर बसपा सरकार ने टोरंट पावर के जिम्मे बिजली सप्लाई से लेकर बिलिंग, वसूली, रख-रखाव समेत सारे सम्बन्धित काम सौंप दिए थे. तब से टोरंट की यहां समानान्तर सरकार चल रही है. ग्रामीण विकास संघर्ष समिति लगातार सरकार से इन गांवों को टोरंट से मुक्ति दिलाने की मांग कर रही है. ग्रामीण कहते हैं कि टोरंट की आड़ में तत्कालीन सरकार ने अरबों रुपये के घोटाले किए, सपा सरकार के कार्यकाल में उसकी जांच होनी चाहिए थी और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. लेकिन सपा सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया. उल्टे टोरंट के अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार गांव वालों का उत्पीड़न कर रहे हैं, अनाप-शनाप बिल वसूल रहे हैं, अपनी मर्जी से लोगों पर बिजली चोरी के आरोप लगा कर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, बिल बढ़ाकर दे रहे हैं और मीटर चेक करने के नाम पर महिलाओं और बुजुर्गों से बदसलूकी कर रहे हैं. इसके खिलाफ शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही. ग्रामीण इससे तंग आ चुके हैं और सबने मिल कर टोरंट की अंडरग्राउंड केबलिंग का काम रोक दिया है. अंडरग्राउंड केबलिंग का काम बिना किसी सरकारी आदेश के कराया जा रहा था. दहतोरा में बिना परमिशन के अंडरग्राउंड केबलिंग का काम कर रहे टोरंट के कर्मचारियों को सरकारी आदेश दिखाने को कहा गया तो आदेश दिखाने के बजाय टोरंट के अधिकारी और ठेकेदार बदसलूकी पर उतर आए.

टोरंट कंपनी ग्रामीणों को मुकदमों में फंसाने की धमकियां दे रही है, इससे लोगों में गुस्सा फैलता जा रहा है. नतीजा यह हुआ कि ग्रामीण विकास संघर्ष समिति ने चुचाना गांव से टोरंट पावर के कर्मचारियों को खदेड़ भगाया. ग्रामीण विकास संघर्ष समिति के संयोजक डॉ. सुनील राजपूत के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नगला चुचाना पहुंच कर टोरंट कर्मचारियों से ग्राम पंचायत का परमिशन दिखाने को कहा. इस पर टोरंट कर्मचारी अभद्रता पर उतर आए, जिससे ग्रामीण गुस्से में आ गए और गांव की महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य लोगों ने उपकरण वगैरह उखाड़ डाले और उसे टोरंट के कर्मचारियों को देकर उन्हें गांव छोड़ कर चले जाने का फरमान जारी कर दिया. ब्रह्मानंद राजपूत ने कहा कि चुचाना गांव बाईपुर ग्राम पंचायत में आता है, जो अब टोरंट के अतिक्रमण से पूरी तरह मुक्त है. आम ग्रामीणों की इस सीधी कार्रवाई में प्रमुख रूप से शिवा बघेल, चौधरी अजय, चौधरी जितेन्द्र, योगेन्द्र फौजदार, सत्यप्रकाश लोधी, हरिशचन्द, वैकुंठी देवी, मीरा, सावित्री, रामादेवी, हाकिम सिंह, उमेश, लखन, बबलू, महावीर, रवि, वीरेन्द्र राजपूत, पप्पू, रोहित वगैरह शरीक थे.

ग्रामीण विकास संघर्ष समिति के नेता कहते हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चाहें तो 24 गांवों को टोरंटकी काली छाया से फौरन मुक्ति दिला सकते हैं, लेकिन ग्रामीणों को उनकी नियति के भरोसे छोड़ दिया गया है. टोरंट पावर कंपनी की गलत नीतियों और हरकतों से ग्रामीण बुरी तरह परेशान हैं. गांव वालों की मांग है कि दहतोरा समेत सभी सम्बन्धित गांवों की बिजली सप्लाई को टोरंट पावर से मुक्त कर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से जोड़ा जाए. ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तबतक जारी रहेगा जबतक गांवों को टोरंट पावर से मुक्ति नहीं मिल जाती. 24 गांवों की महापंचायत ने परिणाम प्राप्त करने तक एकजुट संघर्ष जारी रखने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है. जनसम्पर्क और समन्वय के लिए 24 गांवों में मोटर साइकिलों से दौरा किया जा रहा है. जिसमें प्रमुख रूप से ब्रह्मानंद राजपूत, डॉ. सुनील राजपूत, डॉ. ऊदल, विष्णु मुखिया, उमेश राजपूत, जीतू राजपूत, भीम राजपूत चौधरी मनोज, चौधरी अजय, योगेन्द्र चौधरी, वेदपाल फौजदार, लखन राजपूत, आनंद राजपूत, बबलू राजपूत, प्रेमराज लोधी, जितेन्द्र राजपूत, योगेश, निनुआ खान, राहुल खान, थान सिंह, बन्टी लोधी, चन्दू राजपूत, योगेन्द्र फौजदार, सतीश राजपूत, मुकेश राजपूत, सुनील लोधी, वीरेन्द्र राजपूत, छोटू लोधी, चोबसिंह समेत अन्य सदस्य शामिल हैं. विष्णु मुखिया ने बताया कि टोरंट पावर कंपनी पिछले छह वर्षों से लगातार ग्रामीणों का उत्पीड़न कर रही है. ग्रामीण विकास संघर्ष समिति भी पिछले छह वर्षों से टोरंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती आ रही है, लेकिन शासन और प्रशासन ग्रामीणों की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. इससे ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है. ग्रामीण हरिकिशन लोधी कहते हैं कि ग्रामीण विकास संघर्ष समिति टोरंट कंपनी के किसी भी नुमाइंदे को अब किसी भी कीमत पर गांवों में घुसने नहीं देगी. लब्बोलुबाब यह है कि टोरंट कंपनी की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ ग्रामीणों ने मशाल उठा ली है. टोरंट पावर की बदइंतजामी से न केवल ग्रामीण इलाके बल्कि पूरा आगरा शहर भी परेशान है. फर्जी बिलिंग से पूरा शहर तबाह है. सप्लाई की हालत खस्ता है और टेक्निकल सपोर्ट का हाल यह है कि कहीं छोटा भी फाल्ट हो जाए तो ठीक होने में 20 से 24 घंटे लग जाते हैं. सिस्टम इतना नाजुक है कि हवा तेज हो तो सब कुछ ठप्प. टोरंट की बदइंतजामी के खिलाफ लोग गुस्से में हैं. शहर में कई जगहों पर टोरंट के खिलाफ हंगामा और प्रदर्शन दिख रहा है. कंपनी की पूरी तकनीकी टीम ही सवालों के घेरे में है. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश में फिर पसर रहा ज़हरीली शराब का क़हर

सपा नेता परोस रहा ज़हर!

- एटा के अलीगंज में ज़हरीली शराब से 44 मरे
- आगरा, फर्रुख़ाबाद में हो रहा सैकड़ों का इलाज
- मैनपुरी से एटा आया था मिथाइल अल्कोहल
- सपा विधायक पर उठ रही हैं लोगों की उंगलियां

अवधेश दीक्षित

एटा जिले के अलीगंज कस्बे में जहरीली शराब से हुई मौत का आंकड़ा 44 पार कर गया है. मृतकों में अलीगंज क्षेत्र के 36 व फर्रुखाबाद के आठ लोग शामिल हैं. जहरीली शराब पीकर जिंदगी व मौत के बीच झूल रहे पांच दर्जन से अधिक लोगों का उपचार सैफई, आगरा, फर्रुखाबाद, अलीगंज के चिकित्सालयों में चल रहा है. अलीगंज की गलियों में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है. जिनका उपचार चल रहा है, उनके परिजन सहमे हुए हैं कि मौत की खबर फिर न आ जाए. सरकार व प्रशासन ने घटना के पांच दिन बाद भी शातिराना चुप्पी साध रखी है. जहरीली शराब के रूप में मौत बेचने वाले शराब माफियाओं की गिरफ्तारी में पुलिस नाकाम रही है. पुलिस ने दिखाने के लिए अलीगंज के मोहल्ला काजी में अवैध शराब बेचने वाले श्रीपाल को गिरफ्तार किया है. लेकिन असलियत में मामले की लीपापोती में जुटी है. पीड़ितों के परिजनों के सवाल अभी भी अनसुलझे हैं कि आखिर जहरीली शराब आई कहां से? इस नेटवर्क में कौन लोग शामिल हैं? सत्ता मृतकों के परिजनों को मुआवजा देकर परिवार पर टूटे कहर को भूल जाने और धंधेबाजों पर पर्दा डालने की जुगत में है.

गत 10 वर्षों में एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद व मैनपुरी समेत आगरा जोन के कई जनपदों में अवैध शराब का धंधा पुलिस सरंक्षण में कुटीर उद्योग के रूप में फैल चुका है. सत्ता व प्रशासन की नाक के नीचे भारत के भविष्य युवा जहरीली शराब पीकर मौत के मुंह में जा रहे हैं. शासन व प्रशासन को कभी इसकी सुध ही नहीं आई कि इस धंधे पर प्रहार कर लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचा सके. आगरा व कासगंज में जहरीली शराब से हुई मौत ने इस बात के संकेत दो वर्ष पूर्व ही दे दिए थे कि जहरीली शराब से अभी और लोग मरेंगे. प्रशासन व पुलिस ने गंभीर पहल की होती तो शायद अलीगंज की घटना न होती. अलीगंज में ही नौ जुलाई 2001 को बंजारा जाति के 10 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी. उसमें भी पुलिस ने लीपापोती का ही काम किया था.

कासगंज जनपद के नगला भंडारी में दो वर्ष पूर्व आयोजित भंडारे में हुए जहरीली शराब के वितरण के बाद तीन लोगों की मौत हुई और एक दर्जन बीमार हुए थे तो पुलिस ने उसमें भी लीपापोती ही की. नगला भंडारी में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में पुलिस ने भाजपा नेता के पुत्र का नाम भी लिया और एफआईआर भी हुई. लेकिन वरिष्ठ नेताओं के दबाव के चलते पुलिस ने इसमें भी लीपापोती कर दी.

गत 16 जुलाई को अलीगंज में जहरीली शराब पीकर एक ही दिन में हुई 17 मौत से कोहराम मचा और मौत का आंकड़ा 19 जुलाई तक 44 तक पहुंच चुका है. कस्बे में जिस जगह अवैध शराब बेची जा रही थी वह कोतवाली के निकट ही है. जहरीली शराब से हुई मौत से घबराई सरकार व आलाधिकारियों ने एटा के जिला आबकारी अधिकारी, अलीगंज के क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी समेत कुछ पुलिस कर्मियों से सस्पेंड कर यह दिखाने की कोशिश जरूर की कि वह दोषियों पर कार्रवाई करेगी.आगरा जोन के आईजी दुर्गा चरण मिश्र ने एटा पहुंचकर पत्रकारों से कहा कि पुलिस आगरा जोन के सभी जनपदों में शराब माफियाओं पर कार्रवाई करेगी. उसके बाद पुलिस सक्रिय भी हुई तो कच्ची शराब खींचने वाले लोगों पर कार्रवाई की. एटा में कच्ची शराब का धंधा करने वाले 53 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई. लेकिन पुलिस जानती है कि असली दोषी कौन लोग हैं. जनता भी जानती है. मृतकों के परिजन भी जानते हैं. वे पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं. अलीगंज व आस-पास के क्षेत्रों में शराब माफियाओं के विरुद्ध आक्रोश है. पुलिस ने जिस श्रीपाल को जहरीली शराब बेचने के मामले में गिरफ्तार किया है, उसका कहना है कि उसके पास शराब मैनपुरी से आई थी. मैनपुरी के रहने वाले अनिल (निवासी गोकिलपुर) ने उसे शराब बेची थी. मैनपुरी पुलिस ने अनिल को गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया. मैनपुरी पुलिस का कहना है कि श्रीपाल व अनिल के बीच कोई संबंध ही नहीं हैं. अनिल की न तो श्रीपाल से रिश्तेदारी है और न ही कोई कारोबारी रिश्ता है. लेकिन पुलिस इस बात का जवाब नहीं दे पा रही है कि शराब आखिर आई कहां से. सूत्रों की मानें तो श्रीपाल के पास टैंकर में भरकर मिथाइल अल्कोहल मैनपुरी से ही आया था. जिससे शराब बनी और एटा के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में बेची गई. यही शराब लोगों की मौत की वजह बनी. अलीगंज क्षेत्र में लोग सत्ता, पुलिस व शराब माफिया के खौफ से डरे सहमे हैं और कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. सरकार, आला अधिकारी व पुलिस मामले में कार्रवाई के नाम पर केवल स्वांग रच रहे हैं. अलीगंज क्षेत्र में ही डेढ़ सौ गांवों में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है. गत वर्षों में पुलिस ने टपुआ गांव को ही टारगेट कर जो कार्रवाई की उससे भी अलीगंज के अन्य क्षेत्रों में अवैध शराब का कारोबार फैला. टपुआ गांव के आस-पास बिकने वाली अवैध शराब गत 40 वर्षों से बिक रही है. टपुआ गांव के शराब माफियाओं को भी सत्ता का संरक्षण वर्षों तक मिलता रहा. शराब माफियाओं ने हरियाणा व दिल्ली से तस्करी कर लाई गई शराब को बेचना शुरू कर दिया. इसके साथ ही हरियाणा की शराब के नाम पर मिथाइल अल्कोहल से बनी शराब भी खूब बिक रही है. इस काम में पुलिस ने माफियाओं को संरक्षण दे रखा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

विपक्ष की उंगली सपा विधायक पर

एटा के अलीगंज में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद राजनीति शुरू हो गई है. विरोधियों के निशाने पर सपा विधायक रामेश्वर सिंह हैं. रामेश्वर सिंह यादव का कहना है कि भाजपा लाशों पर राजनीति कर रही है. शराब से मौत के बाद भाजपा का प्रतिनिधिमंडल अलीगंज पहुंचा और पीड़ित परिवारों से मिल कर उन्हें ढाढस बंधाया. भाजपा के प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह ने जहरीली शराब से हुई मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की. पंकज सिंह ने आरोप लगाया कि अवैध शराब का कारोबार सरकार, विधायक व पुलिस प्रशासन की मदद से चल रहा है. सत्ता का संरक्षण होने की वजह से पुलिस अधिकारी शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने से डर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी अलीगंज पहुंचा और उन्होंने पीड़ित परिवारों से मिलकर शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की. पूर्व मंत्री अवधपाल सिंह ने भी इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है. बहुजन समाज पार्टी ने भी इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है.

मंत्री जी शराब बिकवाते ही क्यों हो?

पीड़ित परिवार आबकारी मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि जब शराब से लोग मर रहे हैं तो शराब बिकने की इजाजत ही क्यों दी जा रही है? उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री राम करन आर्य पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद जब लोगों से शराब न पीने की अपील कर रहे थे तो पीड़ित परिवार के आक्रोशित परिजनों ने मंत्री से सवाल पूछा कि मंत्री जी शराब बिकवाते ही क्यों हैं? आबकारी मंत्री इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने चुप्पी साध ली. सपा विधायक पर शराब माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप का आबकारी मंत्री ने यह कहकर जवाब दिया कि विरोधियों का काम ही आरोप लगाना है. जहरीली शराब से हुई मौत के बाद लोगों में जर्बदस्त आक्रोश है. सरकार व पुलिस को लोगों के कई सवालों के जवाब देने होंगे, जिसमें जहरीली शराब बिक्री के नेटवर्क में कौन शराब माफिया शामिल हैं और उन्हें किन लोगों का संरक्षण मिला हुआ था. पीड़ित परिवारों की महिलाओं ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी लोगों को फांसी की सजा दी जाए. जहरीली शराब से जो 44 लोग मरे हैं उनमें अधिकांश युवा हैं.

नोटिस और कार्रवाई के बीच धंधा भी जारी है

एटा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लेने की औपचारिकता निभाई और प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से जवाब तलब किया है. आयोग ने स्पष्ट तौर पर माना है कि इस मामले में पुलिस और आबकारी विभाग के कुछ अधिकारियों के निलंबन से यह जाहिर होता है कि सरकारी मशीनरी की लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ. आयोग ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव दीपक सिंघल और पुलिस महानिदेशक जावीद अहमद को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है. आयोग का कहना है कि एटा और फर्रुखाबाद में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के बाद बरेली, बिजनौर, कानपुर देहात, इलाहाबाद, मऊ, कुशीनगर और सोनभद्र जिलों में अनेक स्थानों पर मारे गए छापों में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से बनाई गई शराब और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई है. लिहाजा, इसके फैलने का अंदेशा है. जहरीली शराब मामले में कार्रवाई के बारे में शासन ने बताया है कि अलीगंज थाने के प्रभारी मुकेश कुमार सहित कुल सात पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है. एटा के जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक एवं आबकारी सिपाही को पहले ही निलंबित कर दिया गया था. पहले मृतकों के परिजनों को सरकार की तरफ से दो-दो लाख मुआवजा दिए जाने की बात कही गई, बाद में संवेदनशीलता दिखाते हुए इसे 5 लाख रुपये कर दिया गया. प्रदेश में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में 1585 मुकदमे दर्ज कर 1621 लोगों को गिरफ्तार किया गया. 36121 लीटर अवैध शराब भी जब्त की गई.इस अभियान और सतर्कता के दिखावे के बीच एटा में ही नौसादर और मिथाइल अल्कोहल से शराब बनना और बिकना जारी है.

गिरफ्तार अभियुक्त

शराबबंदी के समर्थन में उतरे लोग

एटा के अलीगंज में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग उठने लगी है. समग्र विकास परिषद संस्था ने एटा के डीएम को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में शराब की बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग की है. परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल यादव, तेज सिंह वर्मा व अन्य कार्यकर्ताओं ने डीएम से मांग की है कि शराब की बिक्री फौरन बंद की जाए. जहरीली शराब से हुई 44 मौत देख कर आम लोग भी कहने लगे हैं कि बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी की कामयाबी को देखते हुए उसे उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाना चाहिए.

डेढ़ सौ गांवों में होती है अवैध शराब की बिक्री

कासगंज जनपद की काली नदी, हजारा नहर व कटरी क्षेत्र के डेढ़ सौ गावों में अवैध शराब का कारोबार होता है. त्योहारों व विवाह समारोहों के दौरान राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली से तस्करी होकर आने वाली शराब भी धड़ल्ले से बेची जाती है. इस शराब में नशीली दवाओं व कैमिकल का प्रयोग शराब माफिया धड़ल्ले से करते हैं. शहर कोतवाली के भैंसोरा व सतावी महादेवा व काली नदी के आस-पास के गांव कच्ची शराब बनाने के लिए मशहूर हैं. काली नदी के किनारे बसे एटा व मैनपुरी के गांवों में कच्ची शराब बनाने का कारोबार चलता है. इन गांवों तक पुलिस की पहुंच नहीं हो पाती इसलिए लोगों को कोई डर भी नहीं रहता. सोरों के नगला लक्ष्मी, सूखा नगला, पचलाना, सियपुर, खड़ैया आदि गांवों में शराब की बिक्री होती है. पटियाली के नगला हीरा, घौसगंज, नगला भिटी, नगला मुंशी, नगला देवी, नगला चतुरी, नगल जयकिशन, नगला रौकरी, नगला भटमई, नगरिया, उस्मानपुर, दीवान नगर, अलीपुर दादर, अजीजपुर, चाकरपुर, नगला रगी, नगला बौड़ार, गंगनपुर, सनौढ़ी, नगला दरका, नगला हंसी, नगला गुलाबी, नगला खड़ऊआ आदि हैं. इसी तरह अमांपुर क्षेत्र के भृगवासिनी, जाटऊ, अशोकपुर, बरसौड़ा,नगला पौपी, कुचलपुर, महदवा, नगला सीडर, नगला तालई, महेशपुर, जारई, नगलाबरी आदि गांवों में कच्ची शराब बनाने का कारोबार होता है.

मगही के कबीर का स्मरण

अनंत विजय

साहित्य में इस बात पर बहुधा चिंता प्रकट की जाती है कि युवा साहित्य की ओर नहीं आ रहे हैं. युवाओं को जोड़ने की भाषा को समकालीन साहित्यकार विकसित नहीं कर पा रहे हैं. युवाओं की चाहतों और ख्वाहिशों को कहानी और उपन्यास में जगह नहीं मिल पा रही है. इस बात को लेकर भी साहित्य जगत में खूब मंथन होता है कि युवाओं को साहित्य की ओर कैसे लाया जाए. यह बात भी कई बार की जाती है कि साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं में लेख, कहानी, कविता आदि छपने पर सिर्फ बुजुर्ग लेखकों की ही प्रतिक्रिया मिलती है. अपना अनुभव भी कुछ इसके ही आसपास का है. ऐसा बहुत कम होता है कि कोई कम उम्र के पाठक की ओर से ऐसी प्रतिक्रिया या सूचना ही मिलती हो कि उन्होंने अमुक लेख या अमुक रचना हंस या पाखी में पढ़ी. टेलीविजन की तरह पत्रिकाओं में इस तरह की कोई तकनीक विकसित नहीं हो पाई है जिससे पता लग जाए कि किस आयु वर्ग के पाठक कौन सी पत्रिका या अखबार पढ़ते हैं. सर्वे आदि से इसका अनुमान लगाया जाता है. साहित्यिक पत्रिकाओं के लिए तो ये अनुमान भी नहीं लगाया जाता है. यह पता लगाना लगभग असंभव है कि कौन सी साहित्यिक पत्रिका किस आयु वर्ग के पाठक पढ़ते हैं. पाठकों की मिलने वाली प्रतिक्रिया से और गोष्ठियों आदि में उपस्थित श्रोताओं की उम्र से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है. कितना सही या कितना गलत होगा ये कहना मुश्किल है.

इतना तय है कि साठ और सत्तर के दशक में युवाओं में साहित्य को लेकर जो क्रेज था उसकी कमी आज दिखाई देती है. हिंदी साहित्य में इस कमी को कैसे दूर किया जाए इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए. इसकी अगर हम पड़ताल करें तो यह पाते हैं कि दशकों से हिंदी में यह परंपरा चल रही थी कि कविता कहानी और उपन्यास के अलावा साहित्येतर विषयों पर लेखन नहीं हो रहा था. नतीजा हम सबके सामने है. हिंदी साहित्य से कई विधाएं लगभग गायब होती चली गईं और पाठक वही पढ़कर उबते चले गए. युवाओं में बेहद लोकप्रिय फिल्म और संगीत पर लिखने वालों को हेय दृष्टि से देखने या फिर बुर्जुआ विचाधारा के पोषक माने जाने की वजह से नए लेखकों ने फिल्म पर संजीदगी से नहीं लिखा. इस वजह से भी पाठक तो खोते ही चले गए, युवा भी हिंदी साहित्य से दूर होकर अंग्रेजी की ओर बढ़ चला. कहानी और उपन्यास में एक खास किस्म की विचारधारा और यथार्थ को बढ़ावा देने की कोशिश ने भी युवाओं को साहित्य से दूर किया. इस शताब्दी की शुरुआत में ही कई युवा लेखकों ने इस ठस सिद्धांत पर अपनी रचनाओं के माध्यम से हमला किया लेकिन फिर भी बहुतायत में लेखक उसी लीक पर चलते रहे. नतीजा युवा पाठक दूर होते चले गए.

साहित्य संस्कृति के मामले में बिहार की भूमि उर्वरा रही है. पाठकों के मामले में भी बिहार को अव्वल स्थान हासिल है. पत्र-पत्रिकाएं सबसे ज्यादा बिहार में ही बिकती हैं. चाहे वो अखबार हो या पाक्षिक पत्रिका या फिर साहित्यिक लघु पत्रिकाएं. इन सबके पाठक सबसे ज्यादा बिहार में ही हैं. इसी बिहार की धरती पर एक ऐसी शुरुआत हुई है जिसने युवाओं के साहित्य से दूर होते जाने की बात को थोड़ा ही सही निगेट किया है. बिहार में एक स्थान है बड़हिया, समृद्ध किसानों से लेकर काश्तकारों और जमींदारों का वहां बोलबाला रहा है. बड़हिया के लोग बिहार में अपनी दबंगई की वजह से जाने जाते हैं. एक बार अटल बिहारी वाजपेयी वहां चुनावी सभा में गए थे तो उन्होंने बड़हिया को अपने ही अंदाज में व्याख्यायित किया था. अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने उम्दा भाषण में कहा था कि बड़ा है जहां के लोगों का हिया बड़ा है वही है बड़हिया. हिया यानि दिल. यानि जहां के लोगों का दिल बड़ा है वही बड़हिया है.

अभी उसी बड़े दिलवाले जगह बड़हिया में करीब सौ युवाओं ने एक अनूठी पहल की है. बड़हिया के ये सौ युवा नौकरी आदि की तलाश में अपने गांव से बाहर रहते हैं लेकिन बार-बार लौट कर अपनी जड़ों की तरफ लौटते हैं. युवाओं के इस समूह ने बड़हिया में साहित्य को लेकर एक बड़ा फैसला किया. उन्होंने तय किया कि बड़हिया में पैदा हुए मशहूर मगही कवि मथुरा प्रसाद नवीन की एक प्रतिमा वहां लगाई जाएगी. इस दौर में जब नेताओं से लेकर संविधान निर्माता अम्बेडकर तक की मूर्तियां लगाने का चलन है, मायावती जैसी नेता खुद की मूर्तियां लगवा रही हैं वैसे माहौल में सौ युवाओं का एक समूह अगर ये फैसला लेता है कि एक कवि की मूर्ति लगानी है तो यह एक सुखद आश्चर्य से भर देता है. इन युवाओं ने यह तय किया कि मगही के महान कवि मथुरा प्रसाद नवीन की याद में जो मूर्ति लगाई जाएगी वो जन सहयोग से लगाई जाएगी. इसके लिए उन युवाओं ने फैसला किया कि बड़हिया के हर घर से एक-एक रुपया चंदा लिया जाएगा. हर घर से एक रुपया चंदा लेने के पीछे तो सोच यह थी कि यह लगे कि सबके सहयोग से ये मूर्ति लगाई जा रही है. मुझे बताया गया कि जात-पात से उपर उठकर बड़हिया के ये उत्साही युवक हर घर में गए और वहां से एक-एक रुपया इकट्ठा किया. किसी ने एक की जगह दस दिए तो किसी ने पांच तो किसी ने सौ. राशि जमा होने के बाद मथुरा प्रसाद नवीन की प्रतिमा समारोहपूर्वक स्थापित कर दी गई. यह अपनी तरह का अनूठा प्रयास है. मथुरा प्रसाद नवीन मगही के महान कवि हैं और उस अंचल में उनको मगही का कबीर भी कहा जाता है.

मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन मथुरा प्रसाद नवीन हमारे आमंत्रण पर एक बार जमालपुर आए थे. सर्दियों के दिन थे और वो सर पर चादर लपेटे हुए जब जमालपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे थे तो हमको लगा था कि कवि नहीं कोई किसान उतर रहा है. चादर को गांती की तरह बांधकर ठंड से मुकाबला कर रहे मथुरा प्रसाद नवीन जब अगले दिन कविता सुनाने लगे तो पूरा सभागार उनकी कविताओं पर मुग्ध था. करीब दो दशक पहले सुनाई गई उनकी एक कविता अब भी मेरे स्मरण में है *शब्द शब्द में शोला भरके तोहरे गीत सुनएबो हम, कसम खाहियो गंगाजी के कलम न कभी घुमैबबो हम, तोहरे खातिर सबकुछ करबो, भुक्खल भी मुस्कयबो हम, अत्याचार मिटैबे खातिर सुक्खल चना चबैबो हम.* अब इन पंक्तियों में कवि जिस तरह से कहता है कि अत्याचार मिटाने की खातिर सूखा चना चबाने के लिए वो तैयार है उससे उनके तेवरों का अंदाजा लगाया जा सकता है.

1928 में जन्मे मथुरा प्रसाद नवीन को अपने समय के सारे बड़े साहित्यकारों का स्नेह प्राप्त था जिसमें निराला से लेकर दिनकर तक शामिल थे. नवीन जी ने मगही के अलावा हिंदी में भी कविताएं लिखी *लो लिख लो मेरी बातों को, क्रांति के उत्पातों को/हो गए मूर्ख विद्वान यहां, गंजे हो गए महान यहां/दलाल लगे कविता करने, कविराज गए जंगल चरने/तिकड़म के लाखों गेट यहां, मालिश का ऊंचा रेट यहां/नेता से मुश्किल भेंट यहां, मंत्री का भारी पेट यहां.* अब इस कविता में कवि रेंज को देखिए, चार पंक्तियों में उन्होंने साहित्य से लेकर समाज और राजनीति की विद्रूपताओं को बेनकाब कर दिया. कविता की उस वक्त की स्थिति पर कैसा प्रहार है. अपने समय पर प्रहार का सहास दिखाने वाले इस कवि मथुरा प्रसाद नवीन को हमारे हिंदी समाज ने लगभग भुला दिया है. बिहार में एक मगही अकादमी हुआ करती थी, शायद अब भी हो लेकिन यो क्या करती है ये शायद पटना के साहित्यकारों को भी ज्ञात नहीं है. जो इसके कर्ताधर्ता होंगे उनको सहलियतें आदि मिल रही होंगी लेकिन अपने कवियों और लेखकों की रचानओं को सहेजने और उसको विकसित करने का काम ये अकादमियां नहीं कर पा रही हैं. संभव है कि इस कार्यक्रम में उनकी भागीदारी हो लेकिन पहल युवाओं की है. साहित्य की इसी उदासीनता पर मथुरा प्रसाद नवीन जी ने तल्ख टिप्पणी की है *तुलसीदास तमाशा देखो, तिकड़म कैसन चल रहलो हैं/ पूजा पर बैठल बाबा जी खैनी-चूना मल्ल रहल हो.* अब इस तरह की पंक्तियों को देखकर या पढ़कर बरबस कबीर की याद आ जाती है. कबीर भी इसी फक्कड़पने के अंदाज में अपनी बात कहा करते थे और समाज की विसंगतियों पर प्रहार करते चलते थे. कबीर की ही तरह मथुरा प्रसाद नवीन को भी जिंदगी में अपमानित होना पड़ा था. उनको उनके जीवन काल में वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे. मगही के इस कबीर को जिस तरह से वहां के युवाओं ने अपनी अनूठी पहल से याद किया है वो साहित्य प्रेमियों के लिए सुकून देने वाला है और साहित्य अकादमियों को चुनौती भी. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

मानसून में कैसे रखें त्वचा को स्वस्थ

डॉ. दीपाली भारद्वाज

मानसून के दौरान कुछ सावधानियां अपनाने से आपको अपने त्वचा को चमकदार और स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिल सकती है. मानसून के दौरान आर्द्रता और बारिश के मौसम में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सनस्क्रीन की जरूरत नहीं होती. इस मौसम में भी धूप में बाहर निकलने से 10-15 मिनट पहले इसका इस्तेमाल करें. इसके अलावा बारिश के दौरान हो सकता है कि आपको कम प्यास लगे लेकिन निर्जलीकरण से बचाने के लिए इस मौसम में भी खुद को हाइड्रेट रखना चाहिए. दैनिक रूप से 4-5 लीटर पानी पीना वयस्कों के लिए जरूरी है.

स्वस्थ त्वचा के लिए टिप्स

- रात और सुबह दो बार चेहरे को साफ करें.
- सोने से पहले मेकअप उतार दें.
- यदि बारिश का पानी आपके शरीर या बालों पर गिरता है तो जितनी जल्दी हो इसे बहते पानी से धो लें ताकि त्वचा को विभिन्न बैक्टीरियल और फंगल संक्रमण से बचाया जा सके.
- बहुत तंग कपड़े न पहने, क्योंकि इससे बारिश का पानी त्वचा के नजदीक लंबे समय तक चिपका रहता है.
- जीवाणुरोधी साबुन से नहाएं.
- मानसून के दौरान छाता और रेन कोट फैशनेबल नहीं बल्कि आपकी त्वचा के लिए बहुत जरूरी सामान है.
- सही फल, मेवे, सब्जियां खाने से शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति को मजबूत रखने में मदद मिलेगी. केवल वसायुक्त तेल और खाद्य पदार्थ या शर्करा युक्त खाद्य वस्तुओं को खाने से मानसून के दौरान समस्या पैदा हो सकती है.

बालों के लिए टिप्स

- बाल नियमित रूप से धोएं.
- मानसून के दौरान बालों के लिए तेल महत्वपूर्ण नहीं है और बहुत सूखे बालों के लिए भी सप्ताह में एक बार अधिकतम इस्तेमाल करना चाहिए और कंडीशनर का उपयोग मददगार साबित होगा.
- यदि बाल गिर रहे हों तो खाने में अंडे का सफेद हिस्सा, सोया, पनीर, टोफू और दाल की मात्रा बढ़ा दें. शैम्पू करने से आधे घंटे पहले या रात भर के लिए सरसो के दाने मिश्रित कैस्टर आयल का पैक बाल में लगाएं. कम से कम रसायन वाला शैम्पू ही आपके बालों के लिए उपयुक्त है.
- यदि बालों में रूसी है तो मानसून के दौरान सिर में सही पीएच मात्रा के लिए नींबू के रस के साथ जैतून तेल का मालिश करें. यह रूसी को बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा है. ■

त्याग का मतलब है अहंकार का त्याग: डॉ. प्रणव पंड्या

जिसने स्वार्थ और अहंकार को छोड़ दिया उसने जीवन में सब कुछ पा लिया. त्याग का मतलब ये नहीं है कि हिमालय चले जाएं, वन चले जाएं. त्याग का मतलब होता है अहंकार का त्याग. ये बातें अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख डॉ. प्रणव पंड्या ने एमपी फाउंडेशन द्वारा आयोजित कर्नल अजय मुशरान वार्षिक स्मृति व्याख्यान में अपने की-नोट लेक्चर के दौरान कही.

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश फाउंडेशन 2007 से लगातार कर्नल अजय मुशरान वार्षिक स्मृति व्याख्यान आयोजित करता रहा है, जिसमें किसानों की आत्महत्या, भोपाल गैस पीड़ितों की त्रासदी, भूमंडलीकरण, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर वरिष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर, कांग्रेस नेता शशि थरूर, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी जैसे लोगों ने अपना व्याख्यान दिया है. इस वर्ष के व्याख्यान का विषय था त्याग की शक्ति.

मध्य प्रदेश फाउंडेशन के महासचिव डॉ. हरीश भल्ला ने डॉ. पंड्या का परिचय कराते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने डॉ. पंड्या को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया लेकिन उन्होंने सरकार के इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया. आज के दौर में ऐसे लोग कहां मिलते हैं जो सत्ता को ठुकरा देते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश फाउंडेशन ने उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया.

अपने व्याख्यान के शुरुआत में डॉ. पंड्या ने त्याग को अध्यात्म के माध्यम से समझाने की कोशिश की और दरअसल यही उनके व्याख्यान का सार भी था. उन्होंने कहा कि त्याग को समझने के लिए अध्यात्म को समझना होगा. सांसारिकता के जो मानक हैं वो अध्यात्म के उलट हैं, जिन्हें संसार अपनी उपलब्धियां समझता है, गौरव समझता है, वो आध्यात्मिक जीवन के लिए बोझ मानी जाती है. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. कर्ण सिंह ने मध्यप्रदेश फाउंडेशन की ओर से डॉ. प्रणव पंड्या का प्रतीक चिन्ह और शॉल से स्वागत किया. अपने संबोधन में डॉ. सिंह ने सबसे पहले कर्नल मुशरान और गायत्री परिवार के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा और माता भगवती देवी शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि गायत्री हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ है.

डॉ. पंड्या के राज्यसभा की सदस्यता के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रिया पर बोलते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि राज्यसभा कोई इतनी बुरी सभा भी नहीं है. त्याग पर अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉ. कर्ण सिंह ने कहा कि मेरे विचार में त्याग और कर्म दोनों महत्वपूर्ण हैं. उपनिषद का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि त्याग का मतलब होता है आंतरिक त्याग. मध्य प्रदेश फाउंडेशन के टूरटी और आउटलुक (हिन्दी संपादक) आलोक मेहता ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया. कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मशहूर सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खां और मध्य प्रदेश फाउंडेशन के अध्यक्ष विवेक तनखा ने भी सभा को संबोधित किया. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

साईं वंदना

प्राणिमात्र का कल्याण ही एकमात्र उद्देश्य

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

चमत्कार : सद्गुरु की सूक्ष्म कार्य-प्रणाली

क्या सद्गुरु चमत्कार करते हैं?

जैसा हम समझते हैं कि किसी कार्य को कोई करता है-मकान बनाना, नौकरी करना आदि, तो सद्गुरु भी इसी प्रकार चमत्कार का कोई कार्य करते होंगे, सद्गुरु इस प्रकार कोई कार्य करने की तरह चमत्कार नहीं करते. उनके काम का दायरा इतना वृहत् है कि वे हजार-हजार प्राणियों की एक ही समय में, एक साथ उन्नति कर सकते हैं. एक ही स्थूल शरीर लेकर यदि वे इतना करना चाहेंगे तो यह संभव नहीं होगा, क्योंकि इस स्थिति में समय और दूरी से वे सीमित हो जाएंगे. इसलिए उनका कार्य एक सूक्ष्म शक्ति के द्वारा होता है, जिसको समझ न सकने के कारण हम उसे चमत्कार कहते हैं. सूक्ष्म शक्ति के द्वारा कार्य करना उनका स्वभाव है और वे उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं. उदाहरण के लिए जब आदमी पैरों से चलता हो और पक्षी अपने पंख से उड़ता हो, तो वह यह नहीं सोचता कि वह चल रहा है या उड़ रहा है, क्योंकि यह उसका स्वभाव है. उसी प्रकार जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, वह सद्गुरु का सूक्ष्म स्वभाव है. प्रकृति की सारी शक्तियां उनकी शक्ति से स्वतः चालित होती हैं. जैसे आग का बुझ जाना, बारिश का रुक जाना या किसी की अलौकिक उपाय से मदद करना.

चमत्कार : सामूहिक कल्याण के लिए प्रयुक्त ईश्वरीय शक्तियां

ऐसा देखा गया है कि कुछ तथाकथित साधु-संन्यासी, फकीर आदि जिन्हें छोटी-छोटी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अपनी शक्तियों का दंभ रखते हैं और उनका चमत्कारिक प्रदर्शन करते हैं. इस संबंध में आपकी क्या धारणा है?

बहुत कम लोगों को असली सिद्धियां प्राप्त होती हैं. ये सिद्धियां भी प्रकृति की शक्तियां होती हैं, जो अद्भुत कार्य करती हैं. चमत्कारिक प्रदर्शन के लिए किए जाने वाले कृत्यों में ईश्वरीय शक्ति नहीं अपितु निम्न स्तर की तन्त्र या टोटका विद्या होती है. जिनहें वास्तविक शक्ति कहते हैं, वह ईश्वरीय शक्ति होती है, जिसका उद्देश्य सामूहिक कल्याण होता है. जब तक अहंकार रहेगा, तब तक ईश्वरीय शक्ति का आना सम्भव नहीं है. अहंकार खत्म होने से ही ईश्वरीय शक्तियों का आविर्भाव होता है. लोगों को प्रभावित करने के लिए या दूसरों का अहित करने के लिए शक्तियों के चमत्कारपूर्ण प्रदर्शन का दंभ अनुचित है. यदि कोई इन सिद्धियों का, शक्तियों का अनुचित प्रयोग करता है, तो ये शक्तियां उसी व्यक्ति के लिए विनाशकारी सिद्ध होती हैं और उसका साथ छोड़ देती हैं. जिसके पास ईश्वरीय शक्तियां होंगी उसे उनका रंचमात्र भी दंभ नहीं होगा. सद्गुरु का हाथ सुबंद मुठ्ठी की भांति होता है, जिसमें विश्व की आधारभूत अगणित शक्तियां बंधी हुई होती हैं, जो कभी भी मिथ्या चमत्कार प्रदर्शन या अमंगल के लिए नहीं खुलती. यह बात दूसरी है कि आर्तजनों के कल्याण के लिए अनेक बार उनके द्वारा विस्मयकारी घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिन्हें लोग चमत्कार का नाम दे देते हैं, किंतु, सद्गुरु स्वयं उन अलौकिक समझे जाने वाले कृत्यों से बेखबर होते हैं. वे सिद्धियों के पीछे नहीं, सिद्धियां उनके पीछे चलती हैं. प्राणिमात्र का कल्याण ही उनका एकमात्र उद्देश्य होता है.

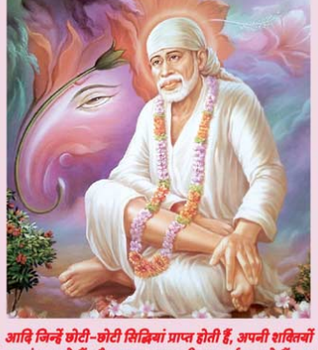

गुरु और चमत्कार

अक्सर लोग अपने गुरु के चमत्कारिक कृत्यों का बढ़ा-चढ़ा कर उल्लेख करते हैं. इस विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

गुरु के चमत्कारों का उल्लेख कर प्रमाणित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए. अपने घर में या समाज में मेरा धर्म, मेरा गुरु-यह प्रमाणित करना नहीं है. अगर वास्तव में धर्म और गुरु में गुण होंगे, शक्तियां होंगी तो वे स्वयं भासित होंगी. आपको गुरु का झूठा प्रचार-प्रसार करने की जरूरत नहीं है. गुरु के बारे में बोलने से कि-मेरे गुरु ऐसा अलौकिक कार्य कर रहे हैं-फोटो से शहद झर रहा है-ऐसा झूठ बोलने से महापाप होता है. केवल गुरु सत्य हैं. वे तीन गुणों (सत्त्व, रज, तम) से अतीत हैं. मैं हर स्थान पर कहता हूं, कभी भी श्री साईंनाथ के बारे में गलत बातें बढ़ा-चढ़ा कर मत बोलना. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

दीपिका कुमारी के तरकश में हैं कई सधे हुए तीर

इस तीरंदाज़ को नहीं कर सकते नज़रअंदाज़

सैयद मोहम्मद अब्बास

भारतीय खेल जगत में इस समय केवल ओलम्पिक की बात हो रही है. चारों तरफ भारत की सम्भावना को लेकर चर्चा है. इस बार रियो के खेल में भारतीय खिलाड़ी अपनी पुख्ता तैयारियों के साथ कूच कर रहे हैं. विश्व के सबसे बड़े खेल मेले में इस बार भारत के कुल 122 खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे. 31वें ओलम्पिक में भारतीय खिलाड़ी 14 खेलों में पदक की दावेदारी पेश करेंगे. भारतीय खिलाड़ियों के समक्ष इस बार ओलम्पिक में बेहतर प्रदर्शन करने का सुनहरा मौका है. इतना ही नहीं सरकार ने भी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण से लेकर हर सुविधाएं प्रदान की हैं. रियो के खेल में इस बार एथलेटिक्स में 38, हॉकी में 32, निशानेबाजी में 12, कुश्ती में आठ, बैडमिंटन में सात, तीरंदाजी, टेबल-टेनिस और टेनिस में चार-चार खिलाड़ी पदक के लिए मैदान में उतरेंगे. कुछ खेलों में पदक जीतने की अपार सम्भावना है लेकिन कुछ ऐसे भी खेल हैं, जिनकी चर्चा बेहद कम होती है. दरअसल खिलाड़ी अपने प्रदर्शन के बल पर उस खेल को विश्व खेल पटल पर चमकाता है. उसका एक जानदार प्रदर्शन उसे रातों-रात स्टार का तमगा भी दिला देता है. पदक की उम्मीद न के बराबर भी होती हो तो उसका स्वर्णिम प्रदर्शन उसके करियर की दशा और दिशा दोनों को बदलकर रख देता है. इसका उदाहरण हमें अतीत में मिलता रहा है. अभी रियो ओलम्पिक खेलों की बात की जाए तो तमाम भारतीय स्टार खिलाड़ियों से केवल पदक की आस की जा रही है. भारत बैडमिंटन और निशानेबाजी में मजबूत दिख रहा है, तीरंदाजी में भी भारत के पदक जीतने के असार बढ़ गए हैं. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि भारतीय टीम की स्टार तीरंदाज और सबसे बड़ी उम्मीद दीपिका कुमारी के तरकश में कई तीर हैं जो पदक पर निशाना लगा सकते हैं. रियो में भारतीय तीरंदाजी टीम में कुल चार खिलाड़ी इस बार अपना जौहर दिखाएंगे. उनमें दीपिका, बोंबायला देवी और लक्ष्मीरानी मांझी महिला टीम और व्यक्तिगत स्पर्धा में अपना दम-खम रखेंगी जबकि अतनु दास पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में अपनी चुनौती पेश करेंगे. इस बार भारत की पुरुष तीरंदाजी टीम रियो ओलम्पिक खेलों में भाग नहीं लेगी क्योंकि वह विश्व कप ओलम्पिक क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में टिकट हासिल करने में सफल नहीं हो सकी. ओलम्पिक में कोटा हासिल करने के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम के कई पुरुष खिलाड़ियों

ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया और वह रियो का टिकट हासिल करने में नाकाम रहे. अतनु दास ने किसी तरह से व्यक्तिगत पुरुष रिकर्व में एकमात्र कोटा हासिल किया. वहीं महिला रिकर्व टीम ने बीते साल डेनमार्क में अच्छा प्रदर्शन करते हुए कट हासिल किया था.

तीरंदाजी में सबसे पहले दीपिका कुमारी का नाम सामने आएगा. दीपिका दरअसल बीते कई सालों से भारतीय उम्मीदों को अकेले अपने मजबूत कंधों पर उठा रही हैं. उनका खेल विश्व स्तरीय रहा है लेकिन अहम मौकों पर उन्हें नाकामी भी मिली है. लंदन ओलम्पिक में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था. इस प्रदर्शन के बावत दीपिका की दलील थी कि उस दिन हवा का रूख सही नहीं था. बहरहाल, वह इस बार ओलम्पिक में शानदार फॉर्म के साथ जा रही हैं. लंदन ओलम्पिक के बाद से दीपिका ने रियो के खेल के लिए खास तैयारी की है. जमशेदपुर के टाटा अकादमी से प्रशिक्षण लेने वाली तीरंदाज दीपिका कुमारी ने मौजूदा सत्र में बेहद खास प्रदर्शन किया है. इस सत्र में वह लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदकों का अम्बार लगाती रही हैं. भारत की स्टार बन चुकी दीपिका कुमारी ने यहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है. वह बेहद गरीब परिवार से आती हैं. ऑटो रिक्शा चालक शिवनाथ महतो की लाड़ली दीपिका शुरू से ही तीरंदाजी में अव्वल थीं लेकिन सुविधाओं के अभाव में उनका प्रदर्शन प्रभावित हो रहा था. साल 2005 में पहली बार उन्हें अर्जुन आर्चरी अकादमी से जुड़ने का मौका मिला. माना जाता है इसी अकादमी के बल पर दीपिका ने तीरंदाजी के हुनर को निखारना शुरू कर दिया था. इसके बाद दीपिका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगीं. साल 2006 में दीपिका के करियर को तब और बल मिल गया जब उन्होंने प्रोफेशनल करियर में कदम रखा. इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रदर्शन को लेकर चर्चा होने लगी. वर्ष 2009 में कैडेट वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप का खिताब जीतकर तीरंदाजी की दुनिया में दीपिका ने खूब नाम कमाया. पलटन हंसदा के बाद दीपिका यह खिताब जीतने वाली देश की दूसरी महिला खिलाड़ी थीं. साल 2009 में वह केवल 15 साल की थीं और 11वीं यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप जीतकर उन्होंने भारत का मान बढ़ाया. दीपिका इसके बाद लगातार कई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में धमाल मचाने लगीं. 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में दीपिका के कमान से निकला तीर स्वर्ण पर जाकर लगा. दीपिका की इस कामयाबी ने भारतीय तीरंदाजी को विश्व स्तर पर बुलंद कर दिया. इसके बाद उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. इसमें प्रमुख है साल 2012 का अर्जुन अवॉर्ड व 2016 में पद्मश्री पुरस्कार. तुर्की में आयोजित 2012 के आर्चरी विश्व कप व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने खिताब जीता था. उन्होंने साल 2016 में भी बेहद शानदार प्रदर्शन किया है. इतना ही नहीं इसी साल दीपिका ने आर्चरी विश्व में महिला वर्ग में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की. उनके इस प्रदर्शन को देखकर रियो ओलम्पिक में पदक की दावेदारी मजबूत दिख रही है. बोंबायला देवी और लक्ष्मीरानी माझी के नाम भी ओलम्पिक टीम में शामिल है, लेकिन इनकी दावेदारी थोड़ी कमजोर मानी जा रही है. इस बीच रियो ओलम्पिक में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम पहले ही रियो पहुंच गई है. ओलम्पिक पांच अगस्त से शुरू हो रहा है. ऐसे में भारतीय तीरंदाजी टीम को इस खेल महाकुंभ में रियो की परिस्थितियों से वाकिफ होने का यह एक सुनहरा मौका है. कुल मिलाकर लंदन ओलम्पिक में भले भारतीय तीरंदाजी टीम ने कुछ खास नहीं किया हो लेकिन इस बार रियो में भारतीय तीरंदाजी टीम के खिलाड़ी खासकर दीपिका कुमारी पर भारतीय खेल प्रेमियों की खास निगाह होगी. ■

दीपा करमाकर में भी है इतिहास बनने का दम-खम

जिमनास्टिक खेल में करियर बनाने में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था. लेकिन इस बाधाओं को पार करते हुए दीपा ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी. उनकी कामयाबी का पता इसी से लगता है कि उन्होंने अपने छोटे से करियर में अब तक 77 पदक जीते हैं. इस सफलता में 67 स्वर्ण पदक शामिल हैं.

दीपा करमाकर, यह नाम भले ही भारतीय खेलों की दुनिया में नया हो, लेकिन यही नाम अब रियो में पदक की आस बन गया है. देश में जिमनास्टिक खेल को लेकर कोई खास उत्साह नहीं देखा जाता है. आज से कुछ साल पूर्व जिमनास्टिक में आशीष कुमार का नाम सुर्खियों में था, लेकिन अब दीपा करमाकर भी जिमनास्टिक की दुनिया में भारत का मान बढ़ा रही हैं. दीपा के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जो धमक देखने को मिली अब वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परवान चढ़ने लगी है. हाल में दीपा ने बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए ओलम्पिक के लिए क्वालीफाई किया. इसके साथ ही वह देश की पहली महिला जिमनास्ट खिलाड़ी हैं जो ओलम्पिक जैसी बड़ी प्रतियोगिता में अपना लोहा मनवाएंगी.

त्रिपुरा की रहने वाली दीपा के सपने बेहद बड़े हैं. केवल छह साल की आयु में जिमनास्टिक का ककहरा सीखने वाली इस खिलाड़ी में प्रतिभा कूट-कूट कर भरी हुई है. उनका हालिया प्रदर्शन इस बात का गवाह है. शुरुआती दौर में दीपा के पैर सपाट थे लेकिन उसने अपनी कड़ी मेहनत से इस बाधा को भी पार कर लिया. दरअसल जिमनास्टिक में अगर आपके पैर सपाट हों तो इस खेल में आगे बढ़ने की बेहद कम सम्भावना रहती है. दीपा के यहां तक पहुंचने में कई लोगों का योगदान रहा है, खासकर उनके कोच विश्वेश्वर नंदी का. उनकी देख-रेख में दीपा ने इस खेल में अपनी अलग पहचान बनाई. बहुत कम लोग जानते हैं कि दीपा इस खेल से जुड़ना नहीं चाहती थीं. उनके पिता दुलाल करमाकर ने इस खेल के

लिए दीपा को प्रेरित किया. उनके पिता दुलाल साई में भारोत्तोलन के कोच थे. पिता हमेशा अपनी लाडली को खेलों की दुनिया से जोड़ना चाहते थे. उनकी उम्मीदों को तब और बल मिला जब दीपा ने इस खेल में खुद को तराशना शुरू कर दिया. उनको इस खेल में करियर बनाने में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था. लेकिन इस बाधाओं को पार करते हुए दीपा ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी. उनकी कामयाबी का पता इसी से लगता है कि उन्होंने अपने छोटे से करियर में अब तक 77 पदक जीते हैं. इस सफलता में 67 स्वर्ण पदक शामिल हैं. भारत में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में दीपा भारतीय जिमनास्टिक टीम की अहम सदस्य थी, लेकिन वहां उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं था. 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए आशीष कुमार ने इतिहास रचते हुए भारत को पहला पदक दिलाया था. आशीष कुमार ने इस प्रदर्शन से भारतीय जिमनास्टिक टीम में एक नई जान फुंक दी थी. दीपा भी आशीष के इस प्रदर्शन से प्रभावित दिखीं. इसके बाद दीपा में भी पदक जीतने का आत्मविश्वास बढ़ गया. दीपा अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय अपने पिता और कोच को देती हैं. उनके इस सहयोग से दीपा आज अंतरराष्ट्रीय फलक पर अपनी चमक बिखेर रही हैं.

दीपा ने ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक जीता और 2015 राष्ट्रीय जिमनास्ट चैम्पियनशिप में जोरदार प्रदर्शन किया. रियो के खेल में कई खेलों में इस बार भारतीय खिलाड़ी देश का झंडा बुलंद करेंगे. देश के खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि उन्हें इस बार लंदन ओलम्पिक से बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा. दीपा करमाकर जैसी उभरती हुई प्रतिभा को अब विश्व खेल के सबसे बड़े मंच पर अपना कौशल दिखाने का अवसर है. ■

feedback@chauthiduniya.com

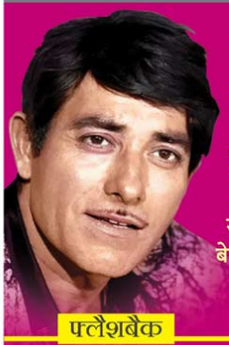

थानेदार से कैसे बन गए हीरो

राजकुमार से जुड़े कुछ रोचक क़िस्से

राजकुमार पर्दे पर ही नहीं, असल ज़िंदगी में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे. उनके बारे में मशहूर था कि डायलॉग पसंद न आने पर वह कैमरे के सामने ही उसे बदल देते थे.

फ्लैशबैक

राजकुमार मुंबई के एक थाने में कार्यरत थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना-जाना लगा रहता था. एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम से आए. वे राजकुमार से बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उनको अपनी फिल्म शाही बाजार में एक्टर के रुप में काम करने की पेशकश की. राजकुमार अपने एक साथी की बात सुनकर पहले ही एक्टर बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और निर्माता का ऑफर मंजूर कर लिया. राजकुमार की गिनती बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर्स में होती है. उनकी एक्टिंग और डायलॉग डिलिवरी जितनी रोचक होती थी, उतनी ही रोचक उनकी ज़िंदगी के किस्से भी हैं. वे पर्दे पर ही नहीं, असल ज़िंदगी में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे. उनके बारे में मशहूर था कि डायलॉग पसंद न आने पर वे कैमरे के सामने ही उसे बदल देते थे. आज हम आपको राजकुमार की ज़िंदगी से जुड़े ऐसे ही कुछ रोचक किस्से बताने जा रहे हैं.

•जब राजकुमार ने बप्पी लाहिड़ी को मंगलसूत्र पहनने के लिए बोला

संगीतकार बप्पी लाहिड़ी की मुलाकात एक पार्टी में राजकुमार से हुई. अपनी आदत के मुताबिक, बप्पी ढेर सारे सोने से लदे हुए थे. राजकुमार ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपने ही अंदाज में कहा, वाह, शानदार! एक से एक गहने पहने हो, सिर्फ मंगलसूत्र की कमी रह गई है, वो भी पहन लेते. यह सुनते ही बप्पी दा का मुंह खुला का खुला ही रह गया.

•राजकुमार ने गोविंदा की शर्ट को बना लिया था रूमाल

राजकुमार और गोविंदा फिल्म जंगबाज की शूटिंग कर रहे थे. उस दौरान गोविंदा ने एक शानदार शर्ट पहने हुई थी. गोविंदा शूटिंग ख़त्म होने के बाद राजकुमार के साथ बैठे हुए थे, तभी राजकुमार ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है. गोविंदा इतने बड़े आर्टिस्ट की यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए. उन्होंने तब राजकुमार से कहा- सर, आपको यह शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए. राजकुमार ने उनसे शर्ट ले ली. दो दिन बाद सेट पर गोविंदा ने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रूमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ है.

•जब राजकुमार ने ली अमिताभ बच्चन की चुटकी

राजकुमार की बेबाक जुबान का शिकार सुपरस्टार बिग बी भी हो चुके हैं. बताया जाता है कि एक पार्टी में जब राजकुमार मेगास्टार अमिताभ बच्चन से मिले तो उन्होंने उनके विदेशी सूट की प्रशंसा कर दी. तब अमिताभ ने खुश होकर उन्हें उस जगह का पता बताना चाहा, जहां से उन्होंने वह सूट खरीदा था. इससे पहले कि बिग बी कुछ बोलते राजकुमार फिर बोल पड़े, दरअसल, मुझे कुछ पर्दे सिलवाने थे. यह बात सुनकर बिग बी मुस्कुराकर रह गए.

•जब जीनत अमान से कहा, दिखती सुंदर हो फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती

यह वह दौर था, जब जीनत अमान फिल्म इंडस्ट्री में फेमस हो गई थीं. बताते हैं इसी दौर में एक पार्टी में जीनत की मुलाकात राजकुमार से हुई. राजकुमार ने जीनत को देखा और कहा-तुम इतनी सुंदर हो, फिल्मों में कोशिश क्यों नहीं करती? अब ये बात सुनकर जीनत का क्या हाल हुआ होगा, आप खुद ही समझ सकते हैं.

•जंजीर न करने की यह बताई वजह

प्रकाश मेहरा फिल्म जंजीर में राजकुमार को लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया. राजकुमार ने इसकी दो वजहें बताईं. पहली, उन्हें प्रकाश मेहरा की सूरत अच्छी नहीं लगी और दूसरी उन्होंने कहा, तुम्हारे पास से बिजनौरी तेल की ऐसी बदबू आ रही है, हम फिल्म तो दूर तुम्हारे साथ एक मिनट और खड़ा रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

सलमान, अक्षय और अजय से ही मैंने मारपीट सीखी है

बॉलीवुड की रियल दबंग सोनाक्षी सिन्हा

अकीरा का निर्देशन ए. आर मुरुगादोस ने किया है और इसकी रिलीज़ की तारीख़ दो सितंबर है. मुरुगादोस के साथ अकीरा सोनाक्षी की दूसरी फिल्म है. इससे पहले उन्होंने उनके साथ हॉलीडे में भी काम किया है.

सोनाक्षी सिन्हा की नई फिल्म *अकीरा* देखने के लिए अक्षय कुमार बेताब हैं. फिल्म का ट्रेलर भी काफी जबरदस्त है जिसमें सोनाक्षी सिन्हा एक्शन करती नज़र आ रही हैं. यह एक एक्शन मूवी है जिसमें सोनाक्षी सिन्हा ने लीड रोल किया है. सोनाक्षी फिल्म में मार्शल आर्ट करती नज़र आएंगी. सोनीक्षी ने अकीरा के लिए मार्शल आर्ट के टिप्स अक्षय कुमार से लिए हैं.

सोनाक्षी ने कहा कि उन्होंने अपने कोस्टार्स से ही एक्शन सीखा है. आगे वह कहती हैं कि सलमान खान दबंग हैं, अक्षय राउडी और अजय देवगन सरदार हैं...मैंने इन्हीं सब से मारपीट सीखी है. सोनाक्षी सिन्हा ने इन सभी सुपरस्टार्स के साथ हिट फिल्में दी हैं. अजय देवगन के साथ *सन्स ऑफ सरदार*, तो सलमान खान के साथ *दबंग*, *दबंग 2*. वहीं अक्षय कुमार के साथ *हॉलीडे*, *राउडी राठौर* जैसी हिट फिल्में की हैं.

सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, पिछले पांच सालों से मैं इन एक्टर्स के साथ काम कर रही हूं. मैंने इन्हीं लोगों से एक्शन के टिप्स लिए हैं. जब स्क्रीन पर ये एक्टर्स एक्शन करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे एक्शन फिल्मों से प्यार है. मैं बहुत खुश हूं कि मुझे एक्शन फिल्म करने का मौका मिला. सोनाक्षी ने बताया कि अक्षय कुमार ने उन्हें मार्शल आर्ट के अहम टिप्स दिए थे ताकि चोट से दूर रहा जाए. अकीरा का निर्देशन ए.आर मुरुगादोस ने किया है और इसकी रिलीज़ की तारीख़ दो सितंबर है. मुरुगादोस के साथ अकीरा सोनाक्षी की दूसरी फिल्म है. इससे पहले उन्होंने उनके साथ *हॉलीडे* में भी काम किया है. उम्मीद है कि अकीरा में हमें सोनाक्षी का दमदार एक्शन देखने को मिलेगा और फिल्म हिट साबित होगी.■

आमिर खान ने की सलमान की तारीफ़

सलमान हैं फिल्म जगत के असली बॉडी बिल्डर

आमिर की फिल्म दंगल 23 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है.

अपनी आगामी फिल्म *दंगल* में अपने किरदार के युवा अवतार से लोगों को हैरान करने वाले बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान ने कहा कि वह सलमान खान की काया के प्रशंसक हैं और उन्हें फिल्म जगत का असली बॉडीबिल्डर मानते हैं. नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित फिल्म *दंगल* दिग्गज पहलवान महावीर सिंह फोगाट के जीवन पर आधारित है. जिन्होंने सभी बाधाओं से लड़कर अपनी दोनों बेटियों-गीता फोगाट और बबीता कुमारी को पेशेवर कुश्ती का प्रशिक्षण दिया. सलमान के साथ अपनी तुलना के बारे में आमिर ने दंगल के सेट पर कहा कि मैं हमेशा से उनका बड़ा प्रशंसक रहा हूं. फिल्म जगत में हमें हमेशा से सलमान की फिटनेस अच्छी लगी है. अगर फिल्म जगत में कोई बॉडी बिल्डिंग में शामिल रहा है, तो वह सलमान हैं. मैं उनकी फिटनेस और काया का प्रशंसक हूं. मुझे नहीं लगता कि मेरा शरीर सलमान जैसा फिट है. वह बॉलीवुड के असली बॉडीबिल्डर हैं.

सोशल साइट्स पर जारी तस्वीर में आमिर काफी यंग नजर आ रहे हैं, फैट से फिट होने के लिए आमिर ने चार से पांच महीने का ब्रेक लिया था. आमिर ने कहा कि पहले जब मैं लुधियाना आया था, तो काफी मोटा था. उस वक्त हमने उम्रदराज फोगाट से संबंधित दृश्यों की शूटिंग की थी. इस अवतार में 85 प्रतिशत फिल्म की शूटिंग की जा चुकी है. अब पहलवान के युवा अवतार की शूटिंग बाकी है. इस फिल्म में साक्षी तंवर को आमिर द्वारा निभाए जा रहे किरदार की पत्नी की भूमिका में देखा जाएगा.

हाल ही में आमिर खान की फिल्म दंगल का पोस्टर रिलीज़ किया गया जिसके बाद इस फिल्म को लेकर कई राज्यों में विरोध किया जा रहा है.■

कैटरीना का बड़ा धमाका

कैटरीना कैफ को अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना पसंद नहीं है, ये तो सबको पता है. इसलिए वो इतना बड़ा धमाका कर देंगी ये किसी ने नहीं सोचा था. दरअसल, कैटरीना कैफ 33 साल की हो गयी हैं. कैटरीना ने अपने जन्मदिन के ख़ास मौके पर अपने फैन्स को एक ख़ास तोहफा दिया है, जिससे उनके प्रशंसक काफी खुश नज़र आ रहे हैं. बॉलीवुड की इस मशहूर अभिनेत्री ने अपने जन्मदिन के मौके पर अलग अंदाज़ में सोशल साइट फेसबुक पर वीडियो के साथ दमदार एंट्री मारी है.

हालांकि पहले उन्हें इस काम से दिक्कत थी, क्योंकि वो रणबीर कपूर को डेट कर रही थीं और रणबीर कपूर को सोशल मीडिया से दिक्कत है. लेकिन अब कैटरीना और रणबीर कपूर के बीच ब्रेकप की ख़बरों के बाद कैटरीना ने एक बार फिर सोचा और यह कदम उठाया.

कैटरीना ने फेसबुक पर अपने समुंद्र के सामने बने अपार्टमेंट का एक वीडियो साझा किया जिस पर लिखा था *लेट्स डू इट*. वैसे भी कैटरीना की बाकी कम्पटीटर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर उनसे काफी आगे हैं. इस ख़ास मौके पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने कैटरीना को बधाई दी. अभिनेता सलमान खान ने भी ट्वीट करके कैटरीना को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनका फेसबुक पर स्वागत किया .■

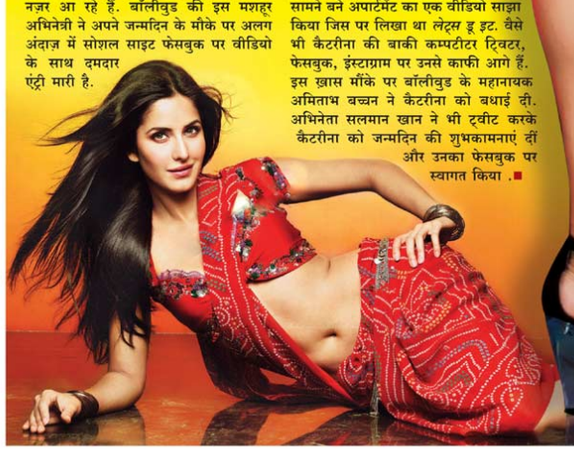

मैं क्लैश को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता

जिसकी फिल्म अच्छी होगी वही चलेगी : अजय देवगन

प्रवीण कुमार

सुल्तान और रईस का क्लैश भले ही न रहा हो, लेकिन इस साल दो और बड़ी फिल्में आपस में भिड़ने वाली हैं. अजय देवगन की फिल्म *शिवाय* और करण जौहर की फिल्म *ऐ दिल है मुश्किल*. दोनों फिल्में दिवाली के मौके पर रिलीज़ होने वाली हैं. बहरहाल, जब अजय देवगन से इस क्लैश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ-साफ कहा कि उन्हें क्लैश से कोई परेशानी नहीं, मैं क्लैश को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता.. जिसकी फिल्म अच्छी होती है वह हिट होती है. सबकुछ आपकी मेहनत पर निर्भर करता है.

अजय ने अपनी फिल्म *सन ऑफ सरदार* का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि आपकी फिल्म दर्शकों को पसंद आती है तो वह बॉक्स ऑफिस पर जरूर सफल होगी. हर किसी को अपनी फिल्म रिलीज़ डेट फिक्स करने का अधिकार है. जो जब चाहे अपनी फिल्म रिलीज़ कर सकता है. लेकिन हां, एक प्रोड्यूसर के तौर पर मुझे यह बात थोड़ी परेशान जरूर करती है. जब मैं बतौर प्रोड्यूसर या बिजनेस के लिहाज से सोचता हूं तो मुझे सामने वाला कभी गलत नहीं लगता. क्योंकि सभी अपनी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर हिट देखना चाहते हैं. उन्होंने कहा, मैंने शिवाय की रिलीज़ काफी डेट पहले ही फाइनल कर ली थी, इसीलिए मैं अपनी फिल्म उसी दिन रिलीज़ करूंगा. इससे पहले भी अजय देवगन बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फिल्मों से टक्कर ले चुके हैं. 1991 में अजय की डेब्यू फिल्म *फूल और कांटे* यश चोपड़ा की फिल्म *लम्हे* से क्लैश थी. अजय देवगन यश चोपड़ा पर भारी पड़े और फूल और कांटे साल की सुपरहिट फिल्म साबित हुई.

आखिरी बार अजय ने अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म *सन ऑफ सरदार* को लेकर शाहरूख खान की *फिल्म जब तक है जान* से भिड़ चुके हैं. यह भी इत्तेफ़ाक ही था कि फिल्म *जब तक है जान* भी यश चोपड़ा द्वारा ही निर्मित थी. ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थीं. ख़ैर यह तो तय हैं कि अजय ने जो ठान लिया फिर वह उससे पीछे नहीं हटते. अब यह तो समय ही बताएगा कि अजय और करण में किसकी फिल्म कामयाबी के झंडे गाड़ती है.■

अजय देवगन की आने वाली फिल्में

शिवाय, सन्स ऑफ सरदार, बादशाहों, गोलमाल-4, क़बीर, सतसंग व सिंघम -3

feedback@chauthiduniya.com